

# Agri Exports

Realising **\$100 Billion** Goal



**एग्री एक्सपोर्ट: 100 अरब डॉलर का लक्ष्य**





MOIL LTD.  
Adding Strength to Steel!



# ADDING STRENGTH TO STEEL

Largest Manganese Ore Producer of the Country



#HarEkKaamDeshKeNaam

**Harvir Singh**  
Editor-in-Chief



## Fast-Tracking India's Agri Exports

**W**ith the services sector growth peaking and not generating jobs like it was during the 1990s, 2000s and 2010s and manufacturing processes becoming increasingly capital-intensive, labour-displacing and automated, there is wide consensus today that it is agriculture which will have an increasing role to play in the Indian economy. The agriculture sector not only has to produce more output, but also generate more value addition and jobs both in and outside the farms.

But all this can happen only when Indian farmers have markets for their produce that will fetch better value and price realisation. They need markets not only within but also outside the country. The focus of this issue of Rural World is on agriculture exports- how to ensure a growing market overseas for the farm produce grown in India. In 2024-25, India's farm exports were valued at about 51 billion dollars. Can we aim at doubling this to 100 billion dollars plus in the next five years, i.e. by 2030?

Progress is being made in this direction, for example, in 2024-25, the export of Basmati and non-Basmati rice has exceeded Rs 1 lakh crore, the export of marine products has reached Rs 60 thousand crore, the export of fruits and vegetables, dairy and processed food products is increasing and the export of organic products has increased by 35 percent. If we continue this momentum and increase investment in infrastructure along with export-focused policy decisions, rules and necessary incentives, the target of \$100 billion agricultural exports is achievable.

While the ambitious target of \$100 billion in agricultural exports is undoubtedly a challenging goal, it is achievable if the government demonstrates genuine commitment to enhancing farmers' incomes through strategic policy decisions and investment.

The global trade landscape, however, is evolving rapidly. The U.S. President Donald Trump's push for reciprocal tariffs disrupted the global trade order and cast uncertainty over the WTO. In response, regional and bilateral FTAs are emerging at a fast pace. While these agreements offer both opportunities and challenges, we must recognise this new reality and build our strategy accordingly.

Agricultural exports begin with production. India has a wide range of export-ready commodities. However, most of our exports are still in the form of raw commodities, making them vulnerable to global price fluctuations. Domestically, price concerns often compel the government to make policy decisions that may hinder exports. Quality remains a major challenge. To thrive in both international and domestic markets, we must prioritise health-centric, high-quality production. Sanitary and phytosanitary standards are critical; unfortunately, they often serve as non-tariff barriers imposed by other countries, restricting our exports.

Currently, about half a dozen products dominate India's agricultural export portfolio. We urgently need to diversify this export basket and explore new markets beyond the traditional ones. Encouragingly, export growth is now being seen in several African and Asian countries. Significant investment is needed in export infrastructure, especially since a large portion of our exports consist of perishable goods. These require specialised packaging, storage, and transportation. Cold storage infrastructure at ports and airports is essential to support these exports.

The cover story in this issue of Rural World provides in-depth coverage of these challenges and opportunities, featuring insightful articles by globally recognised experts in trade and economics. Contributors include Prof. Rakesh Mohan Joshi, Vice Chancellor of the Indian Institute of Foreign Trade; Prof. Biswajit Dhar, Distinguished Professor at the Council for Social Development; Unupom Kaushik, Managing Director of National Cooperative Exports Limited; and Siraj A. Choudhry, Partner at Agvaya LLP. The issue also features an exclusive interview with Abhishek Dev, Chairman of APEDA. In addition, we bring you an exclusive conversation with Dr. Mangi Lal Jat, who took over in April 2025 as the Director General of the ICAR and Secretary of the Department of Agricultural Research and Education (DARE).

We hope that this issue of Rural World in your hands will be seen as our sincere contribution to the advancement of agriculture and allied sectors.

✉ @harvirpanwar



# CONTENTS



Cover Story

**6** The Chequered Path to Achieving \$100 Billion in Agricultural Exports



**10** Interview:  
**Abhishek Dev**  
APEDA Aims  
for \$55 billion  
Exports by 2030

**14** Expert View: Dr Biswajit Dhar  
India's Emergence as an Agricultural  
Export Hub: The Challenges

**18** Insight: Unupom Kausik  
India's Agricultural Exports:  
Performance, Challenges, and Future  
Prospects

**24** Opinion: Siraj A Chaudhry & M  
Ramakrishnan

Reimagining India's Agricultural Exports

**28** Opinion: Prof Rakesh Mohan Joshi  
Making Indian Agriculture  
Globally Competitive



**60** इंटरव्यू:  
**डॉ. मांगी लाल जाट**  
सचिव डेयर, महानिदेशक,  
आईसीएआर

Volume 2, Issue 2  
Quarter (May 2025-July 2025)

**Editor**  
Harvir Singh

**Executive Editor**  
Ajeet Singh

Published and Printed by Harvir Singh  
on behalf of Rural Voice Media Pvt. Ltd.

Printed at Multi Colour Services, Shed No.  
92, DSIDC, Okhla Industrial Area Phase-1,  
New Delhi 110020. Published from 11-A,  
Skylark Apartment, DDA SFS Flats, Site-2,  
Ghazipur, Kalyanpuri, Delhi-110092

Editor: Harvir Singh

Published for the Quarter: May 2025-July 2025  
Released on 20 May 2025

Total Number of pages 68 including covers

Website: ruralworld.co.in

Email: contact@ruralvoice.in

**COVER DESIGN: DesignInc**

**DISCLAIMER:** All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher.



हरवीर सिंह

एडिटर-इन-चीफ

# कृषि निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य



**से**वा क्षेत्र की ग्रोथ चरम पर पहुंच चुकी है और यह 1990 से 2010 तक के दशकों की तरह रोजगार उत्पन्न नहीं कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग पूंजी-प्रधान होती जा रही है और ऑटोमेशन बढ़ने से श्रमिक बाहर हो रहे हैं। ऐसे में इस बात पर व्यापक सहमति बन रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ती जाएगी। कृषि क्षेत्र को न केवल उत्पादन बढ़ाना होगा, बल्कि वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार भी उत्पन्न करने होंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब भारतीय किसानों को अपनी उपज के लिए ऐसे बाजार मिलें जहां उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। इसके लिए किसानों को घरेलू के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों की भी आवश्यकता है। *रुरल वर्ल्ड* का यह अंक कृषि निर्यात पर केंद्रित है। वर्ष 2024-25 में भारत का कृषि निर्यात लगभग 51 अरब डॉलर रहा। क्या हम 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं?

कृषि निर्यात के मोर्चे पर सकारात्मक नतीजे आ भी रहे हैं, मसलन 2024-25 में बासमती और गैर-बासमती चावल का निर्यात एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, मरीन उत्पादों का निर्यात 60 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, फल-सब्जी, डेयरी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है और ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात 35 फीसदी बढ़ा है। अगर हम यह गति जारी रखें और निर्यात पर केंद्रित नीतिगत फैसले, नियम और जरूरी प्रोत्साहन के साथ ढांचागत सुविधाओं पर निवेश बढ़ाएं तो 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

यह बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, इसलिए सरकार को जरूरी नीति और निवेश पर फोकस करना होगा। हालांकि यह राह बहुत आसान नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ से वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर उथल-पुथल मचा रखी। इसके साथ ही मल्टीलेटरल और नियम आधारित इंटरनेशनल ट्रेड की डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं। नतीजा, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) तेजी से अस्तित्व में आ रहे हैं। इनके अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमें नई वास्तविकता को स्वीकार कर रणनीति बनानी होगी।

हमारे ज्यादातर कृषि उत्पाद निर्यात कमोडिटी श्रेणी में हैं और वैश्विक बाजार में कीमतें इनको सीधे प्रभावित करती हैं। घरेलू स्तर पर भी इनकी कीमतें सरकार को निर्यात से संबंधित फैसले लेने को बाध्य करती हैं, जो कई बार निर्यात के खिलाफ जाते हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता बड़ी चुनौती है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के अलावा कई एशियाई देशों में भी गुणवत्ता के मानक काफी सख्त हैं। सेनेटरी और फाइटोसेनेटरी मानक भी हमारे निर्यात में बाधक बनते हैं और कई देश नॉन-टैरिफ बैरियर के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं। हमें किसानों के स्तर पर ही गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज (जीएपी) पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार और निर्यातक दोनों को मिलकर एक्सटेंशन का ढांचा दुरुस्त करना पड़ेगा।

फिलहाल हमारे कृषि निर्यात में ज्यादातर हिस्सा करीब आधा दर्जन उत्पादों का है। इस बास्केट को बड़ा करने के साथ नए निर्यात बाजार भी तलाशने की जरूरत है। निर्यात सुविधाओं पर बड़े निवेश की जरूरत है क्योंकि निर्यात का बड़ा हिस्सा पेरिशेबल (जल्दी खराब होने वाले) उत्पादों का है। इनके लिए पैक हाउस से लेकर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग के साथ खास पैकेजिंग और स्टोरेज व ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। पोर्ट और एयरपोर्ट पर भी विशेष स्टोरेज चाहिए। इन सुविधाओं पर तो सरकार को ही निवेश करना होगा। तमाम उत्पाद ऐसे हैं जिनकी हैंडलिंग के लिए विशिष्ट कौशल वाले श्रमिकों की जरूरत है।

*रुरल वर्ल्ड* के इस अंक में हमने यह बताने की कोशिश की है कि 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात लक्ष्य के लिए किस तरह के नीतिगत फैसलों, उत्पादन और निवेश की जरूरत है। इस विषय पर आईआईएफटी के कुलपति प्रो. राकेश मोहन जोशी, काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के विशिष्ट प्रोफेसर बिश्वजीत धर, एनसीईएल के एमडी अनुपम कौशिक, अगवाया एलएलपी के पार्टनर सिराज ए. चौधरी के लेख हैं। एपीडा चेयरमैन अभिषेक देव का साक्षात्कार भी इस विषय पर केंद्रित है। आईसीएआर महानिदेशक और कृषि शिक्षा विभाग (डेयर) के सेक्रेटरी डॉ. मांगी लाल जाट का साक्षात्कार भी इस अंक का हिस्सा है। उम्मीद है कि *रुरल वर्ल्ड* का यह अंक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए हमारे ईमानदार प्रयास के रूप में देखा जाएगा।

✉ @harvirpanwar



Image: DesignInc

# **The Chequered Path to Achieving \$100 Billion in Agricultural Exports**

**With the right push, mangoes, millets, and more could follow  
rice to become billion-dollar export champions**



# Cover Story

By Ajeet Singh

India's agricultural and allied exports have surpassed the \$50 billion mark. The next target is an ambitious \$100 billion. The spike in shipments can also support broader ambitions like a \$1 trillion agri-economy and enhanced farmer incomes. However, a consistent and predictable policy environment remains the cornerstone for the road to export success.

Currently, four major product categories each contribute \$4 billion or more to exports. By elevating other products into this category, India can move closer to the \$100 billion mark. However, achieving this target demands clarity and consistency in export policies, simplification of rules and procedures, and improved infrastructure from farm to port. Strengthening Good Agricultural Practices (GAP) and ensuring quality enhancement is crucial.

Despite global trade volatility—especially amid U.S. tariff policies under President Trump—India's agri-exports have performed well. In 2024–25, agricultural and allied exports rose by 6.47% to \$51.91 billion. Rice exports led with a record \$12.5 billion, including \$6 billion from basmati rice alone.

Marine products followed with \$7.4 billion in exports. Spices rose by 4.84% to \$4.45 billion. Buffalo meat exports saw an 8.57% increase, surpassing \$4 billion. Processed foods and fresh fruits grew by about 2%, reaching \$1.68 billion and \$1.17 billion respectively. Processed fruits and juices rose 6% to over \$1 billion. Tobacco exports jumped 40% to nearly \$1.5 billion, while organic products and dairy exports grew by 35% and 54% respectively.

Under the Ministry of Commerce and Industry, APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export

Development Authority) supports this effort. In 2024–25, exports under APEDA's ambit rose 11% to \$27.9 billion, signaling a promising path to the \$100 billion goal by 2030, despite challenges.

According to APEDA Chairman Abhishek Dev, efforts are underway to improve infrastructure, expand export facilities, and connect farmers to global markets. Varanasi, for instance, emerged as a success story—exporting thousands of tons of fruits and vegetables within four years, including black rice from Chandauli and Langra mangoes. Varanasi was developed as an agri-export hub with enhanced airport facilities. Amritsar airport is also being upgraded for export operations.

Because perishable items often fail to reach distant domestic or global markets, the 2024–25 Union Budget announced expansion of air cargo warehousing. Streamlined cargo screening and customs protocols can further ease exports.

## Rice Export: A Success story

Agri-export growth can significantly

**Boosting exports requires facilities like pack houses, cold chains, auction centers, irradiation units, and cargo terminals. APEDA supports these through various schemes. Investing in core agri-infrastructure—power, irrigation, transport—can increase productivity and market reach.**

raise farmers' incomes, provided products meet international quality and safety standards. Basmati rice is a standout success, with rice exports growing 23.48% in 2024–25 to 202 lakh tonnes worth \$12.47 billion (over ₹1 lakh crore). Rice alone contributes 25% to total agri-exports, with basmati accounting for over ₹50,000 crore. This illustrates the potential for other commodities to boost export revenue.

## Quality and Food Safety Standards

Export success hinges on adhering to global quality and food safety norms, from seed selection to post-harvest processing and packaging. Standards vary by region—USDA for the U.S., EU standards for Europe—and include sanitary and phytosanitary regulations, pesticide residue levels, and traceability.

Recent rejections of Indian mango shipments to the U.S.—due to documentation errors at an irradiation facility—highlight how lapses can lead to costly export losses. India produces 43% of the world's mangoes but exports less than 1% due to such hurdles. In 2024, India exported 32,000 tons of mangoes and 60,000 tons of mango pulp, and efforts are underway to promote exports from mango-producing states like Uttar Pradesh.

To ensure compliance, APEDA is collaborating with IARI-Pusa, FSSAI, exporters, and state governments. Awareness among exporters is essential—some states have already banned harmful pesticides used in basmati production.

## Value-Added Products and Multi-Ministry Coordination

Enhancing export value requires a focus on value addition. Subrata Gupta, Secretary of the Ministry of

Food Processing Industries (MoFPI), emphasizes the need for robust infrastructure, hygiene, and sanitary standards aligned with international norms. Coordination among central/state governments and industry players is vital.

FIEO Director General Dr. Ajay Sahai notes that 50% of agri-exports are raw products, while processed foods account for about 30%. Boosting value-added and processed food exports is key to reaching the \$100 billion target.

Multiple ministries play roles in agricultural exports—agriculture production falls under the Agriculture Ministry; exports under the Commerce Ministry; procurement and storage under the Ministry of Consumer Affairs; food processing under MoFPI; and dairy and meat under the Ministry of Animal Husbandry. Customs falls under the Finance Ministry.

### Promoting GI-Tagged Products

Geographical Indication (GI) tags help position Indian products globally. India now has a separate HS code for GI-tagged rice varieties like Kalanamak, Gobindobhog, Navara, Pokkali, and others. This facilitates traceability and enables exports even when generic rice varieties are restricted.

APEDA has started exports of GI-tagged Dalle Khursani chilies from Sikkim and jaggery from Muzaffarnagar, UP. These efforts—often via Farmer Producer Organizations (FPOs)—help ensure direct benefits to farmers. Western UP's jaggery and basmati rice are already being exported to Lebanon and Oman with APEDA's support.

### Building Infrastructure and Export Facilities

Boosting exports requires facilities like pack houses, cold chains, auction centers, irradiation units, and cargo terminals. APEDA supports these through various schemes. Investing in core agri-infrastructure—power, irrigation, transport—can increase

productivity and market reach. Reducing post-harvest losses is equally crucial.

According to Dr. N.C. Saha, former director of the Indian Institute of Packaging, advanced packaging technologies can extend the shelf life of perishables like litchi from 15 to 60 days, enhancing export feasibility. Government incentives for adopting such technologies are recommended.

### Balancing Farmer Interests and Export Policy

The government has to strike a balance between curbing inflation, ensuring national food security, and promoting exports. In this process, farmers often miss out on the benefits of export markets. In 2023, restrictions on the export of onions and non-basmati rice adversely affected the country's agricultural exports and farmers. A similar situation is being witnessed in the case of wheat.

For the past two years, the Ministry of Agriculture has been claiming record wheat production in the country. The ministry estimates that wheat production in 2024–25 will reach a record 115.4 million tonnes. Government wheat procurement this year is around 11% higher than last year. Yet, the export ban on wheat remains in place.

It is worth noting that the

**Export success hinges on adhering to global quality and food safety norms, from seed selection to post-harvest processing and packaging. Standards vary by region—USDA for the U.S., EU standards for Europe—and include sanitary and phytosanitary regulations, pesticide residue levels, and traceability.**



Government of India imposed a wheat export ban in May 2022 due to a decline in production. This step was taken to ensure domestic food security and control inflation. A similar move was made with onions in 2023, when the government banned their export—a decision that became a major issue in Maharashtra ahead of the 2024 Lok Sabha elections.

These circumstances also raise questions about the accuracy of agricultural production data. Despite a bumper harvest of 113.2 million tonnes of wheat last year, government procurement was only 26.6 million





tonnes, and wheat prices in the domestic market did not fall even after the export ban.

In reality, increasing agricultural production is essential to boost agricultural exports. Moreover, the policy of imposing export restrictions for various reasons, thereby denying farmers better prices, also needs reconsideration. Agricultural exports play a crucial role in ensuring better returns for farmers. Therefore, a balance must be maintained between food security and agricultural trade. This harmony can be achieved by enhancing production capacity,

reducing post-harvest losses, improving supply chain efficiency, and adopting sustainable farming practices.

### Need to Enhance Productivity and Efficiency

In terms of agricultural production, India still lags far behind not just developed countries but also China. As a result, the lack of productivity continues to challenge the competitiveness of Indian products. However, India has made significant progress in fruit exports, especially grapes, bananas, and pomegranates.

This momentum must extend to other crops as well—an essential step toward achieving the ambitious \$100 billion agricultural export target.

The government initiated steps toward this target with the new export policy introduced in 2018, but the goal remains distant. However, the \$50 billion mark has now become a sustainable benchmark. The next step is to double it, which is essential not only for better incomes for farmers but also to make farming a more attractive and viable enterprise. Export growth will play a vital role in this endeavor. 





# APEDA Aims for \$55 billion Exports by 2030: **Abhishek Dev**

*India's agricultural exports are entering an exciting new phase, driven by robust global demand, a diversified product portfolio, and an ambitious government target of reaching \$100 billion in agri-exports in the coming years. At the heart of this transformative agenda is the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), which plays a pivotal role in promoting, facilitating, and expanding exports of scheduled agri and food products.*

*In an exclusive interaction with Harvir Singh, Editor-in-Chief and Ajeet Singh, Executive Editor, Rural World, Abhishek Dev Chairman of*





**Abhishek Dev**  
Chairman, APEDA

Photo: Rural World

*APEDA shares key insights into the strategies being rolled out to scale up India's agri-export footprint, the sectors that will fuel the next wave of growth, and the institutional efforts to ensure sustainability, quality, and market access.*

**Q India has set an ambitious target of achieving \$100 billion in agricultural exports. What are the key strategies APEDA is implementing to reach this milestone?**

As part of the broader national objective to achieve \$100 billion in agricultural exports, APEDA has set

**As India sets its sights on reaching \$100 billion in agricultural exports by 2030, APEDA is spearheading a focused strategy that blends product-specific promotion, market diversification, and value addition.**

a target of exporting more than \$55 billion worth of its Scheduled products by 2030. To reach this milestone, the authority is pursuing several strategic initiatives, including targeted export promotion of key and high-potential products, as well as intensive efforts toward market diversification and deeper penetration into under-tapped but high-value markets such as the European Union, USA, UK, Oceania, Japan, and South Korea.

To support these efforts, APEDA has onboarded ICRIER as a knowledge partner to carry out end-to-end value chain analysis for 20 key products. The analysis will help develop region- and country-specific export action plans. Simultaneously, APEDA is working on enhancing the branding and packaging of Indian agri-products to increase their global appeal and export value. Development of sea protocols for perishable products is underway to enable cost-effective and sustainable shipping to distant markets.

Additionally, APEDA has established a Market Intelligence Cell in collaboration with CRISIL, which provides stakeholders with regular insights into key global and domestic developments impacting the agriculture sector.

**Q Which specific sectors or products**

**do you see driving the next phase of export growth? What are the untapped opportunities?**

APEDA has identified a basket of high-potential product categories that are poised to drive the next phase of India's agricultural export growth. Key focus areas include both Basmati and non-Basmati rice, as well as fresh fruits like banana, mango, pomegranate, grapes, and pineapple, all of which enjoy strong international demand.

In vegetables, products like potato, green chili, ginger, and okra are considered priority commodities. The international appetite for processed and value-added foods—such as groundnuts, foxnuts (makhana), sauces, juices, papad, pasta, biscuits, confectionery, and alcoholic beverages—is another key growth driver.

Animal products, including natural honey, dairy items (ghee, paneer), table eggs, and bovine meat, also show strong export promise. The cumulative export potential of these focus products is estimated to exceed \$40 billion by 2030.

**Q What are the biggest challenges in reaching the \$100 billion export target?**

Major challenges include infrastructure gaps such as an inadequate cold chain network and insufficient on-farm processing capabilities, which lead to wastage and reduced export quality. Additionally, the ongoing Red Sea crisis and geopolitical conflicts in the Middle East have escalated logistics costs, especially for air and ocean freight.

Internal transport costs are also disproportionately high in regions like the North Eastern Region and landlocked states. Another challenge is the knowledge gap among farmers regarding Good Agricultural Practices (GAP), which results in the presence of pesticide residues and affects produce quality.

**Q How was India's performance in agricultural exports in 2024–25? What were the highlights?**

India recorded a stellar performance in agricultural exports in 2024–25.

## Cover Story Interview

Exports of APEDA's Scheduled products hit an all-time high of \$27.9 billion. Leading the surge were non-Basmati rice (\$6.5 billion), Basmati rice (\$5.9 billion), and buffalo meat (\$4.0 billion). Other significant contributions came from fresh fruits and vegetables (\$2.06 billion), as well as cereal preparations, pulses, dairy products, processed vegetables, fruit juices, and cocoa products.

Organic product exports rose by 35%, with notable growth across cereals, tea, essential oils, processed goods, and ayurvedic and medicinal products.

**Q How is APEDA working to diversify India's agricultural export markets beyond traditional destinations?**

India's agri-exports have traditionally focused on the Middle East, Africa, and parts of the Asia-Pacific. However, there is significant untapped potential in key markets such as Europe, the UK, Japan, Korea, and China.

To capture these opportunities, APEDA is conducting detailed product-market studies and identifying high-potential commodities for each target region. It also works closely with Indian embassies to gain market feedback and develop entry strategies in collaboration with exporters.

In addition, APEDA promotes Indian products through participation in major international trade events like Gulfood (Dubai), BIOFACH (Germany), SIAL (Paris), ANUGA (Germany), Natural Product Expo West (USA), World Food India, INDUS Food, and AAHAR. It also organizes buyer-seller meets and trade delegations to connect Indian exporters with global buyers, including in the North Eastern Region.

**Q In some markets, quality remains a concern. How is APEDA helping farmers and exporters meet global standards?**

APEDA promotes the adoption of Good Agricultural Practices (GAP) and supports certifications such as GLOBALGAP to ensure compliance with sanitary and phytosanitary (SPS)

standards required by importing countries.

The authority also assists food processors and exporters in obtaining quality and food safety certifications to enhance global acceptance. It has implemented traceability systems for key products like grapes, peanuts, and organic goods—an initiative well-received by importing nations.

To support quality assurance, APEDA has recognized 117 labs across India accredited under ISO 17025 by NABL, enabling reliable testing and certification of export-bound products.

**Q Is there a focus on promoting organic and GI-tagged products in global markets?**

Yes. APEDA prioritizes the promotion of organic and Geographical Indication (GI)-tagged products. The National Programme for Organic Production (NPOP) has been revised following stakeholder input, and efforts are ongoing to establish



**APEDA is tackling these challenges through initiatives like developing sea protocols for perishables, expanding cold chain infrastructure, and upskilling farmers in good agricultural practices.**

equivalency agreements with Australia, the USA, Japan, and New Zealand.

A dedicated portal for organic export promotion has been launched, and APEDA continues to increase participation in international trade shows such as BioFach (Germany), Natural Product Expo West (USA), and the Organic and Natural Product Expo (Dubai). Under the "Brand India" campaign, APEDA has also partnered with IBEF to enhance the global identity of Indian organic products.

As of now, 242 GI products are registered, reflecting India's rich agricultural and cultural heritage. Key GI exports include Basmati rice, several mango varieties, pineapples, onions, Sangli grapes, and North Eastern specialties like Joha rice, Black rice (Chak-Hao), and Mithila makhana. These products are exported to countries including the USA, UK, UAE, Iran, Iraq, Belgium, Germany, and Switzerland.

**Q In the context of global trade tensions and US tariffs, what are the opportunities and challenges for Indian agri-exports?**

Despite global trade tensions, Indian agricultural exports remain resilient due to their unique taste profiles and growing global preference for diverse and healthy foods. APEDA is confident that Indian agri-products will continue to perform well, though exporters must remain agile in responding to new trade dynamics.

**Q What policy interventions or incentives are needed to accelerate export growth?**

*Key areas of focus include:*

**Product-centric strategies:** Export promotion across the full value chain for over 20 high-priority products such as bananas, rice, meat, and organic items. **Branding:** Market-specific promotional campaigns for Basmati rice, fruits, and organic products.

**Logistics:** Implementation of sea protocols for perishables to reduce cost and improve efficiency.

**Quality assurance:** Adoption of



## Comparative Statement of Exports of Agricultural and Processed Food (Principal Commodity Analysis)

APEDA Scheduled Products	Value (US\$ Mill)			APEDA Scheduled Products	Value (US\$ Mill)		
	2023-24	2024-25	Growth Rate (%)		2023-24	2024-25	Growth Rate (%)
Non-Basmati Rice	4573	6528	43%	Cashew	339	338	0%
Basmati Rice	5843	5944	2%	Cocoa Products	184	296	61%
Buffalo Meat	3743	4061	8%	Poultry Products	185	169	-9%
Misc Processed Items	1654	1680	2%	Fruits / Vegetable Seeds	133	158	19%
Fresh Vegetables	891	894	0%	Floriculture	87	89	2%
Processed Fruits & Juices	972	1029	6%	Sheep/Goat Meat	78	85	9%
Cereal Preparations	842	934	11%	Animal Casings	48	60	24%
Fresh Fruits	1147	1171	2%	Cashew Nut Shell Liquid	9	7	-23%
Groundnut	862	795	-8%	Processed Meat	3	1	-52%
Other Cereals	518	271	-48%	Other Meat	1	0	-74%
Pulses	645	778	21%	Sub-total	24809	27707	12%
Processed Vegetables	652	777	19%	Wheat	57	2	-96%
Guargum	542	569	5%	Milled Products	173	192	11%
Dairy Products	469	721	54%	Sub-total	230	194	-16%
Alcoholic Beverages	389	353	-9%	<b>Grand Total</b>	<b>25039</b>	<b>27901</b>	<b>11%</b>

Source: DGCIS, Principal Commodity

Note 1: Major items of Miscellaneous Preparations includes Maize (Corn) Starch, Flakes, Granules & Pellets Of Potatoes, Protein Concentrates & Textured Protein Substances, Soft Drink Concentrates, Mixed, Condiments And Mixed Seasoning, Pan Masala, Areated Waters Containing Sugar

Note 2: Major items of Cereal Preparations includes Sweet Biscuits, Papad, Bread, Pastry, Rice Papad And Similar Products, Biscuits Not Elsewhere Specified and Prepared Foods Obtained By The Swelling Or Roasting Of Cereals Or Cereal Products.

GLOBAL GAP certification and product traceability systems.

**Infrastructure:** Strengthening cold chains and supply networks through coordination with state and central agencies.

**Market access:** Addressing SPS barriers and fast-tracking approvals in key importing nations.

### Q How is APEDA aligning with India's FTAs to boost exports?

APEDA collaborates closely with trade negotiators to align product promotion strategies with India's FTAs. Post-agreement, APEDA conducts training, outreach, and buyer-seller interactions to help exporters maximize opportunities emerging from tariff access and

regulatory harmonization.

### Q How is APEDA addressing sustainability issues like pesticide use, emissions, and biodiversity loss?

Sustainability is at the core of APEDA's export promotion strategy. The agency encourages environmentally friendly farming practices, supports GAP certification, and promotes traceability to manage pesticide usage. These initiatives help India meet global sustainability benchmarks, enhancing the competitiveness of its exports.

### Q How is APEDA supporting agri-startups, FPOs, and cooperatives through technology and innovation?

APEDA is actively empowering agri-startups, FPOs, and cooperatives through:


**Cluster-Based Promotion:** Targeted export plans for high-potential agro-food clusters.

**Tech Integration:** Support for traceability, smart packaging, and cold chains.

**Collaborations:** MoUs with NABARD, SFAC, and NAFED to improve market access and capacity.

**Capacity Building:** Over 879 training programs held in 2024–25, covering more than 78,000 stakeholders.

**Startup Support:** Screening 500 startups, with 25 receiving intensive export and investment-readiness support.

**Financial Assistance Scheme (FAS):** Support for export infrastructure, certification, traceability, and global market promotion. 

# India's Emergence as an Agricultural Export Hub: The Challenges

A policy pivot toward global markets has brought modest gains—but core production and compliance issues remain unresolved



**Dr Biswajit Dhar**

Professor, Jawaharlal  
Nehru University (Retd),  
Distinguished Professor,  
Council for Social  
Development

In December 2018, the government announced an ambitious Agriculture Export Policy, the first time it had done so. The significance of an agricultural export policy lay in the fact that it marked a departure from the earlier emphasis of India's agriculture, namely, to ensure domestic food security. This shift in the focus of agricultural policy was in the offing for quite a while since the 'Green Revolution' strategy had long ensured that India was a food self-sufficient country and that there was no possibility of sliding back to import dependence.

The Agriculture Export Policy had several overarching objectives. First, it was framed with a focus on agriculture export oriented production that was to be synchronised within policies and programmes adopted by the Government of India. Secondly, the policy emphasised the need to have a "farmer centric approach" focused on improved income generation through greater value addition, which would help to minimise losses across the value chain. Thirdly, the policy underlined the need for a farmer oriented strategy that could achieve the twin objectives of food

security and a prominent agriculture exporter of the world. And finally, the intention of policy was to provide a boost to the food processing industry, which would increase India's share of value added processed products in its agriculture export basket enabling it to emerge as a major player at the global level.

Besides its overarching objectives, the Agriculture Export Policy had a number of specific targets, which was an interesting feature of this policy. One, to double India's agriculture exports to \$60 billion by 2022 by doubling India's share in world agricultural exports through integrating with global value chain at the earliest, and to enable farmers to get benefit of export opportunities in overseas market. In fact, promotion of agricultural exports was seen as sine qua non for meeting the objective that the government had set in 2016 for doubling the farmer's income by 2022. Two, diversifying the export basket, destinations and boost high value and value added agricultural exports including focus on perishables. Three, to provide an institutional mechanism for pursuing market access, tackling barriers and to deal with sanitary and phytosanitary issues, or human, animal and plant life and health standards that are critical to expanding India's footprint in the global markets.

The contentious farm reforms introduced in 2020 was yet another move for transforming India into an agricultural export hub. The Essential Commodities Act, 2020, deregulated the markets for agricultural commodities and was expected to provide a fillip to exports. The Act was amended to deregulate the market and to, therefore, give freedom to produce, hold, move, distribute and supply to harness economies of scale and attract private sector as well as foreign direct investment into agriculture sector. The government

Exports of Agriculture and Allied Products			
Years	Agri and allied products (US\$ billions)	Total Exports (US\$ billions)	Share of agriculture and allied products in total exports (%)
2017-18	37.0	303.5	12.2
2018-19	37.1	330.1	11.2
2020-21	40.0	291.8	13.7
2021-22	47.4	422.0	11.2
2023-24 (Apr-Feb)	42.9	395.4	10.8
2024-25 (Apr-Feb)	46.0	395.4	11.6

Source: Department of Commerce



argued that India has become surplus in most agricultural commodities, but farmers have been unable to get better prices due to lack of investment in cold storage, warehouses, processing, and export as “the entrepreneurial spirit” was dampened due to restrictions on stock holding imposed by the Essential Commodities Act.

In 2022, the Directorate General of Foreign Trade adopted the Districts as Export Hubs (DEH) initiative to identify agricultural and other products having export potential in 733 districts. This initiative has three specific objectives in regard to promoting exports: (i) to diversify India’s export destinations and to boost high-value and value-added agricultural exports including focusing on perishables, (ii) to promote exports of novel, indigenous, organic, ethnic, traditional, and non-traditional agricultural products and (iii) to enable farmers to benefit from export opportunities. The Foreign Trade Policy of 2023 provided legitimacy to the DEH initiative through establishment of institutional mechanisms that would enable identified districts of the country to become export hubs. The District Export Promotion Committees were tasked with the responsibility of identifying products and services with export potential in 765 districts (in 2025), addressing bottlenecks for exporting these products/services, supporting local exporters/manufacturers to scale and find potential buyers outside India aimed at promoting exports.

With considerable efforts being put on promoting agricultural exports have been taken since 2018, it would be useful to assess the performance since the Agriculture Export Policy was adopted. It may be recalled that when it was unveiled, one of the overarching objectives of this policy was to double exports of agricultural products by 2022.

The challenges that the country faces in establishing itself as a major agriculture export hub can clearly be seen from the developments since the agricultural export policy was adopted in 2018. Available data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics of the Department of Commerce shows that exports of agriculture and allied products increased from about \$37 billion in 2018-19, to about \$46 billion in 2024-25 (April to February), or about 24%. Increase in exports of agricultural commodities since 2018 was not only far less



than the target of “doubling by 2022” set in the Agricultural Export Policy, but it was also less than India’s overall exports, which grew by 30%. As a share of India’s total exports, agricultural products’ exports remained between 11-12%, except for 2020-21, the year in which exports of all other products other than food products had suffered sharp decline.

Increase in exports of non-basmati rice has been remarkable since the turn of the previous decade, when the value of non-basmati rice was just \$50 million, but a decade and a half later, exports had increased over 10-fold to \$6 billion. In 2020-21, exports of this variety of rice exceeded those of basmati, the most popular agricultural export, for the first time. Increased exports of this variety of rice not only strengthened India’s control over the global rice export market, but to also improve the country’s trade relations with several Sub-Saharan African countries, which accounted for a substantial share of this variety of rice exports. In 2024-25, over 51% of the total exports went to this region accounted, Benin, Cote d’Ivoire, and Senegal were the three most prominent markets in 2024-25. Importantly, steep increase in exports of non-basmati rice during the covid-pandemic helped most of the



**While non-basmati rice exports to Africa have soared, India's wider agricultural export dreams remain constrained. From faltering wheat shipments to persistent regulatory bottlenecks, this analysis explores why most Indian farm exports still struggle to break through globally.**



**India's 2018 Agriculture Export Policy promised a bold transformation—from food self-sufficiency to global agri-export leadership. Six years later, export growth has fallen short, with food safety barriers holding back from its ambitious targets.**

importing countries overcome the strains they had experienced in the aftermath of the covid-pandemic.

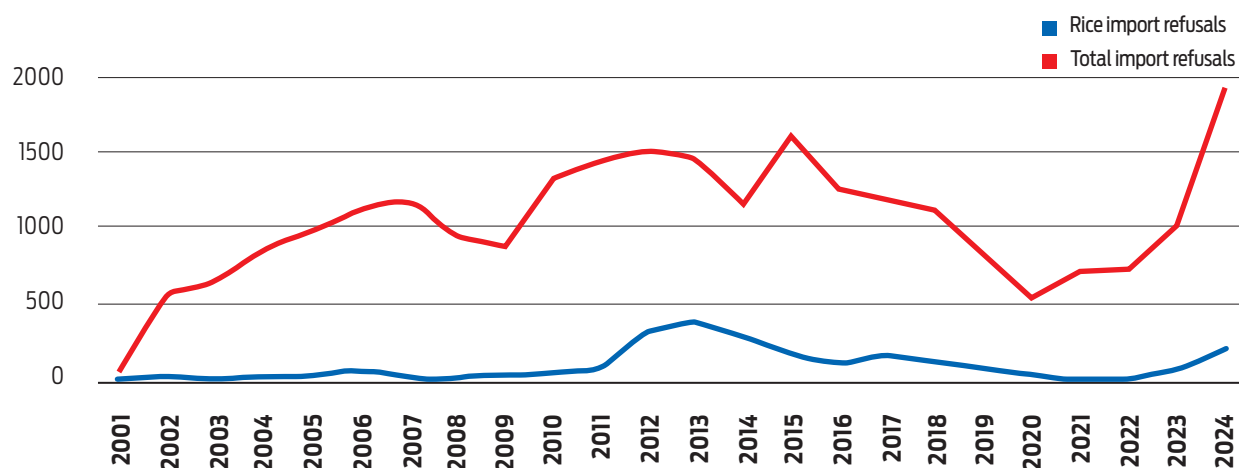
Six largest commodity groups in terms of exports in 2024-25, namely rice, marine products, spices buffalo meat, sugar, and oilmeal accounted for about 63% of total exports of agriculture and allied products. The share of these products in the total exports of agriculture and allied products was higher at about two-thirds in 2018, and after peaking in 2020-21, this figure had declined. Rice exports grew the fastest (48%) during this period, on the back of an almost doubling of non-basmati rice exports, despite the fact that the government had imposed ban on rice exports between July 2023 and September 2024 to stabilise the domestic market. However, the government allowed exports to countries to meet their food security needs and based on the request of their Government. On the other hand, exports of marine products declined between 2017-18 and 2024-25, while buffalo meat exports rose marginally by 3%. Sugar exports increased by 37%, despite suffering from the production cycles, and oil meal exports declined by nearly 19% since 2017-18.

Bullish expectations on agriculture exports had built-up since the end of the previous decade, but this had all but disappeared all too quickly. The expectations suffered a sharp reversal of

in 2022-23, as wheat stocks showed signs of depletion. A major slide-back in wheat production resulted in its exports falling to \$54 million in 2023-24, the lowest level since 2011-12. Heat stress adversely affected wheat production from 2023, resulting in a sharp drop in exports to mere \$1.6 million during 2024-25. Thus within 3 years, wheat exports had declined from a high of \$2.2 billion to \$1.5 million, which was a reminder that fluctuations in the production of the major commodities could pose significant uncertainties. Most crops, with the solitary exception of rice, were unable to overcome the typical production cycles over the past few years that posed severe supply constraints. This meant that except for exports of basmati rice, a commodity, India could not establish itself as a major exporter of agricultural commodities. With the sector mired in structural crises, and farmers agitating over the fact that agriculture had ceased to be a profitable business, maintaining the levels production of most crops was clearly a tall ask.

One positive development is the steady increase in the exports of processed agricultural products, including of fruits and vegetables. Between 2017-18 and 2024-25, exports of processed products had nearly doubled. India needs to focus more on these products to improve value addition and employment opportunities in the country, and, more importantly, the food processing sector is in a better position

**Graph 1: USFDA's Import Alerts on Indian Food Products Exported to the US (2001-24)**



Source: US FDA: Import Refusals, accessed from: <https://datadashboard.fda.gov/oii/cd/imprefusals.htm>.



to realise the objectives of the Agricultural Export Policy.

### Food Safety Standards

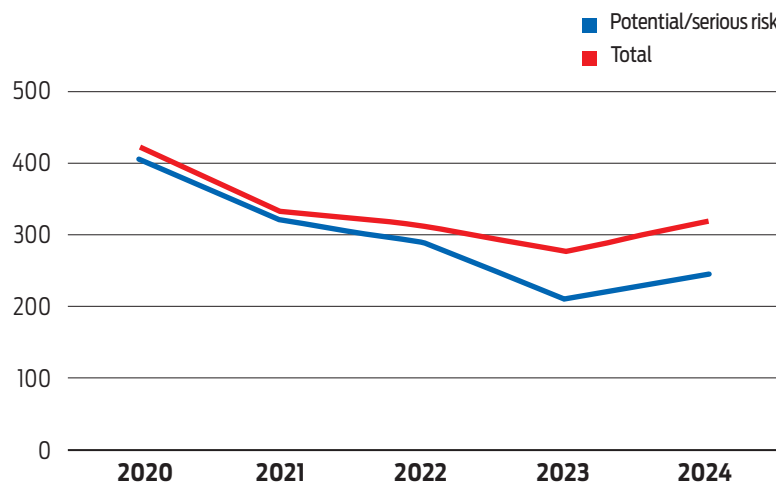
Uncertainties in the levels of production were not the only factor adversely affecting India's exports of agricultural products. A more important factor is the ability to conform to the sanitary and phytosanitary standards that are consistently become more stringent, not only in the advanced countries but also in most advanced developing countries.

The European Union (EU) member states and the United States have comprehensive mechanisms of issuing alerts regarding actual or potential risk arising from import of food products. The EU members have in place a "Rapid Alert System for Food and Feed" (RASFF) for facilitating rapid exchange of information on levels of risks detected in food or feed. RASFF plays a key role for protecting public health through quick responses regarding food safety issues, including concerns arising from imports. In the US, the Federal Drug Administration (FDA) has the authority to ensure that products imported into the US comply with the Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C Act) and other related acts. Imports failing to comply with the FD&C Act are included in "import refusals", FDA's final decision that a detained shipment is in violation of its laws and regulations.

Analysis of the data obtained from EU's RASFF from 2020 and FDA's import alerts since 2001 gives an indication on the extent to which Indian exporters of food products are complying with the sanitary and phytosanitary standards that these two jurisdictions have in place. The FDA's import alerts are available from 2001, enabling a longer term view on how India's exports of food products have met the test of American standards (Graph 1).

The steep increase in import refusals faced by Indian exports of food to the US since covid-pandemic is surely an area of concern. Even in 2025, the import refusals' trend has remained unchanged with 766 cases of import refusals being recorded until the end of April. However, import refusals in case of Indian rice imports into the US shows a positive trend overall, though the slightly upward trend since 2021 must not be allowed to increase any further.

**Graph 2: EU RASFF's identification of levels of risks detected in food or feed**



Source: EU: Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), accessed from: [https://food.ec.europa.eu/food-safety/rasff\\_en](https://food.ec.europa.eu/food-safety/rasff_en).

EU's RASFF flagged 1661 consignments from India containing food or feed as having different levels of risk during 2020 and 2024. However, 12% of these were marked as having "no risk". The trend of those posing potential/serious risk is captured in Graph 2.

Graph 2 which captures the trend of import consignments of food and feed having high levels of risk since 2020 shows an encouraging trend overall, though the moderate increase in 2024 should be taken note of. The trend during the first 4 months of the current year looks encouraging as 72 cases were identified, of which 12 were not serious. However, the trends of complying to sanitary and phytosanitary standards in the US and the EU show that the government need to pay considerable attention towards developing new institutions and strengthening the existing ones, through which producers and exporters of agricultural products can prepare themselves for overcoming the exacting standards prevailing in global markets. Without this preparedness, India's ambition of becoming an agricultural export hub would remain largely unrealised.

At the same time, government must step up its investment in the agricultural sector to provide a sustained boost to production of major commodities which is critical for the country to emerge as a reliable agricultural export hub. **Rw**



**India's push to become an agricultural export powerhouse has led to sweeping policy changes and institutional reforms. Yet, uneven crop output and mounting global food safety rejections expose the gap between ambition and reality.**

# India's Agricultural Exports: Performance, Challenges, and Future Prospects

While challenges such as infrastructure deficits, fragmented landholdings and policy inconsistencies persist, the sector's potential remains enormous



**Unupom Kausik**

Managing Director,  
National Co-operative  
Exports Limited

India stands as a global agricultural powerhouse, ranking second in world agricultural production yet holding only 2.4% of global agricultural exports. With agricultural exports valued at USD 48.9 billion in FY 2023-24, down from USD 53.2 billion in FY 2022-23, India faces both opportunities and challenges in expanding its agricultural footprint in international markets. This article examines the current state of India's agricultural exports, analyses key performance indicators, and explores strategies for sustainable growth.

India's agricultural exports have experienced fluctuations in recent years, reflecting both global market dynamics and domestic policy decisions. Agricultural exports touched USD 48.9 billion in 2023-24, registering a decline from USD 53.2 billion in 2022-23. This 8.2% decline was primarily attributed to export restrictions imposed on key commodities including rice, wheat, and sugar to ensure domestic food security.

## Year-on-Year Performance Analysis:

- FY 2023-24: USD 48.9 billion (8.2%

decline from previous year).

- FY 2022-23: USD 53.2 billion.
- FY 2021-22: USD 50.24 billion (21.8% growth).
- FY 2020-21: USD 41.25 billion.

Key Performance Highlights for FY25 (April-December): Total Agricultural Exports: Rs. 3,18,509 Crore (USD 36.95 billion).

Strong performance in specific commodities showing market recovery. Export Diversification: Continued focus on high-value products and new markets.

India's agriculture sector primarily exports: Agricultural & allied products, Marine products (leading category), Plantation products (tea, coffee, spices), and Textile & allied products.

The agricultural export sector has shown a 5-year average growth trend, with the recent decline attributed primarily to policy interventions aimed at ensuring domestic food security. However, the lifting of export restrictions on key commodities like rice has begun to show positive results in the current fiscal year.

India's Agricultural Exports comprises 2.5% of global agricultural trade maintaining its position as 8th largest agricultural exporter. India ranks second in global agriculture production, but its share in global agricultural exports is only 2.4%, placing it eighth in the world (WTO's Trade Statistical Review, 2022). This disparity between production capacity and export performance reveals significant untapped potential.

Rice contributes more than 20% of total agricultural exports. Top 5 commodities (Basmati rice, Non-basmati rice, Sugar, Spices, Oilseeds) account for 51.5% of total

## Trade Balance Indicators

Metric	Value	Trend
Agricultural Trade Surplus (2023-24)	USD 16 billion	Declining from USD 27.7 billion peak (2013-14)
Agricultural Imports (2023-24)	USD 32.8 billion	-8% decline from previous year
Export-Import Ratio	Positive	India remains net exporter

*Note: Values are approximate based on available official data from APEDA, Ministry of Commerce, and industry reports. Exchange rates vary throughout the fiscal year.*



agricultural exports. Marine products represent the highest value export in the agricultural and allied sector.

Coffee exports showed robust 12.3% growth, Tea exports achieved 10-year high with 10% growth, Fruits & vegetables exports grew by 14%, Meat, dairy & poultry exports increased by 12.4%.

Rice, wheat, and sugar exports faced restrictions in 2023-24. These restrictions contributed to the overall 8.2% decline in agricultural exports. Policy measures aimed at ensuring domestic food security affected export performance.

According to the Export Performance Report released by the Marine Products Exports Development Authority, in Financial Year 2023-24, an all-time high volume of 17,81,602 MT of marine products were exported from India. Valued at over Rs. 60,524 Crore, approximately USD 7,382 million, the export of marine products has greatly benefitted farmers and farmer collectives from the coastal states of Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Gujarat, Maharashtra, Kerala and Tamil Nadu. Despite the total value decreasing by 5.39% (Rs. 63,969 Crore in 2022-23 against Rs. 60,524 in 2023-24) due to geopolitical challenges in the Red Sea and reduced consumer demand caused by inflation in major markets like the USA, EU and UK, exports increased by 2.67% in quantity.

This reflects the positive impact of various initiatives of the Government of India, including the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) and the branding, innovation, and infrastructural development efforts of MPEDA and the Department of Fisheries. India exported marine products to 132 countries, with FY 2023-24 seeing exports to six new markets – Suriname, Chad, the Central African Republic, Mayotte, Sierra Leone, and Guadeloupe. In Financial Year 2024-25, the marine products sector continued to show promising growth, with the Ministry of Commerce and Industry's Department of Commerce reporting that exports increased by 3.40% from USD 0.49 Billion in February 2024 to USD 0.51 billion in February 2025. Total exports have been valued at USD 7.2 billion, reflecting a strong performance despite continuing geopolitical challenges in international trade.

Rice continues to dominate India's

## Geographic Diversification

### Top Export Destinations (FY 2024-25)

Rank	Country	Key Commodities
1	United States	Spices, marine, tea
2	UAE	Rice, meat, marine
3	China	Marine, rice
4	Bangladesh	Rice, onions
5	Saudi Arabia	Rice, meat, tea

*Data sources: APEDA, Ministry of Commerce and Industry, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, and various industry reports.*

agricultural export basket. India had the highest export volume of rice worldwide, at 16.5 million metric tons as of 2023/2024. Rice exports during the first eight months of FY25 (April to November 2024) saw a sharp spike of over 13% to Rs. 63,012 Crore (USD 7.31 billion) compared to Rs. 55,512 Crore (USD 6.44 billion) reported during the same period in FY24. New data released by the Government on 16th May 2025 shows that India achieved a record high of USD 12.5 billion in rice exports in FY 2024-25, a significant increase from the USD 10.4 billion recorded in FY 2023-24.

Rice is the largest exported agricultural product from India and accounts for more than 20% of total agriculture exports. In FY 23, rice exports from India were valued at USD 11.14 billion, as against USD 9.67 billion in FY22, registering a growth of 15.22%. Exports of spices increased slightly, valued at USD 4.45 billion in FY 2024-25, against the recorded value of USD 4.25 billion in the previous financial year. Coffee exports in FY 2024-25 stood at USD 1.81 billion, up from USD 1.29 billion in FY 2023-24. Coffee exports from India jumped by 12.3% to 1146.2 million tonnes in 2023. India's tea exports have also hit a 10-year high, reaching 255 million kilograms in 2024, despite facing challenges from global geopolitical tensions. The Tea Board of India's data shows a robust 10 percent increase from the previous year's 231.69 million kilograms. Recent data shows that tea exports grew from USD 0.83 billion in FY 2023-24 to USD 0.92 billion in FY 2024-25.

India is one of the largest exporters of sheep and goat meat globally. Sheep and goat meat exported from India amounted to over USD 69 million in fiscal year 2023. This was a significant increase from the previous fiscal



**The agricultural export sector has shown a 5-year average growth trend, with the recent decline attributed primarily to policy interventions aimed at ensuring domestic food security. However, the lifting of export restrictions on key commodities like rice has begun to show positive results in the current fiscal year.**

## Cover Story Insight

year. The country has exported 9,592.31 MT of goat/sheep meat to markets globally, valued at Rs. 537.18 Crores during the year 2022-23. Major export destinations for sheep and goat meat in 2022-23 included United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Maldives and Oman (in descending order). The fastest growing export markets for sheep and goat meat between 2022 and 2023 were the United Arab Emirates (USD 8.29 million), Bahrain (USD 663,000), and Kuwait (USD 453,000).

Latin America, Africa, and Scandinavian countries represent high-growth potential destinations, with India actively pursuing market diversification strategies.

Frequent restrictions (such as bans on rice and sugar exports) have impacted India's credibility in global markets, leading to a decline in trustworthiness when it comes to agricultural exports. Imposing restrictions not only affects global food security, particularly for less affluent nations in the Global South, but also undermines India's reputation as a dependable food supplier. India's agri-export basket is dependent primarily on five commodities, making the sector vulnerable to fluctuations in global prices and demand.

The share of processed agricultural exports in India remains relatively low, constituting approximately 17% of total agricultural exports. This is significantly lower compared to leading economies such as the United States (roughly 25%) and China (roughly 50%).

The sector is hindered by inadequate cold chain infrastructure (CCI) and inefficient logistics. Additionally, there is little awareness of the need for farmgate packhouses (pre-cooling units with cold rooms) or other CCI components. According to APEDA, approximately 40% of the country's food undergoes spoilage, which significantly impacts farmers' income.

Ensuring consistent quality and compliance with international sanitary and phytosanitary (SPS) standards is a significant challenge for Indian agricultural exports due to pests, diseases, and lack of awareness.

Small and marginal landholdings, coupled with a lack of access to credit, present persistent challenges in transitioning to commercial production. Small and marginal farmers with less than two hectares of land account for 86.2% of all farmers in India. Small land holdings and low mechanisation hinder economies of scale.

### Government Initiatives and Policy Framework

The Government introduced a comprehensive Agriculture Export Policy in December 2018 with a vision to harness export potential of Indian agriculture, through suitable policy instruments, to make India a global power in agriculture and raise farmers' income through the 'Doubling Farmers' Income' set of interventions.

Key objectives include achieving USD 100 billion in agricultural exports over the next decade and striving to double India's share in world agricultural exports by integrating with the global value chain as a matter of priority.

One of the most significant recent developments in India's agricultural export landscape is the formation of National Co-operative Exports Limited (NCEL) by the decision of the Union Government's Cabinet and with the



Photo: NCEL



support of the Ministry of Cooperation. NCEL was registered under the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 on January 25, 2023.

NCEL is a multi-state cooperative society jointly promoted by some of the leading cooperative societies in the country, namely: Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (GCMMF) - Amul; Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO); Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO); National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED); and National Cooperative Development Corporation (NCDC), a statutory corporation under the Ministry of Cooperation.

The authorised share capital of NCEL is Rs 2,000 crore, with cooperatives at all levels, from primary to national, eligible to join as members. NCEL serves as an umbrella organisation for exports from the cooperative sector, promoting exports at all levels and across all sectors. This helps maximise the export potential of Indian cooperatives in overseas markets.

NCEL provides a complete ecosystem for the promotion of exports, mainly of agricultural commodities, for the benefit of farmers. It will promote exports through various activities including procurement, storage, processing, marketing, branding, labelling, packaging, certification, research & development, and trading.

NCEL assists cooperatives in value addition and improving product quality according to international standards to enable cooperative exports to compete in the international market. The organisation provides the following services - Assistance with export certification and logistics; Obtaining funds and providing technical guidance; Training and capacity building; International and national market research and building market intelligence systems; Export-related consultation services; Creating and maintaining a knowledge repository for cooperative exports and Branding, labelling, and packaging support

Being an umbrella organisation for cooperative sector exports, NCEL assists farmers in obtaining higher prices for their products in overseas

NCEL addresses several critical challenges in agricultural exports - Solving

**Export Market Problems:** Tackles issues such as fierce competition, monopoly, malpractices, lack of infrastructure, and standardisation. **Leveraging Cooperative Strength:** Utilises the extensive cooperative network that serves 60% of India's population dependent on agriculture. **Whole-of-Government Approach:** Helps cooperatives reap benefits of various export-related schemes and policies of different ministries in a focused manner. **Inclusive Growth Model:** Works towards fulfilling the Government's vision of "Sahkar se Samridhi" (prosperity through cooperation)

The National Co-operative Exports Limited represents a paradigm shift in India's approach to agricultural exports. By harnessing the collective strength of cooperatives, NCEL can play a pivotal role in achieving the USD 100 billion agricultural export target through scaling cooperative participation. With over 10,000 cooperatives onboarded as members and the potential for exponential growth, NCEL can aggregate production from millions of small farmers across the country.

By providing technical guidance and quality enhancement support, NCEL can ensure that cooperative products meet international standards consistently. Through collective branding and marketing efforts, NCEL can create strong brand identities for Indian agricultural products in global markets. The umbrella structure allows smaller cooperatives to access international markets with reduced individual risk.

A major boost for agricultural exports would come from newer ideas and innovations, both in terms of technology and business models. In this context, policies to support and enrich the start-up ecosystem may prove to be extremely beneficial. Technology and innovation are radically transforming Indian agriculture, ushering in a new era of efficiency and sustainability. Digital platforms and agtech solutions empower farmers with real-time data, precision farming techniques, and automated irrigation systems. AI-driven tools enable predictive crop management, early detection of diseases, and optimized fertilizer use, thereby reducing waste and increasing yields. Innovations in mobile applications, sensor networks, and drone



**While challenges such as infrastructure deficits, fragmented landholdings, and policy inconsistencies persist, the sector's potential remains enormous. With strategic interventions focusing on technology adoption, value addition, infrastructure development, and policy stability, India can realise its ambition of achieving \$100 billion in agricultural exports.**



**Frequent restrictions (such as bans on rice and sugar exports) have impacted India's credibility in global markets, leading to a decline in trustworthiness.**

surveillance bridge information gaps while connecting rural farmers to markets and financial services. This technological revolution not only boosts productivity but also strengthens rural economies, positioning India as a future farming powerhouse in the global agricultural landscape. NCEL is striving to promote advanced agricultural technologies, precision farming, and efficient irrigation, while empowering agri-startups and innovative solutions to boost productivity and export efficiency.

Value addition and processing of agricultural produce play a pivotal role in expanding India's export potential by transforming raw materials into high-quality, market-ready products. Enhanced processing techniques improve shelf life and increase nutritional value, thus appealing to global consumers. Converting perishable items into processed goods also minimizes post-harvest losses and strengthens food safety standards. Additionally, value addition facilitates product branding and differentiation, enabling access to premium markets abroad. By investing in modern processing infrastructure and adopting innovative technologies, India can significantly boost its agricultural exports,

ensuring higher returns for farmers while reinforcing its esteemed reputation in the international trade arena.

To boost exports, the government has identified 20 agricultural products with high export potential in developed countries. These include items such as bananas, mangos, cashew nuts, buffalo meat and alcoholic beverages. India's share in the USD 400 billion global market of such products was only 2.23% in 2022, amounting to USD 9 billion. The aim is to capture 4 to 5% of the international market share in the next few years.

### Policy Recommendations

Economists suggest more predictable and rules-based policies, like temporary tariffs, to manage exports without sudden shocks. The government should maintain buffer stocks of essential commodities to mitigate price volatility and ensure market stability. Focus on meeting international standards and developing quality assurance mechanisms to improve competitiveness in global markets. Expand NCEL's reach to include more cooperatives, enhance its technological capabilities for scaling operations.

India's agricultural export sector stands at a critical juncture. While challenges such as infrastructure deficits, fragmented landholdings, and policy inconsistencies persist, the sector's potential remains enormous. With strategic interventions focusing on technology adoption, value addition, infrastructure development, and policy stability, India can realise its ambition of achieving USD100 billion in agricultural exports.

The success of this endeavour will not only boost foreign exchange earnings and improve farmers' incomes but also position India as a reliable and competitive player in the global agricultural market. The journey ahead requires coordinated efforts from government, private sector, and farming communities to unlock the full potential of India's agricultural export sector.

Data sources: APEDA, Ministry of Commerce and Industry, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, and various industry reports. 







श्री पुष्कर सिंह धामी  
मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखंड



International Year  
of Cooperatives

Cooperatives Build  
a Better World



डॉ. धन सिंह रावत  
मा. सहकारिता मंत्री, उत्तराखंड

# उत्तराखंड को-आपरेटिव रेशम फेडरेशन लि.

सिल्क पार्क भवन, चकराता रोड, प्रेमनगर-देहरादून



## Doon Silk

A Brand of Uttarakhand Co-operative Resham Federation

**More than 6500 beneficiaries associated**

**A Complete value chain unique business model**

**More than 58 Primary Co-operative societies Associated**

**100% backward and forward lineages**

**A umbereela brand Doon Silk for all silk and allied by products**



आनंद ए.डी. शर्मा  
प्रबंध निदेशक यूसीआरएफ

सोनिका (आईएसएस)  
प्रशासक/निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखंड, देहरादून

Website: [www.ucrf.org.in](http://www.ucrf.org.in), [www.doonsilk.com](http://www.doonsilk.com), Email: [dosua2002@gmail.com](mailto:dosua2002@gmail.com)

# Reimagining India's Agricultural Exports: From Plough to Port

A blueprint for sustainable growth through product diversification, market alignment, and infrastructure reform



**Siraj A Chaudhry**

Partner, Agvaya LLP



**M Ramakrishnan**

Managing Director,  
Primus Partners

Agriculture contributes to the livelihood of 40%+ our population, and 18%+ to our GDP. Over the past 3 years, our Agriculture and Allied products' exports has hovered around US\$ 50 billion .

Our share of global Agriculture exports is less than 3%. China, with comparable (rather, lesser) arable land, exports nearly US\$ 100 billion worth of agricultural products . This disparity underscores the efficiency and value-addition gap that must be bridged.

The Top 5 countries we export to include US, China, UAE, Vietnam, Bangladesh. The next in line are Saudi Arabia, Malaysia, Iraq, etc.

The top commodities we export include marine products, rice (both basmati and others), spices, buffalo meat, sugar, etc. Marine products' exports value was US\$ 7~8 billion in the recent years. Cotton exports stood at ~US\$ 6.8 billion . Rice (both basmati and others) remains a top export item, with its recent numbers hovering ~US\$ 10 billion. Buffalo Meat exports have remained relatively stable, ranging from US\$ 3.17 ~3.74 billion.

Fresh fruits, overall, barely make it to the top 10.

Interestingly, the share of processed food in exports of agricultural products has increased from 13.7% in 2014-15 to 23.4% in 2023-24 . Processed food exports have grown from ~US\$ 6 billion in 2018-19, to ~US\$ 10.9 billion in 2023-24 .

However, in the face of climate stress, declining groundwater levels, and global market shifts, it is imperative for India to recalibrate its agricultural export strategy. The current export mix, dominated by water-intensive staples like paddy, must gradually give way to nutritionally dense, economically

viable, and environmentally sustainable alternatives.

To almost double our Agricultural exports, to reach US\$ 100 billion, will take significant efforts across multiple dimensions – policy, incentives, infrastructure development, active engagement with buyers, and above all, a strong will to make it happen.

This paper identifies the emerging and underutilised export avenues in Indian agriculture, evaluates the sustainability of key export segments, and suggests a forward-looking roadmap for diversified, climate-resilient, and globally competitive agricultural exports.

## How should the commodity mix change, for sustainable growth in Agricultural exports?

### The Case Against Paddy

Rice has been India's agri-export mainstay for decades. However, the ecological cost of paddy cultivation is increasingly under scrutiny. Paddy consumes over 4,000–5,000 litres of water per kilogram, making it unsustainable in water-scarce states. Continuous monocropping leads to nutrient depletion and declining productivity. Also, paddy fields are a significant source of methane emissions.

As climate change exacerbates agronomic stress, relying on paddy exports as a growth lever is not sustainable. There is growing policy and market consensus around diversifying into low-input, high-output crops.

### Millets: The Superfood Revolution

Millets have emerged as the poster child of sustainable agriculture. In 2023–24, India exported 1.46 lakh tonnes of millets worth US\$71 million, led by products like sorghum, finger millet, pearl millet, and processed millet snacks (source: APEDA ). Millets require 70% less water than paddy, are pest-resistant, and



thrive in arid soils. Also, millets are gluten-free, rich in fibre, minerals and protein—ideal for health-conscious global consumers.

The declaration of 2023 as the International Year of Millets by the UN has opened new markets, especially in Europe, North America, and West Asia. This momentum must now be institutionalised with branding, GI tagging, and organic certification.

#### Maize: A Resilient Commodity with Diverse Demand

Maize is increasingly being used across food, feed, starch, and biofuel sectors. In FY24, India exported 1.44 million tonnes of maize valued at US\$440 million, with high demand from Bangladesh, Vietnam, and Nepal. It is less water-intensive and adaptable across agro-climatic zones.

Investments in post-harvest drying, better agronomy practices, and a push towards contract farming can further consolidate India's position.

#### Cotton: Rebuilding Leadership through Value Addition

Over the last 7-8 years, Cotton exports from India have fluctuated between US\$ 5 ~10 billion. Our farmers deal with global prices volatility and competition from Brazil and the US.

To revive competitiveness, India must shift from raw cotton exports to value-added segments like organic cotton, yarns, and technical textiles. Branding initiatives around "Sustainable Indian Cotton" can enhance price realization.

#### Buffalo Meat and Animal Products

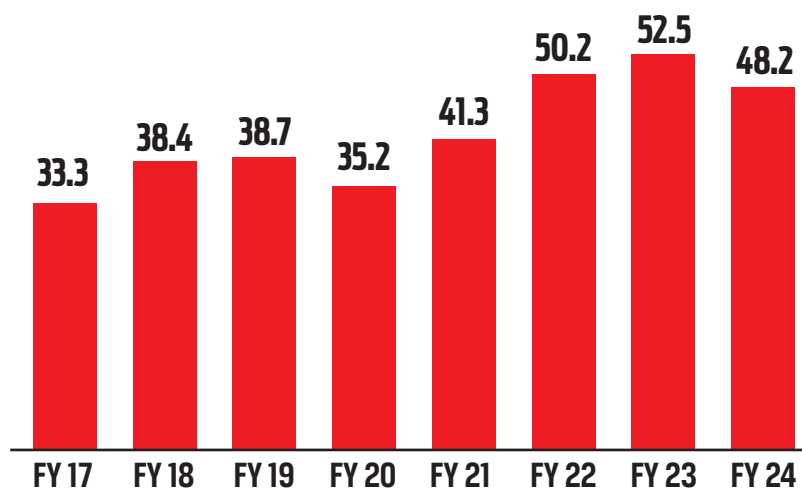
India is the world's largest exporter of buffalo meat, with FY24 exports reaching US\$3.74 billion. Primary markets include Vietnam, Malaysia, and Indonesia. India's meat sector adheres to OIE and Codex standards, making it globally competitive. With rising global protein demand, particularly in Asia, India can grow its meat exports with improved traceability and logistics.

Additionally, categories like animal casings, hides, and dairy products (e.g., paneer, ghee) are gaining ground, with scope for premiumisation.

#### Processed Foods: The Next Frontier

Processed foods accounted for US\$ 10 billion in FY24 exports, making up over 23% of

### India's agriculture exports trend (US \$ billion)



Source: IBEF

India's agri-exports. The shift towards packaged and branded foods in global markets is irreversible. India's diverse culinary tradition, low-cost manufacturing base, and growing organic segment give it a unique edge.

In markets such as the US, ~50% of the food exports is processed. In India, there is scope to increase the share of processed exports to ~40%. Shrimp exports alone could grow to nearly US\$ 10 billion with more processing as ready-to-eat items.

#### What we need to work on, to achieve our exports goals

**Customer Engagement:** We need to critically analyse top food importing countries around the world, and keeping in mind their local procurement needs and the Indian produce strengths, identify gaps to be addressed. It is important to diversify beyond our existing large customer base and establish a strong presence in large and profitable markets such as Europe, Australia.

Once we prioritize a few key target countries, we must invest heavily in engaging with these customers. It could require establishing international presence of a government body such as APEDA or similar entity. Both government and the industry (export bodies, Agricultural traders, organizations such as NABARD, etc. from India) need to work closely with



**India's agri-export strategy, long dominated by water-intensive crops like paddy, must now pivot to climate-resilient, high-value commodities such as millets, maize, and processed foods.**

these importing nations, understand their requirements and then work with the farmer ecosystem as per the requirements. For instance, we need to pay special attention to sanitary and phytosanitary (SPS) compliance in export destinations like the EU and the US.

If it needs any government-to-government negotiations such as FTA, then those steps need to be taken. The engagement may require investments in trade shows abroad (e.g. Gulfood, Anuga, Biofach), or inviting the large buyers to India. It may require promotional schemes and incentives – either to the buyers abroad, or to the farmers in India. A strong campaign on, say “Taste of India” (drawing inspiration from Thailand’s “Kitchen of the world” push), may be required to promote Indian Agriculture and food exports.

A heavy marketing budget should be planned for all these activities, just the way a typical, large Food / FMCG business would plan its global expansion.

**Product Development:** As mentioned above, once we understand the importer requirements, we need to work with the farmer ecosystem accordingly. These may be new products (e.g., avocado) or new clusters (e.g., North-east) or just a new push within an existing cluster (e.g. Grapes / Nasik). If we look at the length and breadth of Indian agro-climatic zones, we grow a wide variety of “not very popular in India” items such as rambutan, dragon fruit, avocados, etc. If we get the right market linkage, we can scale such items. Eventually, the product mix must be such that the per-unit-value of the trade goes up from current levels.

The product specifications need to be translated into agronomy practice definitions and standard operating procedures. Whether it includes more sustainable practices (less water usage or lower emissions) or involves technology embedding such as blockchain-for-traceability, all those necessary elements need to be incorporated.

GI-gagging is already being explored; more should be considered, with the clear intent to demand a premium wherever the customer recognizes our produce specialty. The government must actively work with its network of KVK (Krishi Vikas Kendra)s and their extension workers as well as FPOs and other farmer organizations to ensure that necessary changes happen on the ground.

**Supply chain Effectiveness:** As the core

commodity production process gets streamlined, the next step is to ensure that there is appropriate infrastructure support across the supply chain. Starting from right kind of solar-powered cold storage units at the farm level, to cold storage facilities, to pack-houses, to reefer trucks to advanced packaging and processing units is critical.

The customer needs for processed food items would require us to invest in large processing factory set ups. With our agricultural production levels, India can easily establish ten mega food parks exclusively for export-oriented processing. These should incorporate integrated facilities from warehousing to quality testing and export documentation.

We also need adequate testing facilities (for globally valid certifications – GAP, HACCP, organic, etc.). Treatment facilities (e.g., vapor treatment) also need to be set up, to ensure the products meet global phytosanitary requirements.

One common issue faced by Agriculture exporters is connectivity to airports or seaports. Secondly, not all ports are well equipped to handle Agriculture exports. When looking at the supply chain, every single link from the farm until the product reaches the customer location, needs to be critically analysed. Fresh infrastructure investments may be needed; and these may be needed to be beefed up with incentives and subsidies



**Doubling agricultural exports to \$100 billion requires more than good harvests—it demands cold chains, port access, testing labs, skilled manpower, and strategic customer engagement. With coordinated public-private investment and a shift from volume to value, India can build a globally competitive export ecosystem.**





around transportation costs. PPP investments should be strongly encouraged. Soft loans and grants to FPOs for setting up their own units is another way. Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) scheme should be expanded, with special focus on Agricultural exports. Government should use viability gap funding to make investments in critical infrastructure more attractive.

Switching from air freight to sea freight offers significant advantages in terms of cost effectiveness and environmental sustainability. Sea freight provides a more economical

option for transporting large volumes of goods over long distances, reducing shipping costs per unit. Additionally, it has a lower carbon footprint compared to air freight,

aligning with global efforts to minimize environmental impacts and promote sustainable

supply chain practices. The right protocols need to be developed, from on-farm practices to packaging and logistics.

The development of 50 integrated export logistics hubs across major agricultural production regions could be a major boost to exports. These should provide end-to-end solutions including aggregation, sorting, packaging, pre-cooling, and customs clearance.

In case there is any technology investment needed from the government side to support

these activities – e.g., usage of satellite data and IoT sensors to ensure timely and accurate agronomy advice – those necessary investments must be stepped up. There would certainly be a need for a central “war room” with real-time insights coming from global developments, weather pattern changes and latest production trends in the fields.

Approximately US\$ 8-10 billion is needed across inputs, infrastructure, processing, and demand enablers. These Infrastructure improvements could generate 7-10 million jobs along the agricultural export value chains.

**People Development:** Whatever direction we take, we must consciously invest in training and capacity building of the entire ecosystem.

The bureaucrats should be trained on global best practices, how large MNCs in the food / FMCG space operate, how other governments (such as China) expand the business footprint.

The extension workers and KVK employees need to be trained on global standards, any new practices required, and how to address weather unpredictability when adopting new methods.

Needless to say, the farmer needs the maximum training if there is a new requirement from the customers, or there is a need to adhere to stringent processes or quality standards.

And all these different stakeholders need to be trained on new technological possibilities.




**Processed foods now account for over 23% of India's agri-exports, driven by rising global demand for convenience and quality. By focusing on branding, compliance, and value addition, India can capture a greater share of high-margin export markets and position itself as a global hub for healthy, ready-to-eat products.**

## Conclusion:

### From Volume to Value

India's agricultural export strategy must evolve from a volume-driven to a value-led approach. Instead of chasing incremental gains in traditional exports like rice or sugar, we must invest in sustainable, climate-resilient, and high-growth commodities—such as millets, maize, buffalo meat, processed foods, cotton value chains, and horticulture.

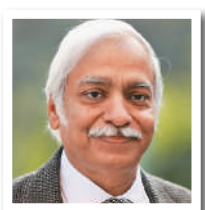
Doubling exports will directly contribute to the goal of doubling farmers' income. In addition, the food processing industry will also grow.

Reaching US\$ 100 billion in agricultural exports is not a distant dream. With coordinated reforms, strategic investments, and an unrelenting focus on execution (and not just intent), we can turn this dream into reality. 



# Making Indian Agriculture Globally Competitive

India's ambitious goal in agricultural exports hinges on overcoming supply chain challenges, boosting value addition and navigating complex global trade dynamics



**Prof. Rakesh  
Mohan Joshi**

Vice Chancellor  
Indian Institute of Foreign  
Trade, New Delhi

rakeshmohanjoshi@iift.edu

Agriculture in India is crucial to the livelihood of its people, employing over 45% of the population and contributing 18% to the GDP. Moreover, food security and self-sufficiency are critical for the world's most populous country, India, with 1.42 billion people. India's agricultural production is largely consumed domestically to feed its massive and growing population, unlike developed economies where major production is sold in international markets. Indian agriculture is characterised by fragmented landholdings, high vulnerability to climatic fluctuations, low productivity, and market inefficiencies. Despite these challenges, India has emerged as the world's largest producer of various agro-commodities such as milk, pulses, jute, rice, sugarcane, wheat, cotton, etc.

India has come a long way from being a net importer of agricultural commodities like foodgrains to the world's largest exporter of rice, accounting for about 40% of the world market share. India's agro-exports grew impressively from \$7.5 billion in 2000-01 to \$53.1 billion in 2022-23 at a compound annual growth rate (CAGR) of 8%, despite restrictions imposed from time to time in terms of quantity or minimum export prices on commodities such as rice, sugar, and wheat.

Over the years, India has been heavily dependent on imports of edible oils and pulses, which in value terms exerts considerable drag on India's trade balance in agri-trade. In 2024, India's agricultural exports increased by 6.5%,

whereas imports surged by 18.7%, leading to a rise in India's agri-trade deficit. Major agri-exports such as marine products, non-basmati rice, sugar, basmati rice, and spices contribute over 50% of India's total agro-exports.

## Key Challenges to Agro-Exports:

FAO indices on agri-commodity prices and World Bank commodity price indices indicate a declining trend in agri-commodity prices in real terms. The World Bank forecasts about a 7% decline in world food prices in 2025, followed by a further 1% decline in 2026. This makes it imperative to make Indian agriculture





competitive at every stage of the value chain to ensure agri-produce is globally competitive in international markets.

The perishable nature of agri-food products faces significant challenges from supply chain bottlenecks, especially related to cold-chain, storage, transportation, and processing. Indian agriculture suffers from systemic issues that need to be addressed holistically. Supply chain constraints owing to inefficient storage and transportation lead to considerable post-harvest losses of about 15-20%.

Developed markets are increasingly protectionist, erecting insurmountable non-tariff barriers in the form of stringent quality standards, restrictions on fertilizers and pesticides, and sustainability requirements.

### Need for a Comprehensive Strategy and Meticulous Implementation:

To harness India's full potential in agro-exports, it is essential to address supply chain inefficiencies and reduce wastage both on farms and across the supply chain. Focus should be on value addition and processed food exports rather than commodities with little value addition. Identifying and diversifying into new markets in light of emerging geopolitical sensitivities should form an integral part

of India's agro-export strategy.

India needs to improve productivity significantly, reduce the phased use of agro-chemicals, shift towards organic production, and use water efficiently while ensuring production volume gains. This requires the efficient integration of innovative scientific techniques for production and water harvesting, leveraging AI technology and next-generation agricultural technologies.

India must also shift focus from foodgrain production and exports towards horticulture and value-added products with longer shelf lives and higher margins.

India's One District One Product (ODOP) strategy requires effective implementation, leveraging inherent efficiencies and synergies.

Both state and central governments need to develop schemes facilitating these objectives at the farm and supply chain levels, integrating various agencies. Government departments should function in a coordinated, holistic exports promotion strategy rather than in silos.

India must be cautious in entering new trade agreements to ensure market access benefits with clarity on non-tariff barriers. Considerable efforts are needed to upgrade quality to meet emerging trade barriers and minimise rejection of consignments at destination markets.

Special caution is warranted as developed countries such as the USA, EU, Australia, and New Zealand are keenly eyeing India's vast consumer market of 1.42 billion people.

The recent unpredictable US tariff regime—with a 26% tariff on India and differential reciprocal tariffs on other countries—has complicated international trade analytics. Under this regime, tariffs on Vietnam and Thailand increased, making Indian rice more competitive, but later all tariffs were paused.

The international market is becoming more complex with differential reciprocal tariffs, especially higher tariffs on China, which may reduce China's dependence on US agro-imports and compel US producers to find alternative markets. This necessitates timely monitoring of import tariffs across countries, especially competitors and major markets. Governments, promotional agencies, and exporters alike need to vigilantly track international markets and adopt dynamic trade strategies. 



**Both state and central governments need to develop schemes facilitating these objectives at the farm and supply chain levels, integrating various agencies. Government departments should function in a coordinated, holistic exports promotion strategy rather than in silos.**



# India's Dairy Export Potential: A Perspective

Examining India's rise as the world's top milk producer and the steps needed to convert surplus into global export success.



**Vipin Kumar  
(Kakkar)**

Enav Enterprises

As the world's leading milk-producing nation, India has reached an annual production of 240 billion litres (240 million tonnes), accounting for over 24% of global output. What a phenomenal transformation it has been—from a milk-deficit country 50 years ago to one that is now self-sufficient and looking to become a global supplier!

We often lament that milk production growth last year was only 3.8%, a drop from the earlier average of 6%. But let's not forget: global milk production is growing at just about 1% annually. Coupled with challenges faced by developed nations—such as high nitrogen levels in soil and greenhouse gas emissions like methane—one must ask: where will surplus milk come from in the future? India arguably offers the most promising answer, with its vast cattle wealth (over 300 million), dairying as a major economic activity, and multiple government initiatives focused on improving the sector. An estimated 10 million people are engaged in milk production, with women comprising more than 75% of this workforce!

## Let's take a closer look at where we stand globally in milk production:

As seen in the table, India—with 240 billion litres today—is on track to match the combined milk production of the five major dairy-exporting countries/regions in just 3–5 years. Imagine that!

Looking ahead, India is projected to contribute 30% (300 million tonnes) of global milk production by 2030, and possibly 45% by 2047. With our per capita domestic milk consumption now at 470 grams/day (compared to the world average of 322 grams/day), one might ask: how much more can we consume? When compared to developed nations, where the average is around 750 grams/day, there's still headroom for growth. But in 3–5 years, India is likely to reach a surplus—if not sooner.

## Preparing for Surplus: The Need for Strategic Action

In anticipation of this surplus, it's imperative that we begin preparing now. The global dairy trade stood at \$107 billion in 2023, and India's entry into this space is not just logical—it's necessary.

## Current Scenario & Constraints

In a typical year, India produces approximately 600,000 tonnes of skim milk powder (SMP). Of this, around 350,000 tonnes are used during the lean season for recombination, and another 150,000 tonnes are absorbed into food applications, leaving about 100,000 tonnes as rolling stock. However, over the past 2–3 years—due to attractive milk prices, herd growth, better feed, and a shorter lean season—we found ourselves with surplus stocks exceeding 300,000 tonnes of SMP. This excess caused SMP prices to remain depressed for months.

With domestic consumption unlikely

## Fluid Milk

Cow's Milk Production Summary for major Exporters (Million tons)				
	2022	2023	2024 Forecast	2023-2024 Change
Argentina	11.9	11.7	10.8	-7.4
Australia	8.5	8.5	8.8	3.3%
European Union	144.4	145.2	145.3	0.1%
New Zealand	21.1	21.2	21.1	-0.7%
United States	102.7	102.7	102.9	0.2%
Major Exporter Total	288.6	289.3	288.9	-0.1%

Note: Data is rounded



to shift dramatically overnight, exports appeared to be the only solution. Yet Indian SMP prices were not internationally competitive, and global demand remained weak—particularly from China. So, what's the way forward? We need to diversify beyond basic Medium Heat SMP and develop specialized variants such as Low Heat SMP (used in cheese production) and High Heat SMP (used in evaporated milk). But consistent production of these variants requires not only high-quality raw milk but also advanced equipment and technology. This means investing in technical capacity, R&D, and adopting a more innovation-led mindset.

To compete globally, India must focus on the Three C's: Consistency in Quality: Consistency in Supply: and Consistency in Price Competitiveness

A bright spot amidst recent challenges was the strong performance in butter and milk fat exports—55,000 tonnes in calendar year 2024—helping dairy processors manage excess stock, improve cash flow, and earn foreign exchange. One can only imagine how difficult the situation would have been without this opportunity.

**Where Do We Stand on Dairy Exports?** Currently, India's exports of SMP and butter are largely opportunistic in nature.

While we've maintained trade with the Middle East, Southeast Asia, and neighboring countries, players like Amul have led the way in taking Indian dairy to global markets, with a presence now in the USA and plans for the EU. KMF has also launched Nandini Dairy Parlours in Dubai. Perhaps it's time to learn from these pioneers and scale up.

We should also draw inspiration from established dairy-exporting nations like New Zealand, the USA, and the EU. Additionally, countries like Malaysia, which aren't traditionally milk producers but excel in exports (e.g., condensed milk), offer valuable lessons. We don't need to copy their models, but we can certainly learn from their experience and create our own unique USP.

### Exploring New Markets

We need to expand our market reach to include key importers such as Russia, China, Africa, and Mexico. While some of these markets are already open, others require regulatory clearances—an area where



government intervention would be invaluable.

Looking further ahead, once we establish a reputation for reliable, standardized, and competitive supplies, why not envision an “Indian Dairy Products Auction Platform” for global exports? Why not, indeed?

### Opportunities: What to Target?

As mentioned earlier, moving beyond bulk SMP to value-added and specialized dairy products is crucial. Here are some avenues:


**B2C Consumer Products:** India's proximity to markets makes UHT milk, flavored milk, fresh cream, and ice cream mixes attractive export options.

**Buffalo Milk Advantage:** As the world's largest producer of buffalo milk—with expected herd growth—we have a distinct edge in white dairy products like mozzarella and white cheese spreads.

**Anhydrous Milk Fat (AMF):** Ideal for recombination in Middle East and Southeast Asian markets.

**Ethnic Sweets with Shelf Life:** Indian sweets are increasingly popular among the diaspora. Tweaking recipes to suit global palates could unlock new demand.

**Tailored Products:** Milk powder with vegetable fat, though not in high domestic demand, is well-accepted in Africa, Iraq, the Middle East, and Southeast Asia.

In a nutshell, exports are the only sustainable long-term solution for India's dairy sector. While we've achieved self-sufficiency, becoming a global leader will require further vision, investment, and effort. Let's seize this opportunity—while we still have the advantage. 



**While we've maintained trade with the Middle East, Southeast Asia, and neighboring countries, players like Amul have led the way in taking Indian dairy to global markets, with a presence now in the USA and plans for the EU.**

# Focus will be on Farmer Centric Research: Dr. ML Jat

*The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) plans to change its research methods and make the needs of farmers the basis of its research. Along with this, the functioning system of all the institutes working for agricultural research and state agricultural universities is also going to change, while the role of Krishi Vigyan Kendras will also be redefined so that their role in agricultural extension can become more effective.*

*In a way, the concept of One ICAR will be taken forward. Also, the emphasis will be laid on a holistic agri food system approach at the center of research and methodology. Dr. Mangi Lal Jat, the new Director General of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and Secretary of the Department of Agricultural Education (DARE), said in an exclusive interview with Rural World Editor-in-Chief Harvir Singh on the country's agricultural sector, research and policy issues.*

*Here are the excerpts of this interview with Dr. Jat: -*

**Q** *Agriculture is the most important sector for the country's economy. Coming from a rural background, you have a long experience in the field of agricultural research in national and international institutions. Now you have got the responsibility of ICAR, which is counted among the world's largest agricultural research systems, and DARE, Secretary of the Government of India. What is your vision for ICAR and agricultural research?*

Agriculture is the backbone of our country. The dream of a developed India by 2047 cannot be achieved without developed agriculture. Agriculture is diverse – in terms of land, water, climate, and farmers. We need to conduct research and innovation in agriculture accordingly. A single research or innovation may not work everywhere. That's why it's said that there is nothing absolutely right or wrong in agriculture. Its mantra is demand-based and relevant research.

There was a time when we lacked food. Hence, during the Green Revolution, our focus was on increasing production and productivity. Research at that time was designed with a focus on yield. But the situation today is different. Now, overproduction is the problem. The government faces challenges in managing this surplus. Farmers are forced to sell crops at throwaway prices. We need to focus on this issue.

Recently, there was a discussion that overproduction of rice leads to disposal issues, while on the other hand, we import pulses and oilseeds. Why are we moving in that direction? We need targeted research and technology. Targeting means directing the right solution to the right place, economically feasible for farmers and sustainable for the environment. For example, extracting water for 10 years to grow paddy and then running out of water is not viable. We must design our approach according to specific conditions.

Conditions have changed significantly. These are the mega-trends – climate change, land degradation, and biodiversity loss. To address these challenges, our research design must evolve. We've remained fixated on production, but agricultural output alone is not holistic. We must also consider pre- and post-production factors. Hence, there's increasing talk of a comprehensive agri-food systems approach. Without this, farmers won't get market linkage, technology targeting won't happen, and business models won't be built.







**Dr. Mangi Lal Jat**  
Secretary, DARE  
Director General, ICAR

Photo: [Rural World](#)

**Q What kind of changes are needed in the research system?**

When the focus was on production, our scientists were skilled in that area. Now, as we design a complete agri-food system, different skills are needed. For example, we talk about FPOs (Farmer Producer Organizations). While KVKs can provide FPO training, an expert is needed to create a business plan. These are new areas we need to integrate.

**Q So you're saying agro-economy, research, natural resources, and**

**climate change should all come together as a complete package?**

Exactly. It shouldn't be commodity-centric. For instance, suppose a rice variety matures in 150 days but is harvested in 155 days. While this may increase yield by half a ton, it may delay the next crop, causing a loss of one ton. We need to determine what fits best where. If a farmer has a 70-day window, what can be grown in that period? Growing a 100-day crop in a 70-day window won't work. Redesigning is essential.

**Q How is ICAR working in agricultural research, education, and extension?**

Historically, India has had a robust system of agricultural research, education, and extension, from top to bottom. But as we've become more self-reliant, we started working in silos. We can't afford that. Every institute can't have every kind of expertise. Suppose one person specializes in something, and someone nearby specializes in another – sharing their expertise enhances the whole system. We need to



## Interview

consolidate these capabilities.

Agriculture is a state subject. Coordinated programs are run in state agricultural universities. Crop varieties are developed locally, recommendations are given to states, and states implement them. We must strengthen coordination with state agricultural universities. KVKs work under different bodies – some under state agri-universities, some under NGOs, some under ICAR. State extension departments also work in isolation.

We want the system to be interconnected from bottom to top. Information should flow both ways – from ground-level demand to research, and from research to farmers via extension. For this, we must create a strong National Agricultural Research Extension Education System.

**Q Research involves two aspects – science and economics. Research is often conducted in ideal conditions, but when it reaches farmers' fields, the economics differs. How can this be made transparent?**

There is a system. First, the technology is developed. Then, it undergoes multi-location testing, followed by adaptive trials on farmers' fields. Even within a single field, differences exist – due to soil, management, etc. Even two brothers with adjacent fields may get different yields from the same variety because of management differences.

Therefore, today we need as much socio-economic research as biophysical research – on varieties, water, nutrients. We often say farmers adopt or don't adopt technologies. But why? We must understand the behavior behind it.

No farmer wants low yields. But many decisions are influenced by relatives or community. We talked to farmers about zero tillage. They said it saves water, money, and gives good crops. But they don't like how the field looks afterward – a behavioral issue. Agriculture is not always straightforward.

**Q Will ICAR increase its focus on sociology, humanities, or liberal sciences?**

Absolutely. But it won't happen overnight. We are focusing on strengthening social sciences. The scope of biophysical scientists' work is broad and includes other aspects too. We've seen a wide gap between average and actual yields. This shows that while technology exists, adoption is a challenge. We need to understand the reasons behind the yield gap. More than 50% of it is due to knowledge gaps. That means we must improve knowledge dissemination. Krishi Vigyan Kendras help bridge this gap.

**Q One new technology is GM. There has been a lot of research, both in ICAR and private sector. How will this move forward?**

Our focus is on science-based agricultural transformation. We cannot progress without science. We need new science to solve future challenges. There's a regulatory process, and the matter is in court, so I won't comment. But I will say this: science must lead the way. Change should be science-driven.

**Q There's growing focus on Internet of Things (IoT) in agriculture. Many ICAR projects are based on it. How do you see this trend?**

We must keep pace with technological progress. Otherwise, we'll fall behind. But it should not just be a fancy term. It must be usable on the ground. The core of AI and IoT is data. Without quality, organized, and interoperable data, success is limited. AI relies on data. If AI lacks integration with natural intelligence, it won't suffice. A balanced combination is needed. We must develop a strong data ecosystem.

We have decades of data. The Ministry is building a Digital Public Infrastructure to map every field. Agriculture relies on data from 7–8 ministries. Without fertilizer or water data, can we farm? A robust AI requires a complete data ecosystem. For small tasks, things may work, but for the big picture, quality data is essential.

**Q Extension is a crucial component, but it is said to be underperforming. How do you see this, especially in the**

**context of yield gaps and behaviour?**

Extension is essential. Compared to the past, today's extension is more complex. Now we talk about digital extension, which requires skills. Without skills, delivery fails. Hence, we talk about the "science of delivery." We must link the science of discovery with the science of delivery. If they function separately, problems arise.

Extension is a science in itself – the science of delivery. It requires several elements, like technology-based business models. If business grows through technology, delivery happens. If not, delivery fails. For 70 years, we've followed a linear extension model. We now need a mix of linear and non-linear systems. A new extension ecosystem is emerging. The private sector also has its own network. We aim to converge both public and private systems. If they





work in different directions, farmers lose. We're working towards this convergence.

**Q** *Our agricultural exports have reached \$50 billion. What is ICAR's focus on export-oriented production, quality, and standards?*

Our exports are based on quality – whether it's basmati or other crops. But we must also assess what the country can afford to export. For example, producing rice in water-scarce areas for export while importing pulses and oilseeds isn't sustainable. We're working on this. Sustainability is key. We will focus only on what benefits India and its farmers.

**Q** *How can farm mechanization help bring youth back into agriculture? It is also tied to dignity.*



**We want the system to be interconnected from bottom to top. Information should flow both ways – from ground-level demand to research, and from research to farmers via extension. For this, we must create a strong National Agricultural Research Extension Education System.**



Photo: Rural World



We always talk about efficiency – of water, nutrient, etc. But we forget time efficiency, which is most critical, especially with climate uncertainty. Without mechanization, we can't ensure time efficiency.

There is good progress in mechanization, but many areas still need access – like rainfed or hilly regions. Mechanization isn't just about tractors. Planting, harvesting, inter-cultivation – these are vital. Mechanization must not deceive farmers. We need multi-utility, multipurpose quality. A farmer shouldn't need 10 planters for 10 crops. One planter should work for all.

Mechanization must be supported by business models. A machine used only for 15 days a year will sit idle for 350 days – that's not viable. We are discussing a national mechanization strategy and how India can feed the world. Our research and agriculture have such potential that we can feed all of Africa. In terms of quality and affordability, no one can beat us.

**Q** *Private sector activities in agriculture has increased – many startups are tech-focused, big companies are in seeds and chemicals. How do you see the relationship between public research institutions and private players?*

Public sector doesn't work for profit; the private sector must. If they don't profit, they collapse – and we understand that. But they must also consider how they contribute to national goals. CSR (Corporate Social Responsibility) must be properly channeled – currently, it's used as they please.

Second, they should assess where they can contribute. We're mapping this at the district level – how many people from public and private sectors are engaged in extension? Are they on the same wavelength or giving farmers conflicting information? Everyone has a role and responsibility.

As universities are opening up in various places, we are discussing what the mechanism for quality control should be. It is essential to ensure the quality of education and to make it relevant. **Rw**

## India Develops Genome-Edited Rice Varieties

The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has developed two genome-edited rice varieties—'DRR Dhan 100 (Kamala)' and 'Pusa DST Rice 1'. Developed using CRISPR-Cas technology, these varieties modify native genes without introducing foreign DNA, ensuring higher yields, early maturity, and resilience to drought, salinity, and alkalinity.

Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan called it a milestone in Indian agriculture, promising a second Green Revolution by improving farmers' incomes, conserving water, and

reducing greenhouse gas emissions.

Kamala, developed by ICAR-IIRR, matures 20 days earlier and yields 19% more grain than Samba Mahsuri. Pusa DST Rice 1, developed by IARI, boosts yield by 20-30% in drought- and salt-affected regions. Collectively, these could produce 4.5 million tonnes more rice over 5 lakh hectares, save 7.5 billion cubic meters of water, and reduce emissions by 20%.

ICAR Director General Dr. M.L. Jat confirmed that both varieties have completed All-India Coordinated Trials. The process of breeder seed,

foundation seed, and certified seed production is underway to make these varieties available to farmers. He called it a historic day in Indian agriculture and said many other genome-edited crop varieties will be released in the coming years.

After extensive debate over genome-edited crops, the Government of India has exempted genome-edited plants developed using SDN1 and SDN2 techniques from biosafety regulations. This has enabled the development of new plant varieties.



## NCOL Expands Organic Market Access

The National Cooperative Organics Limited (NCOL), established in 2023, aims to boost organic farming and ensure market access for farmers. Backed by NDDB, Amul, NCCF, and NCDC, NCOL has united 7,000 cooperatives, covering over 10 million farmers. Under the 'Bharat Organic' brand, it offers certified organic pulses, rice, flour, spices, and sweeteners. NCOL ensures product authenticity through QR codes linked to pesticide residue test reports. "We want to build trust in organic products by offering full transparency," said NCOL Managing Director Vipul Mittal. NCOL procures only certified organic produce, tested in NDDB labs. With support from Mother Dairy and major retail platforms, it aims to price organic products just 10–15% above conventional ones. NCOL has MoUs with 15 states and promotes organic farming.



## IFFCO reports 47% Growth in Nano-Fertilizer Sales

The Indian Farmers Fertiliser Cooperative (IFFCO) is set to report a profit before tax exceeding Rs 3,000 crore for the financial year 2024-25,

continuing its strong performance. Dr. U. S. Awasthi, Managing Director of IFFCO, credited this success to innovative agricultural technologies, strategic management, and increased adoption of nano-fertilizers. IFFCO dispatched 113.20 lakh tonnes of fertilizers during 2024-25.

Nano-fertilizer sales saw significant growth, with a 47% year-on-year rise. IFFCO Nano DAP sales surged by 118%, while Nano Urea Plus Liquid sales rose by 31%, totalling 365 lakh bottles sold. It exported over 5.09 lakh bottles to 40 countries, expanding its global footprint. Dr. Awasthi said, "I congratulate everyone for the commendable production and sales of IFFCO Nano Fertilisers. Our profit before tax exceeding Rs 3,000 crore reflects the knowledge and skills of our Strategic Management Group, leading to profitable operations and enhanced financial gains from foreign investments."





## IBETE 2025 Sets the Stage for Bioenergy Push

The curtain raiser for the 2nd India Bioenergy & Tech Expo (IBETE 2025) was held on April 23, 2025, in New Delhi, highlighting the theme “Transition to Net Zero: Need to Scale Up Bio-energy Initiatives.” The main expo will take place from September 24–26 at Yashobhoomi, New Delhi. Union Minister Nitin Gadkari emphasized the critical role of biofuels, green hydrogen, sustainable aviation fuel, and energy crops in India’s clean energy future. Former Minister Suresh Prabhu stressed the need for increased investment, strong policies, and innovation to position India as a global clean energy leader.

A key moment was the signing of an MoU between the Indian Federation of Green Energy (IFGE) and the National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd (NFCFSF) to promote sugarcane-based bioenergy. The inaugural issue of Bharat Bioenergy Horizon, a quarterly magazine by IFGE, was also launched during the event. The session featured discussions on sectors like CBG, ethanol, SAF, and biodiesel.

Over 300 stakeholders from government, industry, academia, and civil society participated. IBETE 2025 is expected to host 1000+ national and international delegates, serving as a vital platform to showcase green technologies, drive innovation, and build public-private partnerships to strengthen India’s bioenergy ecosystem.



## Sugar Production Slumps 18% on Lower Recovery

India’s sugar production for the 2024–25 season dropped 18% to 1257.40 lakh metric tonnes from 315.40 LMT last year as on 15 May, due to lower sugarcane availability, reduced recovery rates and red rot disease in Uttar Pradesh. Cane crushing fell 11%, while the average sugar recovery rate declined from 10.10% to 9.30%. The government fixed the FRP for 2025–26 at ₹355 per quintal based on a 10.25% recovery rate, but actual recovery was lower.

Key states saw sharp declines: UP (92.75 LMT), Maharashtra (80.95 LMT) and Karnataka (40.40 LMT). Ethanol diversion reached 32 LMT, below target, as sugar prices remained more profitable. Closing stocks are expected at 48-50 LMT, sufficient for domestic demand. A production rebound of 280-290 LMT is forecast for 2025–26, supported by a good monsoon and increased cane sowing.



## DAP Prices Touch \$720 in Global Market

The international price of DAP has surged to \$720 per tonne, raising concerns over increased subsidy burdens for the Indian government. However, domestic retail prices are unlikely to rise immediately, as the government will absorb the additional cost under its Nutrient Based Subsidy scheme. For Kharif 2025, the DAP subsidy has been increased to ₹27,799 per tonne, while the MRP remains ₹27,000 per tonne, making DAP imports unviable for fertilizer companies. Despite losses, companies continue imports to meet India’s annual demand of 10 million tonnes, with only 4.8 million tonnes produced domestically. India relies heavily on imports for DAP and its raw materials like phosphoric acid, currently priced at \$1,153 per tonne. The landed cost of imported DAP exceeds ₹65,000 per tonne, but companies are assured that extra costs will be reimbursed.





में सुधार के साथ-साथ एक्सपोर्ट मार्केट तक पहुंच बढ़ाने के लिए फार्म से पोर्ट तक ढांचागत सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर देना होगा। बेहतर कृषि उत्पादन प्रक्रिया (गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज यानी जीएपी) जैसे कई मोर्चे हैं जहां व्यापक सुधार की दरकार है।

अहम बात यह है कि ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसलों और बयानों के चलते उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है, भारत के कृषि निर्यात ने बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत से कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात वर्ष 2024-25 के दौरान 6.47 फीसदी बढ़कर 51.91 अरब डॉलर हो गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान चावल निर्यात का है जो 12.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसमें बासमती निर्यात की हिस्सेदारी करीब 6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है।

चावल के बाद सबसे ज्यादा 7.4 अरब डॉलर का निर्यात मरीन उत्पादों का होता है। मसालों का निर्यात 4.84 फीसदी बढ़कर 4.45 अरब डॉलर हो गया है। बफैलो मीट के निर्यात में 8.57 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 4 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। प्रोसेस्ड फूड का निर्यात करीब 2 फीसदी की वृद्धि के साथ 1.68 अरब डॉलर रहा है जबकि ताजे फलों का निर्यात भी करीब 2 फीसदी बढ़कर 1.17 अरब डॉलर हो गया है।

प्रोसेस्ड फ्रूट्स व जूस का निर्यात करीब 6 फीसदी बढ़कर 1 अरब डॉलर से अधिक रहा है। तंबाकू निर्यात में इस साल 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और यह 1.5 अरब के आसपास है। ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात में 35 फीसदी और डेयरी प्रोडक्ट्स में 54 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

देश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत स्थापित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के दायरे में आने वाली प्रमुख वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2024-25 में 11 फीसदी बढ़कर 27.90 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश के कृषि निर्यात में दर्ज की गई बढ़ोतरी से वर्ष 2030 तक कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की संभावनाओं को बल मिला है। हालांकि, यह राह इतनी आसान नहीं है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के चेयरमैन

अभिषेक देव ने *रूरल वॉयस* को बताया कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से लेकर, निर्यात सुविधाएं बढ़ाने और किसानों को निर्यात बाजारों से जुड़े जैसे कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में बनारस एक सक्सेस स्टोरी है।

अभिषेक देव बताते हैं कि कुछ साल पहले तक बनारस से कोई कृषि निर्यात नहीं होता था। लेकिन चार साल के भीतर बनारस से हजारों टन फल व सब्जियों का कई देशों को निर्यात होने लगा है। चंदौली का काला चावल, बनारसी लंगड़ा आम और आसपास के जिलों से फल-सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनारस को एग्री एक्सपोर्ट हब के तौर पर विकसित किया गया है। इसके लिए बनारस एयरपोर्ट पर कस्टम, एयर कार्गो और अन्य

### अमृतसर एयरपोर्ट को आरए3 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन का दर्जा देकर निर्यात से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अमृतसर से एयर कार्गो के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका लाभ निर्यातकों और किसानों को भी मिलेगा।

निर्यात सुविधाएं तैयार की गईं। अभिषेक देव ने बताया कि अब बनारस की तर्ज पर अमृतसर एयरपोर्ट को आरए3 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन का दर्जा देकर निर्यात से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अमृतसर से एयर कार्गो के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका लाभ निर्यातकों और किसानों को भी मिलेगा।

फल-सब्जियों और कई कृषि उपजों के जल्द खराब होने के कारण अभी ये उत्पाद देश के भीतर भी दूर तक नहीं पहुंच पाते हैं। वर्ष 2024-25 के आम बजट में एयर कार्गो वेयरहाउसिंग की सुविधा बढ़ाने की घोषणा की गई है। इससे निर्यात और घरेलू व्यापार में वृद्धि होगी। कार्गो स्क्रीनिंग और कस्टम प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने से निर्यात की राह आसान हो सकती है।

### एक लाख करोड़ का चावल निर्यात

कृषि उपजों का निर्यात किसानों की आमदनी बढ़ाने का अहम जरिया है क्योंकि वैश्विक बाजार मिलने से उपज का बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है जिसका लाभ किसानों तक भी पहुंचता है। लेकिन इसके लिए उपज की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरना जरूरी है।

कई भारतीय उत्पाद जैसे बासमती चावल अपनी विशेष खूबियों के चलते विश्व बाजार में पैठ बना चुके हैं। कृषि निर्यात में चावल एक बेहतरीन उदाहरण है। वर्ष 2024-25 में भारत से चावल निर्यात पिछले साल के 163.58 लाख टन से 23.48 फीसदी बढ़कर 202 लाख टन तक पहुंच गया है जिसका मूल्य 12.47 अरब डॉलर यानी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है। देश के कुल कृषि निर्यात में करीब 25 फीसदी हिस्सेदारी अकेले चावल की है। अकेले बासमती चावल का निर्यात 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होता है।

इससे अन्य उपजों के निर्यात की संभावनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एक कृषि उपज का निर्यात 12 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच सकता है तो देश की सभी कृषि वस्तुओं का निर्यात 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना कोई असंभव काम नहीं है।

### क्वालिटी और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड

कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए क्वालिटी और फूड सेफ्टी से जुड़े मानकों पर खरा उतरना जरूरी है। खेत में बीज से लेकर फसल कटाई, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, हर लेवल पर अंतरराष्ट्रीय मानकों और सरकारी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। अमेरिका में निर्यात के लिए यूएस एफडीए और यूरोप के लिए ईयू के स्टैंडर्ड हैं। इसके अलावा अलग-अलग देशों और आयातकों के अपने मानक भी होते हैं।

उत्पादों की गुणवत्ता के अलावा सेनेटरी व फाइटोसेनेटरी स्टैंडर्ड, पेस्टिसाइड रेसिड्यू और ट्रेसिबिलिटी जैसे मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं। इसके लिए किसानों को खेत में बीज से लेकर उर्वरक, फसल सुरक्षा और उत्पादन की प्रक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड का ध्यान रखना पड़ता है। इन मसलों पर किसानों और निर्यातकों को जागरूक करना एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। थोड़ी-सी चूक भी ग्लोबल मार्केट में हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अमेरिका को निर्यात हुए आम के कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने का मामला एक ताजा उदाहरण है।

पिछले दिनों अमेरिका में भारतीय आम की 12 खेप रिजेक्ट होने की खबर आई। इसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी और प्रक्रियागत खामियों को वजह बताया गया, जिससे निर्यातकों को 4 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। निर्यातकों का कहना है कि उन्हें इरिडिएशन प्लान्ट की गलती का खामियाज उठाना पड़ा क्योंकि नवी मुंबई स्थित इरिडिएशन सेंटर पर डेटा दर्ज करने में गलती हुई थी। बहरहाल, मामले की जांच-पड़ताल जारी है।

इस तरह के मामले कृषि निर्यात से जुड़ी पेंचिदगियों और चुनौतियों को उजागर करते हैं। खासतौर पर खाद्य वस्तुओं के निर्यात से पहले उन्हें सघन जांच, कस्टम क्लियरेंस और इरिडिएशन जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। जिन देशों को निर्यात करना है, उनके नियम-कायदों और मानकों का पालन करना होता है।

निर्यात की इन चुनौतियों के कारण ही दुनिया का लगभग 43 फीसदी आम उत्पादन करने वाला भारत सालाना आम उत्पादन का एक फीसदी आम भी निर्यात नहीं कर पाता है। जबकि देश में आम की 14 किस्मों को विशेष भौगोलिक पहचान (GI) प्राप्त है और भारत के आम दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में भारत से आम और मैंगो पल्प का निर्यात बढ़ा है। वर्ष 2024 में भारत से 32 हजार टन आम और 60 हजार टन मैंगो पल्प का निर्यात हुआ था। यूपी जैसे प्रमुख आम उत्पादक राज्य से आम निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्पादों की गुणवत्ता, निर्यात सुविधाओं के विस्तार और मानकों पर खरा उतरने को लेकर उठाया जा रहे कदमों पर एपीडा चेयरमैन का कहना है कि हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) पूसा के वैज्ञानिकों, एफएसएसएआई और निर्यातकों के साथ मिलकर इस मोर्चे पर काम कर रहे हैं। राज्यों की भी यहां अहम भूमिका है। बासमती के मामले में राज्य सरकारों ने कई पेस्टिसाइड प्रतिबंधित किये। लेकिन निर्यातकों को भी सजग रहने की आवश्यकता है।

### मूल्यवर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी

निर्यात में बढ़ोतरी के लिए हमें मूल्यवर्धन को प्राथमिकता देनी है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के सचिव सुब्रत गुप्ता का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप

बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी मानकों को विकसित करने और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न विभागों और उद्योग के बीच अधिक तालमेल की आवश्यकता है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक डॉ. अजय सहाय बताते हैं कि भारत के कुल कृषि निर्यात में कच्चे माल की हिस्सेदारी लगभग 50 फीसदी है जबकि प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 30 फीसदी के आसपास है। कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग पर जोर देने की आवश्यकता है। निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने होंगे।

### कई मंत्रालयों, विभागों की भूमिका

दरअसल, कृषि निर्यात का मामला कई मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं से जुड़ा है। कृषि उत्पादन कृषि मंत्रालय के दायरे में आता है जबकि कृषि निर्यात में वाणिज्य मंत्रालय की भूमिका अहम है। खाद्यान्न और कृषि उपज की सरकारी खरीद, उपलब्धता और भंडारण की नीतियों में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का दखल रहता है, जबकि फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी अहम योजनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के जरिए चलाई जाती हैं। इसी तरह डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स के मामले में पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की अहम भूमिका है। जबकि कस्टम से जुड़े मामले वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं।

### जीआई उत्पादों से निर्यात संवर्धन

भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग मिलने से विभिन्न कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर

**अलग एचएस कोड से जीआई-टैग वाले चावल के निर्यात में मदद मिलेगी। खासकर जब चावल की सामान्य किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाता है, तब भी इनका निर्यात संभव होगा। साथ ही ट्रेसेबिलिटी और डेटा प्राप्त करने में भी आसानी होगी।**



पहचान दिलाने और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने जीआई टैग वाली चावल किस्मों के लिए अलग से एचएस (Harmonised System) कोड शुरू किया है। भारत में चावल की 29 किस्मों को जीआई टैग मिला है जिनमें कालानमक, गोबिंदभोग, नवारा, पोक्कली, वायनाड जीरकासला, वायनाड गंधकसाला, कटारनी और चोकुवा चावल की किस्में शामिल हैं।

अलग एचएस कोड से जीआई-टैग वाले चावल के निर्यात में मदद मिलेगी। खासकर जब चावल की सामान्य किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाता है, तब भी इनका निर्यात संभव होगा। साथ ही ट्रेसेबिलिटी और डेटा प्राप्त करने में भी आसानी होगी।

जीआई टैग वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के दिशा में कदम बढ़ाते हुए एपीडा ने सिक्किम से डल्ले मिर्च के निर्यात की शुरुआत कराई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बांग्लादेश को 30 टन गुड़ के निर्यात किया गया। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुड़ निर्यात की शुरुआत की गई है। पश्चिमी यूपी का गुड़ विशिष्ट भौगोलिक पहचान (जीआई) वाला उत्पाद है। एपीडा बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन के जरिए मुजफ्फरनगर क्षेत्र से गुड़ निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। निर्यात का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए एफपीओ





को माध्यम बनाया जा रहा है।

एपीडा के सचिव डॉ. सुधांशु ने बताया कि पश्चिमी यूपी के कई एफपीओ गुड़, गुड़ उत्पादों, बासमती चावल और दालों के निर्यात में जुटे हैं। उन्हें एपीडा की ओर से प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है, ताकि किसानों के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में जगह बना सकें। 2023 और 2024 में पश्चिमी यूपी से एफपीओ के जरिए लेबनान और ओमान को बासमती चावल का निर्यात हुआ था।

### इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात सुविधाएं

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैक हाउस, पेरिशेबल कार्गो, ऑक्शन सेंटर, एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इरेडिएशन सेंटर आदि बुनियादी ढांचे और निर्यात सुविधाओं को विकसित करना जरूरी है। एपीडा कई योजनाओं के माध्यम से इन बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन दे रहा है।

कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे बिजली आपूर्ति, सिंचाई प्रणाली और परिवहन नेटवर्क में पर्याप्त निवेश उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ बाजार पहुंच को बढ़ा सकता है। उत्पादकता में सुधार के साथ ही फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना भी जरूरी है। इसमें नई तकनीक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के पूर्व निदेशक डॉ. एन.सी. साहा बताते हैं कि खाद्य वस्तुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए

पैकेजिंग टेक्नोलॉजी बहुत कारगर साबित हो रही है। पैकेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से लीची की शेल्फ लाइफ 12 से 15 दिन तक बढ़ाने में मदद मिली है। अब ऐसे तकनीक भी विकसित हो चुकी हैं जिनसे लीची जैसे फलों की शेल्फ लाइफ 60 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। निर्यातक पैकेजिंग तकनीक की मदद से निर्यात की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से भी पैकेजिंग तकनीक अपनाने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

### किसान हित और निर्यात नीतियां

सरकार को महंगाई काबू में रखने और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ निर्यात बढ़ाने के बीच संतुलन कायम करना होता है। ऐसे में कई बार जब किसानों को निर्यात बाजार के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। वर्ष 2023 में प्याज और गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगी पाबंदियों का खामियाजा देश के कृष निर्यात और किसानों को उठाना पड़ा था। यही स्थिति गेहूं के मामले में देखने को मिल रही है।

पिछले दो साल से कृषि मंत्रालय की तरफ से देश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के दावे किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि 2024-25 में गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 11.54 करोड़ टन होगा। इस साल गेहूं की सरकारी खरीद पिछले साल से करीब 11 फीसदी अधिक रही है। फिर भी गेहूं के निर्यात पर लगी रोक जारी है।

गौरतलब है कि उत्पादन में गिरावट को

देखते हुए भारत सरकार ने मई 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और महंगाई काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया गया। प्याज के मामले में भी ऐसा ही हुआ था जब 2023 में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बन गया था।

ऐसे में कृषि उत्पादन के आंकड़ों पर भी सवाल उठते हैं। क्योंकि पिछले साल 11.32 करोड़ टन गेहूं के बंपर उत्पादन के बावजूद सरकारी खरीद 266 लाख टन रही थी और निर्यात पर रोक के बाद भी घरेलू बाजार में गेहूं के दाम कम नहीं हुए।

वास्तव में, कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा विभिन्न कारणों से निर्यात पर पाबंदियां लगाकर किसानों को बेहतर दाम से वंचित रखने की नीति पर भी विचार करने की जरूरत है। किसानों को उपज का बेहतर दाम दिलाने में कृषि निर्यात अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा और कृषि व्यापार के बीच सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने, उपज की बर्बादी कम करने, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर यह यह सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

### उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने की दरकार

कृषि उत्पादन के मामले में भारत अभी विकसित देशों के साथ ही चीन से भी काफी पीछे है। ऐसे में उत्पादकता नहीं बढ़ने से हमारे उत्पादों का प्रतिस्पर्धी होने की भी चुनौती बनी रहती है। हालांकि फलों के मामले में हमने अंगूर, केला और अनार जैसे उत्पादों के मामले में बहुत तेजी से तरक्की की है। लेकिन इसे दूसरे उत्पादों में भी हासिल करना है जो 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने की अहम कड़ी है।

निर्यात के लिए सरकार ने 2018 में नई निर्यात नीति के समय ही इस लक्ष्य की बढ़ने का कदम उठाया था, लेकिन अभी हम इस लक्ष्य से काफी दूर हैं। हालांकि 50 अरब डॉलर का स्तर एक टिकाऊ स्तर बन गया है। ऐसे में अब कदम इसे दोगुना करने की ओर बढ़ चले हैं और देश के किसानों की बेहतर आय के साथ खेती को अधिक आकर्षक कारोबार बनाने के लिए भी यह अनिवार्य शर्त है कि कृषि उत्पादों से किसानों को अधिक आय हो जिसमें निर्यात की भूमिका बड़ी है। Ru





# 2030 तक एपीडा उत्पादों का निर्यात 55 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य: **अभिषेक देव**

भारत ने 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। अभी निर्यात इसका लगभग आधा है। अगले पांच वर्षों में कृषि निर्यात दोगुना करने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने कई रणनीति बनाई हैं। एपीडा चेयरमैन **अभिषेक देव** ने **रूरल वर्ल्ड** के एडिटर-इन-चीफ **हरवीर सिंह** और एक्जिक्यूटिव एडिटर **अजीत सिंह** के साथ एक एक्स्क्लूसिव इंटरव्यू में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्यात में तेज वृद्धि के लिए उन बाजारों और उत्पादों पर फोकस किया जा रहा है जो अधिक मूल्य दिला सकते हैं। बातचीत के मुख्य अंश-

■ भारत ने कृषि निर्यात में 100 अरब डॉलर





अभिषेक देव  
चेयरमैन, एपीडा

फोटो: रुरल वर्ल्ड

**का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एपीडा क्या रणनीति अपना रहा है?**

कृषि निर्यात में 100 अरब डॉलर के व्यापक लक्ष्य के मद्देनजर और कृषि निर्यात बास्केट में एपीडा की हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए, हमने 2030 तक अपने अनुसूचित उत्पादों का 55 अरब डॉलर से अधिक निर्यात का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एपीडा कई रणनीतिक पहलुओं पर कार्य कर रहा है। प्रमुख और अधिक संभावना वाले उत्पादों पर केंद्रित निर्यात संवर्धन पर जोर दिया जा रहा है। यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, ओशेनिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े लेकिन कम निर्यात वाले बाजारों में विविधीकरण और गहरी पैठ बनाने पर विशेष

**वर्ष 2024-25 में भारत का कृषि निर्यात प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। एपीडा के अनुसूचित उत्पादों का निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर, 27.90 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें प्रमुख योगदान गैर-बासमती चावल और बासमती चावल का है।**

ध्यान दिया जा रहा है।

इस लक्ष्य की दिशा में एपीडा ने इक्रियर को नॉलेज पार्टनर के रूप में जोड़ा है, जो 20 प्रमुख और अधिक संभावना वाले उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विश्लेषण कर रहा है। क्षेत्र एवं देश के हिसाब से निर्यात योजनाएं तैयार की जा रही हैं। एपीडा उत्पादों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग को बेहतर बनाने पर भी कार्य कर रहा है ताकि उनकी मांग और निर्यात मूल्य में वृद्धि हो सके। जल्दी नष्ट होने वाले उत्पादों के किफायती और सस्टेनेबल समुद्री परिवहन के लिए प्रोटोकॉल विकसित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एपीडा में एक मार्केट इंटेलिजेंस सेल की स्थापना की गई है, जिसमें क्रिसिल को नॉलेज पार्टनर के रूप में जोड़ा गया है। यह सेल कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों पर नियमित जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है, जिससे सभी हितधारकों को लाभ हो सके।

**आने वाले समय में किस सेक्टर या प्रोडक्ट में संभावना है जहां निर्यात अधिक बढ़ेगा?**

एपीडा ने विभिन्न क्षेत्रों में अधिक संभावना वाले उत्पाद श्रेणियों की पहचान की है, जो कृषि निर्यात के अगले चरण को गति दे सकते हैं। हमारे प्रमुख फोकस क्षेत्रों में चावल (बासमती और गैर-बासमती), केला, आम, अनार, अंगूर, अनानास जैसे ताजे फल शामिल हैं। इनकी वैश्विक बाजारों में उल्लेखनीय मांग रही है। सब्जियों में आलू, हरी मिर्च, अदरक और भिंडी को प्रमुख उत्पादों के रूप में चिन्हित

किया गया है। एपीडा प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित खाद्य पदार्थों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग को भी देख रहा है। इनमें मूंगफली, मखाना, साँस, जूस, पापड़, पास्ता, बिस्किट, मादक पेय और मिठाइयां जैसे उत्पाद अधिक संभावनाओं वाले माने जा रहे हैं। प्राकृतिक शहद, दुग्ध उत्पाद (घी, पनीर) और अंडे जैसे उत्पादों से भी और उम्मीदें हैं। इन फोकस उत्पादों का कुल निर्यात वर्ष 2030 तक 40 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।

**आप 100 अरब डॉलर निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ देखते हैं?**

कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं- कोल्डचेन नेटवर्क में इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी, खेत स्तर पर प्रसंस्करण की कमी, आपूर्ति श्रृंखला की कमी। इन वजहों से उपज नष्ट होते हैं और निर्यात गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। रेड सी संकट और मध्य पूर्व संघर्ष के कारण हवाई और समुद्री मार्गों से परिवहन लागत में वृद्धि हुई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों से बंदरगाहों तक परिवहन लागत भी अधिक आती है। एक और चुनौती किसानों में अच्छी कृषि प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी का अभाव है, जिससे उत्पादों में कीटनाशकों के अवशेष पाए जाते हैं और गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।

**भारत का 2024-25 में कृषि निर्यात प्रदर्शन कैसा रहा? प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रही?**

वर्ष 2024-25 में भारत का कृषि निर्यात प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। एपीडा के अनुसूचित उत्पादों का निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर, 27.90 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें प्रमुख योगदान गैर-बासमती चावल (6.5 अरब डॉलर), बासमती चावल (5.9 अरब डॉलर), बफेलो मीट (4 अरब डॉलर), ताजे फल और सब्जियाँ (2.06 अरब डॉलर) जैसे उत्पादों का रहा। इसके अलावा अनाज-आधारित प्रसंस्कृत उत्पाद, दालें, दुग्ध उत्पाद, प्रसंस्कृत सब्जियाँ, फलों के प्रसंस्कृत रस, कोको उत्पाद आदि के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह प्रदर्शन भारत के प्रसंस्कृत और अधिक मूल्य वाले कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग में वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा जैविक उत्पादों का निर्यात इस वर्ष 35% बढ़ा है। इसमें अनाज, चाय, प्रसंस्कृत उत्पाद, एसशियल ऑयल, आयुर्वेदिक और औषधीय उत्पाद जैसी सभी प्रमुख श्रेणियों में अच्छी वृद्धि देखी गई।

**एपीडा पारंपरिक जगहों से अलग कृषि निर्यात बाजारों में कैसे विविधता ला रहा है?**



## खाद्य प्रसंस्करण करने वालों और निर्यातकों को वैश्विक बाजार में बेहतर स्वीकृति दिलाने के मकसद से एपीडा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेशन में भी उनकी मदद कर रहा है। एपीडा के ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को अनेक देशों ने सराहा है।



भारत का कृषि निर्यात पारंपरिक रूप से मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र तक सीमित रहा है। लेकिन यूरोप, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, चीन जैसे बाजारों में अब भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। एपीडा भारतीय दूतावासों के माध्यम से इन बाजारों से प्रतिक्रिया प्राप्त करके और निर्यातकों के साथ रणनीति पर चर्चा कर इन बाजारों में प्रवेश की योजना बना रहा है। भारत के कृषि उत्पादों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के मकसद से एपीडा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग ले रहा है। जैसे ग्लूड (दुबई), बायोफैक (जर्मनी), सियाल (पेरिस), एनूगा (जर्मनी), नैचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट (अमेरिका), वर्ल्ड फूड इंडिया, इंडस फूड और आहार। इसके अतिरिक्त, एपीडा व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के आवागमन को प्रोत्साहित करता है और प्रमुख राज्यों और पूर्वोत्तर में नियमित रूप से बायर-सेलर मीट का आयोजन करता है, ताकि भारतीय निर्यातकों को वैश्विक आयातकों से जोड़ा जा सके।

**प्र** कुछ बाजारों में उत्पादों की गुणवत्ता प्रमुख मुद्दा है। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एपीडा किसानों और निर्यातकों को किस प्रकार सहायता कर रहा है?

एपीडा खेत स्तर पर गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज (जीएपी) को अपनाने और उनके सर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उत्पाद आयातक देशों की सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। एपीडा किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ग्लोबल जीएपी सर्टिफिकेट प्राप्त करने में भी सहयोग करता है, जिससे इन उत्पादों की यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों के बाजारों में मार्केटिंग क्षमता बढ़ती है।

खाद्य प्रसंस्करण करने वालों और निर्यातकों को वैश्विक बाजार में बेहतर स्वीकृति दिलाने के मकसद से एपीडा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेशन में भी उनकी मदद कर रहा है। एपीडा ने अंगूर, मूंगफली, ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को विकसित और लागू किया है, जिसे आयातक देशों ने सराहा भी है। निर्यात वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एपीडा ने देश में 117 प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है। उन्हें एनएबीएल की तरफ से आईएसओ-17025 मान्यता प्राप्त है। ये प्रयोगशालाएं चावल जैसे एपीडा द्वारा अनुसूचित उत्पादों के लिए

परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं देती हैं।

**प्र** क्या वैश्विक बाजारों में जैविक और जीआई टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है?

एपीडा वैश्विक स्तर पर भारत के कृषि निर्यात को विस्तार देने की रणनीति के तहत जैविक और जीआई-टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देता है। जैविक उत्पादों के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) को हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर संशोधित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और न्यूजीलैंड के साथ इस सिलसिले में समझौते पर कार्य जारी है। जैविक निर्यात प्रमोशन के लिए एक समर्पित पोर्टल लांच किया गया है। जर्मनी के बायोफैक, अमेरिका के नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो वेस्ट और दुबई के ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट एक्सपो जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी बढ़ाई गई है। एपीडा ने 'ब्रांड इंडिया' अभियान के अंतर्गत भारतीय जैविक उत्पादों की वैश्विक पहचान को सशक्त करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) के साथ सहयोग भी किया है।

अब तक कुल 242 जीआई उत्पाद पंजीकृत हो चुके हैं, जो भारत की विविध कृषि और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। प्रमुख जीआई निर्यात उत्पादों में बासमती चावल, जीआई किस्मों के आम, केले, अनानास, प्याज, सांगली अंगूर/किशमिश,

पूर्वोत्तर के उत्पादों में असम का जोहा चावल, काला चावल (चक-हाओ), नगा मिर्च, मिथिला का मखाना एवं इनसे बने प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं। इनका निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, ईरान, इराक, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान आदि प्रमुख आयातक देशों को किया गया है।

**प्र** वैश्विक व्यापार में तनाव की स्थिति और अमेरिकी टैरिफ के संदर्भ में भारतीय कृषि निर्यात के लिए क्या चुनौतियां और अवसर हैं?

वैश्विक व्यापारिक तनाव और उभरते हालातों के बावजूद अपनी विशिष्ट और अलग स्वाद प्रोफाइल के कारण भारतीय कृषि निर्यात मजबूत बना रहेगा।

**प्र** निर्यात में तेजी लाने के लिए नीति, इन्फ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय प्रोत्साहन के मोर्चे पर सरकार की तरफ से किन कदमों की आवश्यकता है?

भारतीय कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है:

**प्रमुख उत्पादों पर ध्यान:** केले, बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, बफेलो मीट, काजू, जैविक उत्पाद जैसे 20 से अधिक उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला पर केंद्रित एक्सपोर्ट प्रमोशन।

**ब्रांडिंग को बढ़ावा:** प्रमुख बाजारों में ब्रांडिंग और प्रचार। बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, ताजे फल, जैविक उत्पाद के लिए प्रचार की शुरुआत।

**लॉजिस्टिक्स की बाधाएं दूर करना:** जल्दी नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए समुद्री परिवहन प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन और उन्हें मुख्यधारा में लाना।

**उत्पाद गुणवत्ता में सुधार:** वैश्विक जीएपी सर्टिफिकेशन, उत्पादों की ट्रेसेबिलिटी।

**कोल्डचेन नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती:** विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय।

सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी अवरोधों को दूर करना और उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना।

**प्र** बेहतर बाजार पहुंच के लिए एपीडा भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के साथ अपने प्रयासों को कैसे जोड़ कर रहा है?

एपीडा यह काम सक्रिय रूप से कर रहा है ताकि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाया जा सके। ट्रेड वार्ताकारों के साथ मिलकर उन उत्पादों और टैरिफ लाइन की पहचान की जा रही जिनमें एफटीए से अधिक



## कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात की तुलना [मुख्य कमोडिटी का विश्लेषण]

एपीडा के दायरे वाले प्रोडक्ट	वैल्यू [मिलियन डॉलर में]			एपीडा के दायरे वाले प्रोडक्ट	वैल्यू [मिलियन डॉलर में]		
	2023-24	2024-25	वृद्धि दर (%)		2023-24	2024-25	वृद्धि दर (%)
गैर-बासमती चावल	4573	6528	43%	काजू	339	338	0%
बासमती चावल	5843	5944	2%	कोकोआ उत्पाद	184	296	61%
बफेलो मीट	3743	4061	8%	पोल्ट्री उत्पाद	185	169	-9%
प्रसंस्कृत उत्पाद	1654	1680	2%	फल-सब्जी बीज	133	158	19%
ताजी सब्जियां	891	894	0%	फ्लोरीकल्चर	87	89	2%
प्रसंस्कृत फल एवं जूस	972	1029	6%	भेंड़/बकरा मीट	78	85	9%
अनाज उत्पाद	842	934	11%	पशु केसिंग	48	60	24%
ताजे फल	1147	1171	2%	काजू नट-शेल तरल	9	7	-23%
मूंगफली	862	795	-8%	प्रोसेस्ड मीट	3	1	-52%
अन्य अनाज	518	271	-48%	अन्य मीट	1	0	-74%
दालें	645	778	21%	योग	24809	27707	12%
प्रसंस्कृत सब्जियां	652	777	19%	गेहूं	57	2	-96%
ग्वारगम	542	569	5%	मिल उत्पाद	173	192	11%
डेयरी उत्पाद	469	721	54%	योग	230	194	-16%
अल्कोहल वाले पेय	389	353	-9%	कुल योग	25039	27901	11%

स्रोत: डीजीसीआईएस, प्रमुख कमोडिटी

नोट 1: विविध तैयारियों की प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं - मक्का (कॉर्न) स्टार्च, आलू के फ्लेक्स, ग्रेन्यूल्स और पैलेट्स, प्रोटीन कंसंट्रेट्स और टेक्सचर्ड प्रोटीन पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक कंसंट्रेट, मिश्रित मसाले और मिश्रित सीजनिंग, पान मसाला, शर्करा युक्त एरेटेड वाटर।

नोट 2: अनाज उत्पादों में शामिल हैं - मीठे बिस्किट, पापड़, ब्रेड, पेस्ट्री, चावल के पापड़ और इसी प्रकार के उत्पाद, अन्यथा उल्लेखित नहीं किए गए बिस्किट, तथा अनाज या अनाज उत्पादों को फुलाकर या भूनकर तैयार किए गए खाद्य पदार्थ।

लाभ हो सकता है।

**एपीडा निर्यात वृद्धि को सस्टेनेबिलिटी से संबंधित विताओं जैसे कीटनाशकों का उपयोग, कार्बन उत्सर्जन और जैव विविधता के साथ कैसे संतुलित करता है?**

निर्यात वृद्धि को सस्टेनेबिलिटी के साथ संतुलित करने के लिए एपीडा कृषि निर्यात मूल्य श्रृंखला में पर्यावरण हितैषी प्रथाओं को बढ़ावा दे रहा है। कीटनाशक अवशेषों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए खेत स्तर पर जीएपी को अपनाने और प्रमाणित करने को प्रोत्साहित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद आयातक देशों की सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी आवश्यकताओं का पालन करें।

**एपीडा एग्री-स्टार्टअप, एफपीओ/एफपीसी और सहकारी संस्थाओं को निर्यात प्रतिस्पर्धा**

**बढ़ाने में किस प्रकार मदद कर रहा है?**

इसके लिए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं: **क्लस्टर-आधारित निर्यात संवर्धन:** एपीडा ने अधिक संभावना वाले कृषि खाद्य क्लस्टरों की पहचान की है। यह उत्पादकता, गुणवत्ता और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए लक्षित हस्तक्षेप करता है।

**टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन:** ट्रेसिबिलिटी, इनोवेटिव पैकेजिंग और कोल्डचेन लॉजिस्टिक्स जैसी उन्नत तकनीक को अपनाने में सहयोग।

**विभागों के साथ सहयोग:** नाबार्ड, एसएफएसी और नाफेड के साथ एमओयू के माध्यम से एफपीओ/सहकारी संस्थाओं के लिए कौशल विकास और बाजार पहुंच को मजबूत करना।

**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** 2024-25 में 879 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें

78,264 हितधारकों को निर्यात प्रक्रिया, सर्टिफिकेशन और श्रेष्ठ प्रथाओं के लिए प्रशिक्षित किया गया।

**स्टार्टअप और निर्यात समर्थन:** 500

स्टार्टअप का मूल्यांकन किया जाएगा, इनमें से बेहतरीन 25 स्टार्टअप को निर्यात और निवेश के लिए तैयार करने के मकसद से सहायता दी जाएगी।

**वित्तीय सहायता योजना:** इसमें तीन तरह से मदद- निर्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर (पैकहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयां), क्वालिटी डेवलपमेंट (सर्टिफिकेशन, फूड सेफ्टी, ट्रेसिबिलिटी) और मार्केट डेवलपमेंट (व्यापार मेले, बायर-सेलर मीट, प्रमोशन)।

इन पहलों का उद्देश्य किसान समूहों और स्टार्टअप को निर्यात में सफलता हासिल के लिए सशक्त बनाना है। **Rw**

# कृषि निर्यात का हब बनने में भारत की चुनौतियां

कृषि क्षेत्र में सरकार को निवेश बढ़ाने की जरूरत ताकि प्रमुख कमोडिटी के उत्पादन को निरंतर बढ़ावा मिल सके



**डॉ. बिश्वजीत धर**

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर और काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट में प्रतिष्ठित प्रोफेसर

**दि** संबर् 2018 में सरकार ने पहली बार एक महत्वाकांक्षी कृषि निर्यात नीति की घोषणा की थी। उससे पहले भारत की कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। निर्यात नीति इस उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती थी। कृषि नीति में यह बदलाव लंबे समय से अपेक्षित था, क्योंकि हरित क्रांति की रणनीति ने भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था और आयात पर निर्भरता की स्थिति दोबारा लौटने की कोई आशंका नहीं रह गई थी।

कृषि निर्यात नीति कई मायने में महत्वपूर्ण कही जा सकती है। पहला, इसे निर्यातोन्मुखी उत्पादन पर केंद्रित करके तैयार किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाना था। दूसरा, इस नीति ने किसान केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसका उद्देश्य अधिक मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों की आय में सुधार करना था, ताकि वैल्यू चेन में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। तीसरा, इस नीति ने एक किसान उन्मुख रणनीति की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

करने के साथ भारत को विश्व का एक प्रमुख कृषि निर्यातक बनाने के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस नीति का एक और उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देना था, जिससे भारत के कृषि निर्यात बास्केट में मूल्य संवर्धित और प्रसंस्कृत उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ सके तथा भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर सके।

अपने व्यापक उद्देश्यों के अलावा कृषि निर्यात नीति में कई विशिष्ट लक्ष्य भी शामिल थे। पहला, विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करते हुए इसे वैश्विक मूल्य श्रृंखला से शीघ्र जोड़ना और भारत के कृषि निर्यात को 2022 तक दोगुना कर 60 अरब डॉलर तक पहुंचाना। इससे किसानों को विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ मिलता। सरकार ने 2016 में किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया था और कृषि निर्यात को बढ़ावा देना इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक माना गया था। दूसरा लक्ष्य निर्यात बास्केट तथा गंतव्यों में विविधता लाना और अधिक मूल्य वाले एवं मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना था। इसमें जल्दी नष्ट होने वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाना था। तीसरा लक्ष्य था एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराना, जो बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करे, निर्यात बाधाओं को दूर करे और सैनिटरी तथा फाइटो-सैनिटरी मुद्दों से निपटे। ये सैनिटरी तथा फाइटो-सैनिटरी मुद्दे मानव, पशु, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य मानकों से संबंधित हैं तथा वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

## विवादास्पद कृषि सुधार

2020 में पेश विवादास्पद कृषि सुधार भारत को कृषि निर्यात केंद्र में बदलने की दिशा में एक और कदम था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 ने कृषि उपज बाजार को विनियमन मुक्त कर दिया और इससे निर्यात को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा की गई थी। इस अधिनियम में संशोधन कर बाजार को रेगुलेशन से मुक्त किया गया ताकि उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता दी जा

कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात			
साल	कृषि और संबद्ध उत्पाद [अरब डॉलर]	कुल निर्यात [अरब डॉलर]	कुल निर्यात में कृषि और संबद्ध उत्पादों का हिस्सा [%]
2017-18	37.0	303.5	12.2
2018-19	37.1	330.1	11.2
2020-21	40.0	291.8	13.7
2021-22	47.4	422.0	11.2
2023-24 (अप्रैल-फरवरी)	42.9	395.4	10.8
2024-25 (अप्रैल-फरवरी)	46.0	395.4	11.6

स्रोत: वाणिज्य विभाग



सके, बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ उठाया जा सके और कृषि में निजी क्षेत्र तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। सरकार का तर्क था कि भारत अब अधिकांश कृषि उपज में अधिशेष की स्थिति में है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार के मुताबिक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लगाए गए भंडारण प्रतिबंधों ने उद्यमशीलता की भावना को कमजोर कर दिया था।

2022 में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जिलों को निर्यात हब के रूप में स्थापित करने की पहल की। इसका उद्देश्य देश के 733 जिलों में कृषि और अन्य ऐसे उत्पादों की पहचान करना था जिनमें निर्यात की संभावनाएं हैं।

### इस पहल के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं जो निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित हैं:

- (i) भारत के निर्यात गंतव्य वाले देशों में विविधता लाना और अधिक मूल्य व मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। इसमें जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुओं पर विशेष ध्यान देना शामिल है।
- (ii) नए, देसी, जैविक, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- (iii) किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने योग्य बनाना।

2023 की विदेश व्यापार नीति ने इस जिला निर्यात हब पहल को औपचारिक वैधता प्रदान की। इसके लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई ताकि देश के चिन्हित जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित किया जा सके। 2025 में 765 जिलों में जिला निर्यात संवर्धन समितियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे निर्यात की संभावना वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करें, उनके निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करें, स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को स्केल हासिल करने में मदद करें और संभावित विदेशी खरीदारों तक पहुंचने में उनकी सहायता करें।

2018 से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं, ऐसे में यह उपयोगी होगा कि कृषि निर्यात नीति को अपनाए जाने के बाद से अब तक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए। यहां यह उल्लेख किया सकता है कि जब यह नीति लागू की गई थी, तब इसका एक प्रमुख उद्देश्य 2022 तक कृषि उत्पादों के निर्यात को दोगुना करना था।

भारत को एक प्रमुख कृषि निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें 2018 में कृषि निर्यात नीति अपनाए जाने के बाद की घटनाओं से स्पष्ट रूप से देखा जा



सकता है। वाणिज्य विभाग के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स (DGCI&S) के आंकड़े दिखाते हैं कि कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात 2018-19 के लगभग 37 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 (अप्रैल से फरवरी) में लगभग 46 अरब डॉलर हो गया। यानी इसमें करीब 24% की वृद्धि हुई। हालांकि 2018 के बाद कृषि उत्पादों के निर्यात में यह वृद्धि न केवल कृषि निर्यात नीति में निर्धारित '2022 तक निर्यात दोगुना करने' के लक्ष्य से काफी कम रही, बल्कि यह भारत की कुल निर्यात वृद्धि से भी कम थी। इस दौरान भारत का कुल निर्यात 30% बढ़ा। भारत के कुल निर्यात में कृषि उत्पादों का हिस्सा 11-12% के बीच बना रहा। सिर्फ 2020-21 में खाद्य उत्पादों को छोड़कर अन्य सभी उत्पादों के निर्यात में तेज गिरावट आई थी।

गैर-बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि पिछले दशक की शुरुआत से ही उल्लेखनीय रही है। उस समय सिर्फ 5 करोड़ डॉलर का गैर-बासमती चावल निर्यात हुआ था, लेकिन डेढ़ दशक बाद यह 10 गुना से अधिक बढ़कर 6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2020-21 में गैर-बासमती चावल का निर्यात पहली बार भारत के सबसे लोकप्रिय कृषि निर्यात उत्पाद, बासमती से अधिक हो गया। गैर-बासमती चावल के निर्यात में वृद्धि ने न केवल वैश्विक चावल निर्यात बाजार पर भारत की पकड़ को मजबूत किया, बल्कि कई उप-सहारा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक



**2018 से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं, ऐसे में यह उपयोगी होगा कि कृषि निर्यात नीति को अपनाए जाने के बाद से अब तक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए।**



**कृषि निर्यात को लेकर सकारात्मक उम्मीदें पिछले दशक के अंत से ही बननी शुरू हो गई थीं, लेकिन ये उम्मीदें बहुत जल्दी गायब भी हो गईं। इन उम्मीदों को 2022-23 में तब झटका लगा जब गेहूं के भंडार में कमी के संकेत मिले।**

संबंधों को भी बेहतर किया। चावल की इस किस्म के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों को जाता है। वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात का 51% से अधिक हिस्सा इन देशों को गया। इनमें बेनिन, कोट डी आइवोर और सेनेगल सबसे प्रमुख बाजार रहे। विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान गैर-बासमती चावल के निर्यात में तेज वृद्धि ने अधिकांश आयातक देशों को कोविड के बाद उत्पन्न संकट से उबरने में मदद की।

वर्ष 2024-25 में निर्यात के लिहाज से छह सबसे बड़े कम्पिडिटी ग्रुप - चावल, समुद्री उत्पाद, मसाले, भैंसे का मांस, चीनी और ऑयल मील - का कृषि और संबद्ध उत्पादों के कुल निर्यात में लगभग 63% हिस्सा रहा। 2018 में इन उत्पादों की हिस्सेदारी कुल कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में लगभग दो-तिहाई थी। 2020-21 में चरम पर पहुंचने के बाद इस आंकड़े में गिरावट आई।

इस अवधि में चावल का निर्यात सबसे तेजी (48%) से बढ़ा। गैर-बासमती चावल के निर्यात में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई, जबकि जुलाई 2023 से सितंबर 2024 के बीच सरकार ने घरेलू बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि सरकार ने खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ देशों को उनके अनुरोध पर चावल निर्यात की अनुमति दी थी। दूसरी ओर, समुद्री उत्पादों का निर्यात 2017-18 से 2024-25 के बीच घटा, जबकि भैंसे के मांस का निर्यात मामूली 3% की दर से बढ़ा। उत्पादन चक्र से प्रभावित होने के बावजूद चीनी निर्यात में 37% की वृद्धि दर्ज की गई। ऑयल मील का निर्यात 2017-18 से लगभग 19% गिर गया।

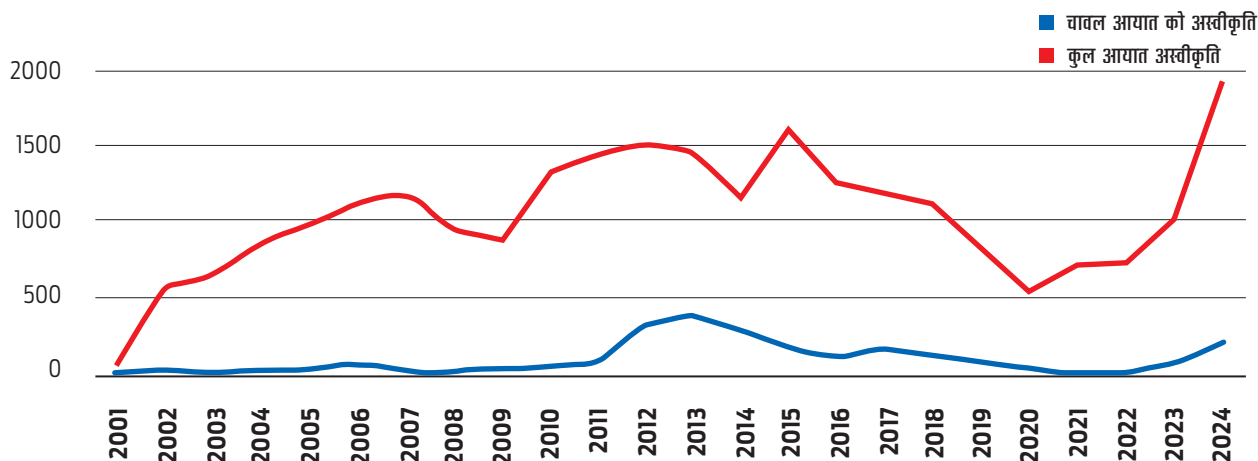
कृषि निर्यात को लेकर सकारात्मक उम्मीदें पिछले दशक के अंत से ही बननी शुरू हो गई थीं,

लेकिन ये उम्मीदें बहुत जल्दी गायब भी हो गईं। इन उम्मीदों को 2022-23 में तब झटका लगा जब गेहूं के भंडार में कमी के संकेत मिले। गेहूं उत्पादन में भारी गिरावट के कारण इसका निर्यात 2023-24 में घटकर 5.4 करोड़ डॉलर का रह गया, जो 2011-12 के बाद का सबसे निचला स्तर था। गर्मी की लहर ने 2023 से गेहूं उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप 2024-25 में इसके निर्यात में तेज गिरावट आई और यह केवल 16 लाख डॉलर रह गया।

इस प्रकार तीन साल के भीतर गेहूं निर्यात 2.2 अरब डॉलर से घटकर केवल 16 लाख डॉलर रह गया। इसने यह अहसास दिलाया कि प्रमुख कृषि उपज के उत्पादन में उतार-चढ़ाव से बड़ी अनिश्चितताएं उत्पन्न हो सकती हैं। चावल के अलावा अधिकांश फसलें पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन चक्र से नहीं निपट पाईं, जिससे गंभीर आपूर्ति संकट उत्पन्न हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बासमती चावल के निर्यात को छोड़कर भारत अन्य कृषि उपज का प्रमुख निर्यातक नहीं बन सका। इस सेक्टर में संरचनात्मक संकट तो था ही, किसान भी इस बात पर आंदोलित होने लगे कि कृषि अब लाभकारी व्यवसाय नहीं रह गया है। ऐसे में अधिकांश फसलों के उत्पादन के स्तर को बनाए रखना एक कठिन कार्य था।

एक सकारात्मक बात यह है कि फल और सब्जियां समेत प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई है। 2017-18 और 2024-25 के बीच प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। भारत को इन उत्पादों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि मूल्य संवर्धन और रोजगार के अवसर बढ़ सकें। इससे भी महत्वपूर्ण

**ग्राफ 1: भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात पर यूएसएफडीए के आयात अलर्ट (2001-24)**



स्रोत: यूएसएफडीए, इंपोर्ट रिफ्यूजल

<https://datadashboard.fda.gov/oii/cd/imprefusals.htm> से लिया गया है।



बात यह है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में है।

### खाद्य संरक्षा मानक

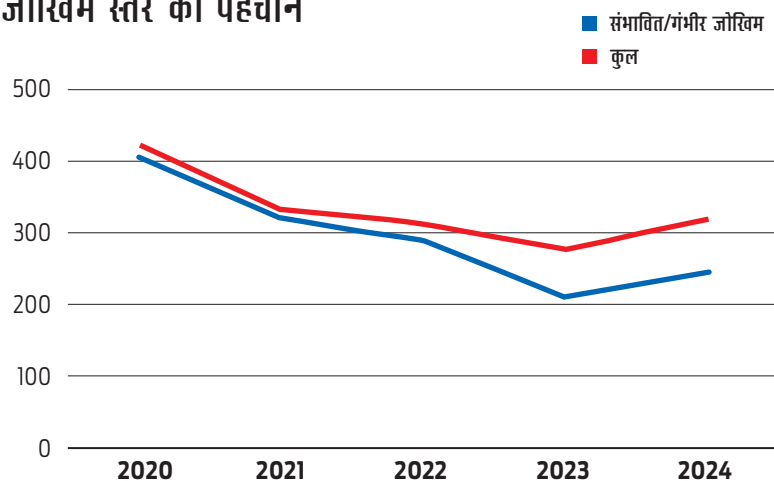
भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने में उत्पादन स्तर में अनिश्चितता एकमात्र कारक नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण कारक है कि निर्यातकों में लगातार सख्त होते सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानकों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता होनी चाहिए। ये मानक न केवल विकसित देशों में, बल्कि विकासशील देशों में भी लागू हो रहे हैं।

यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों और अमेरिका में खाद्य उत्पादों के आयात से उत्पन्न वास्तविक या संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी जारी करने का व्यापक तंत्र है। ईयू के सदस्य देशों में फूड और फीड के लिए रैपिड अलर्ट सिस्टम (RASFF) मौजूद है, जो खाद्य या चारे में पाए गए जोखिम की जानकारी का त्वरित आदान-प्रदान करता है। यह अलर्ट सिस्टम विशेष रूप से आयात से उत्पन्न खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया के जरिए लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिका में फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि आयातित उत्पाद फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट (FD&C Act) और अन्य संबंधित कानूनों के साथ मेल खाते हों। यदि कोई आयात एक्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे 'इंपोर्ट रिफ्यूजल' (आयात अस्वीकृति) के रूप में शामिल किया जाता है। एफडीए का यह निर्णय अंतिम होता है।

ईयू के आरएसएफएफ से 2020 से प्राप्त डेटा और एफडीए के 2001 से जारी आयात अलर्ट्स का विश्लेषण बताता है कि भारतीय खाद्य निर्यातक किस हद तक इन दोनों भौगोलिक क्षेत्रों में सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानकों का पालन कर रहे हैं। एफडीए के आयात अलर्ट्स 2001 से उपलब्ध हैं। ये बताते हैं कि भारतीय खाद्य उत्पादों का निर्यात अमेरिकी मानकों की कसौटी पर कितना खरा उतरा है (ग्राफ 1)।

कोविड महामारी के बाद से भारतीय खाद्य निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार में आयात अस्वीकृति तेजी से बढ़ी है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। 2025 में भी यह रुझान जस का तस बना हुआ है। अप्रैल के अंत तक आयात अस्वीकृति के 766 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल की आयात अस्वीकृति का रुझान सकारात्मक कहा जा सकता है। 2021 के बाद इसमें हल्की वृद्धि हुई है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसे और अधिक नहीं बढ़ने

## ग्राफ 2: ईयू आरएसएफएफ द्वारा खाद्य या चारे में पाए गए जोखिम स्तर की पहचान



स्रोत: EU: Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), [https://food.ec.europa.eu/food-safety/rasff\\_en](https://food.ec.europa.eu/food-safety/rasff_en) से लिया गया।

दिया जाना चाहिए।

ईयू के आरएसएफएफ ने 2020 से 2024 के दौरान भारत से आयातित खाद्य या चारे की 1661 खेप को विभिन्न जोखिम स्तरों के साथ चिन्हित किया। हालांकि इनमें से 12% को 'कोई जोखिम नहीं' के रूप में चिन्हित किया गया था। ग्राफ 2 में उन खेपों के रुझान के बारे में बताया गया है जो संभावित/गंभीर जोखिम का कारण बन सकती हैं।

ग्राफ 2 वर्ष 2020 से खाद्य और चारे की आयात खेपों में उच्च जोखिम के ट्रेंड को दर्शाता है। यह कुल मिलाकर एक उत्साहजनक ट्रेंड है। हालांकि 2024 में मामूली वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान वर्ष के पहले चार महीने का ट्रेंड भी उत्साहजनक दिखता है, क्योंकि इस दौरान सिर्फ 72 मामलों की पहचान की गई जिनमें से 12 मामले गंभीर नहीं थे।

हालांकि अमेरिका और ईयू में सैनिटरी और फाइटो-सैनिटरी मानकों के पालन करने का ट्रेंड यह दिखाता है कि सरकार को नए संस्थानों को खड़ा करने और मौजूदा संस्थानों को मजबूत करने पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके माध्यम से कृषि उत्पादक और निर्यातक वैश्विक बाजारों में प्रचलित कठिन मानकों को पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। इस तैयारी के बिना भारत का कृषि निर्यात हब बनने का सपना अधूरा रहेगा। साथ ही, सरकार को कृषि क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि प्रमुख कमोडिटी के उत्पादन को निरंतर बढ़ावा दिया जा सके। यह देश को एक विश्वसनीय कृषि निर्यात हब के रूप में उभरने के लिए महत्वपूर्ण है। 



**कोविड महामारी के बाद से भारतीय खाद्य निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार में आयात अस्वीकृति तेजी से बढ़ी है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। 2025 में भी यह रुझान जस का तस बना हुआ है। अप्रैल के अंत तक आयात अस्वीकृति के 766 मामले दर्ज किए गए हैं।**

# कृषि निर्यात में कई बाधाओं के बावजूद व्यापक संभावनाएं

इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी, छोटी जोत और नीतियों में अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझते भारतीय कृषि निर्यात के सामने संभावनाएं भी विशाल



## अनुपम कौशिक

मैनेजिंग डायरेक्टर,  
राष्ट्रीय सहकारी निर्यात  
लिमिटेड

**भ**ारत वैश्विक कृषि महाशक्ति बन चुका है और विश्व कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। लेकिन इसका वैश्विक कृषि निर्यात में हिस्सा मात्र 2.4% है। वर्ष 2023-24 में भारत का कृषि निर्यात 48.9 अरब डॉलर रहा, जो 2022-23 के 53.2 अरब डॉलर से कम है। भारत के सामने अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। इस लेख में भारत के कृषि निर्यात की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन किया गया है, और प्रमुख परफॉर्मेंस इंडिकेटर के विश्लेषण के साथ सतत विकास के लिए रणनीतिक संभावनाओं पर विचार किया गया है।

भारत के कृषि निर्यात में हाल के वर्षों में उतार-चढ़ाव रहा है। यह वैश्विक बाजार के डायनामिक्स और घरेलू नीतिगत निर्णय, दोनों को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष 2023-24 में 2022-23 की तुलना में 8.2% की गिरावट घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य रूप से चावल, गेहूं और चीनी जैसी प्रमुख वस्तुओं पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों के कारण हुई।

### साल-दर-साल प्रदर्शन का विश्लेषण:

- 2023-24: 48.9 अरब डॉलर (पिछले साल से 8.2% गिरावट)
- 2022-23: 53.2 अरब डॉलर
- 2021-22: 50.24 अरब डॉलर (21.8% वृद्धि)
- 2020-21: 41.25 अरब डॉलर

वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-दिसंबर) में कुल कृषि निर्यात 3,18,509 करोड़ रुपये (36.95 अरब डॉलर) का रहा।

विशेष वस्तुओं का मजबूत प्रदर्शन बाजार में सुधार के संकेत देता है।

**क्षेत्रवार विवरण:** भारत मुख्य रूप से इन उत्पादों का निर्यात करता है: कृषि एवं संबंधित उत्पाद, समुद्री उत्पाद (शीर्ष श्रेणी), बागान उत्पाद (चाय, कॉफी, मसाले), वस्त्र एवं संबंधित उत्पाद।

**वृद्धि के रुझान:** कृषि निर्यात में पिछले पांच वर्षों में औसतन सकारात्मक वृद्धि हुई है। हाल की गिरावट मुख्य रूप से घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों के कारण हुई है। लेकिन चावल जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध हटाने से चालू वित्त वर्ष में सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं।

**वैश्विक बाजार में स्थिति:** वैश्विक कृषि व्यापार में भारत का 2.5% हिस्सा है और यह दुनिया का आठवां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक बना हुआ है। भारत वैश्विक कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, फिर भी वैश्विक कृषि निर्यात में हिस्सा कम है (स्रोत: डब्ल्यूटोआ का ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, 2022)। उत्पादन क्षमता और निर्यात प्रदर्शन के बीच यह अंतर इस क्षेत्र में छिपी संभावनाओं को दर्शाता है।

**प्रमुख परफॉर्मेंस इंडिकेटर:** चावल कुल कृषि निर्यात में 20% से अधिक योगदान देता है। शीर्ष 5 जिनस (बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, चीनी, मसाले, तिलहन) कुल कृषि निर्यात में 51.5% योगदान करते हैं। कृषि और संबंधित क्षेत्र के कुल निर्यात में समुद्री उत्पाद का हिस्सा सबसे अधिक रहता है। कॉफी निर्यात में 12.3% की मजबूत वृद्धि देखी गई। चाय निर्यात में 10 वर्षों में अधिकतम 10% वृद्धि हुई। फल और सब्जियों का निर्यात 14% बढ़ा। मांस, डेयरी और पोल्ट्री का निर्यात 12.4% बढ़ा।

**निर्यात प्रतिबंधों का प्रभाव:** 2023-24 में चावल, गेहूं और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगे। इन प्रतिबंधों के कारण कृषि निर्यात में 8.2% की गिरावट आई। घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू नीतिगत उपायों ने निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित किया।

### प्रमुख निर्यात कमोडिटी

#### समुद्री उत्पाद: श्रेष्ठ प्रदर्शन

मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार 2023-24 में भारत से समुद्री उत्पादों का निर्यात

व्यापार संतुलन इंडिकेटर		
मानक	वैल्यू	ट्रेंड
कृषि ट्रेड सरप्लस (2023-24)	16 अरब डॉलर	2013-14 के शीर्ष 27.7 अरब डॉलर से गिरावट
कृषि निर्यात (2023-24)	32.8 अरब डॉलर	पिछले साल से 8% गिरावट
निर्यात-आयात अनुपात	सकारात्मक	भारत शुद्ध निर्यातक बना रहा

नोट: मूल्य एपीडा, वाणिज्य मंत्रालय और इंडस्ट्री रिपोर्ट से उपलब्ध डेटा के आधार पर अनुमानित हैं। विनिमय दरें वित्तीय वर्ष के दौरान भिन्न हो सकती हैं।



रिकॉर्ड 17,81,602 टन तक पहुंच गया। इसका मूल्य 60,524 करोड़ रुपये (7.38 अरब डॉलर) से अधिक था। हालांकि रेड सी में भू-राजनैतिक चुनौतियों और अमेरिका, यूरोपीय संघ और इंग्लैंड जैसे बड़े बाजारों में महंगाई से उपभोक्ता मांग में कमी के चलते निर्यात मूल्य में 5.39% गिरावट आई (2022-23 के 63,969 करोड़ रुपये के मुकाबले 2023-24 में 60,524 करोड़ रुपये), लेकिन निर्यात मात्रा में 2.67% की बढ़ोतरी हुई। यह भारत सरकार की विभिन्न पहलों, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य विभाग की ब्रांडिंग, इनोवेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का परिणाम है।

भारत ने 2023-24 में 132 देशों को समुद्री उत्पाद निर्यात किए, जिनमें 6 नए बाजार भी शामिल हैं- सूरीनाम, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मायोत्ते, सिएरा लियोन और ग्वाडेलूप। वर्ष 2024-25 में समुद्री उत्पाद निर्यात में वृद्धि जारी रही। फरवरी 2024 में 0.49 अरब डॉलर की तुलना में फरवरी 2025 में इनका निर्यात 0.51 अरब डॉलर हो गया। कुल निर्यात 7.2 अरब डॉलर का रहा, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जारी भू-राजनैतिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।

#### चावल: कृषि निर्यात का दिग्गज

चावल भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात उत्पाद है और कुल कृषि निर्यात में इसका 20% से अधिक हिस्सा है। 2022-23 में भारत से 11.14 अरब डॉलर का चावल निर्यात हुआ जो 2021-22 में 9.67 अरब डॉलर से 15.22% अधिक था। 2023-24 में भारत ने दुनिया में सबसे अधिक, 165 लाख टन चावल निर्यात किया। सरकार द्वारा 16 मई 2025 को जारी नए आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में भारत ने चावल निर्यात में रिकॉर्ड 12.5 अरब डॉलर की उपलब्धि हासिल की, जो 2023-24 के 10.4 अरब डॉलर से काफी ज्यादा है।

#### अन्य प्रमुख वस्तुएं

**मसाले:** मसालों का निर्यात थोड़ा बढ़कर 2024-25 में 4.45 अरब डॉलर का रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 4.25 अरब डॉलर था।

**काँफी:** 2024-25 में काँफी का निर्यात 1.81 अरब डॉलर रहा, जो 2023-24 में 1.29 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारत से काँफी का निर्यात 2023 में 12.3% बढ़कर 114.62 करोड़ किलो हो गया।

**चाय:** भारत के चाय निर्यात ने भी 10 वर्षों के उच्चतम स्तर को छू लिया। वैश्विक भू-राजनैतिक तनावों के बावजूद यह 2024 में 25.5 करोड़ किलोग्राम तक पहुंच गया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार यह पिछले वर्ष के 23.16 करोड़ किलोग्राम से 10 प्रतिशत ज्यादा है। वैल्यू के लिहाज से देखें तो निर्यात 2023-24 के 0.83 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 0.92 अरब डॉलर हो गया।

**भेड़ और बकरी का मांस:** भारत विश्व में भेड़ और बकरी के मांस के सबसे बड़े निर्यातकों में है। 2022-23 में इसका 6.9 करोड़ डॉलर से अधिक का निर्यात हुआ था। एक

### भौगोलिक विविधता

#### प्रमुख निर्यात गंतव्य (2024-25)

रैंक	देश	प्रमुख कम्पोजिट
1	अमेरिका	मसाले, मरीन, चाय
2	यूएई	चावल, मीट, मरीन
3	चीन	मरीन, चावल
4	बांग्लादेश	चावल, प्याज
5	सऊदी अरब	चावल, मीट, चाय

डाटा स्रोत: एपीडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार तथा विभिन्न इंटरनेट रिपोर्ट

साल पहले की तुलना में इसमें अच्छी वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने वैश्विक बाजारों में 9,592.31 टन भेड़-बकरी का मांस निर्यात किया, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत 537.18 करोड़ रुपये थी। प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, मालदीव और ओमान थे। 2022 और 2023 के बीच सबसे तेजी से बढ़ते निर्यात बाजार संयुक्त अरब अमीरात (82.9 लाख डॉलर), बहरीन (6.63 लाख डॉलर) और कुवैत (4.53 लाख डॉलर) थे।

#### कृषि निर्यात की चुनौतियां

##### नीति संबंधी चुनौतियां

**बार-बार निर्यात प्रतिबंध:** चावल और चीनी के निर्यात पर बार-बार प्रतिबंध ने वैश्विक बाजारों में भारत की विश्वसनीयता प्रभावित की, जिससे खरीदारों का विश्वास घटा है। प्रतिबंध लगाना न केवल ग्लोबल साउथ के कम समृद्ध देशों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है, बल्कि एक भरोसेमंद खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि को भी कमजोर करता है।

**सीमित निर्यात उत्पाद:** भारत के कृषि निर्यात का आधार मुख्य रूप से पांच वस्तुओं पर निर्भर है, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक कीमतों और मांग में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

**प्रसंस्कृत उत्पादों का कम हिस्सा:** प्रसंस्कृत कृषि निर्यात का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है। यह कुल कृषि निर्यात का लगभग 17% है। यह अमेरिका (लगभग 25%) और चीन (लगभग 50%) की तुलना में काफी कम है।

#### इन्फ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता की समस्याएं

**इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी:** कोल्डचेन इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी और अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स बड़ी बाधाएं हैं। फार्मगेट पैकहाउस (कोल्ड रूम वाले प्री-कूलिंग यूनिट्स) या अन्य कोल्डचेन घटकों की जरूरत के प्रति जागरूकता बहुत कम है। एपीडा के अनुसार देश के लगभग 40% खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों की आय पर गहरा प्रभाव पड़ता है।



**वैश्विक कृषि व्यापार में भारत का 2.5% हिस्सा है और यह दुनिया का आठवां सबसे बड़ा कृषि निर्यातक है। भारत कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, फिर भी कृषि निर्यात में हिस्सा कम है। उत्पादन और निर्यात के बीच यह अंतर इस क्षेत्र में छिपी संभावनाओं को दर्शाता है।**



**भारत ने 2023-24 में 132 देशों को समुद्री उत्पाद निर्यात किए, जिनमें 6 नए बाजार भी शामिल हैं। वर्ष 2024-25 में समुद्री उत्पाद निर्यात में वृद्धि जारी रही। फरवरी 2024 में 0.49 अरब डॉलर की तुलना में फरवरी 2025 में इनका निर्यात 0.51 अरब डॉलर हो गया।**

**गुणवत्ता और मानक:** कीटों-बीमारियों के प्रभाव और जागरूकता की कमी के कारण भारतीय कृषि निर्यात के लिए निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय सैनिटरी तथा फाइटो-सैनिटरी मानकों का पालन करना एक बड़ी चुनौती है।

## संरचनात्मक चुनौतियां

छोटी जोत: छोटी और सीमांत जोत के साथ कर्ज मिलने में कठिनाई कमर्शियल उत्पादन की ओर जाने में लगातार चुनौतियां उत्पन्न करती है। भारत में दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे और सीमांत किसान 86.2% हैं। छोटी जोत और कम मैकेनाइजेशन इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल करने में बाधक हैं।

## सरकार की पहल और नीतिगत उपरेखा

**कृषि निर्यात नीति 2018:** सरकार ने दिसंबर 2018 में व्यापक कृषि निर्यात नीति पेश की। इसका उद्देश्य उचित नीतिगत उपायों से निर्यात संभावनाओं का दोहन करना, भारत को कृषि क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनाना और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में मदद करना था। प्रमुख उद्देश्यों में एक दशक में कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना और वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण को प्राथमिकता देकर विश्व कृषि निर्यात में भारत का हिस्सा दोगुना करना शामिल हैं।

## राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड: एक परिवर्तनकारी पहल

भारत के कृषि निर्यात में हाल की सबसे महत्वपूर्ण पहल

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के गठन के रूप में हुई है। एनसीईएल को 25 जनवरी 2023 को बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया।

**संरचना और प्रमोटर:** एनसीईएल एक बहुराज्यीय सहकारी समिति है, जिसे देश की कुछ प्रमुख सहकारी समितियों ने संयुक्त रूप से प्रमोट किया है। इनमें अमूल, इफको, कृभको, नाफेड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) शामिल हैं। एनसीईएल की अधिकृत शेयर पूंजी 2,000 करोड़ रुपये है। प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सभी सहकारी समितियां इसका सदस्य बनने के लिए पात्र हैं।

## कैसे एनसीईएल कृषि निर्यात को बढ़ावा दे रहा है:

**1. शीर्ष संगठन:** एनसीईएल सहकारी क्षेत्र से निर्यात के लिए एक अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है तथा हर स्तर और क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देता है। इससे सहकारी समितियों की विदेशी बाजारों में निर्यात क्षमता बढ़ती है।

**2. समग्र निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र:** एनसीईएल कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। इसमें खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन, अनुसंधान एवं विकास और व्यापार शामिल हैं।

**3. मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता सुधार:** एनसीईएल सहकारी समितियों को वैल्यू एडिशन और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करता है ताकि सहकारी निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सके।

**4. निर्यात समर्थन सेवाएं:** इसकी सेवाएं हैं- निर्यात सर्टिफिकेशन और लॉजिस्टिक्स में सहायता, वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन देना, प्रशिक्षण और क्षमता विकास, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार के लिए रिसर्च करना, बाजार इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना, निर्यात से संबंधित परामर्श सेवाएं, सहकारी निर्यात के लिए नॉलेज रिपॉजिटरी बनाना और उसका रखरखाव, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग में समर्थन।

**5. किसान-केंद्रित दृष्टिकोण**

**6. बाजार पहुंच और मूल्य प्राप्ति:** एनसीईएल किसानों को विदेशी बाजारों में उनके उत्पादों के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता करता है।

## रणनीतिक महत्व

एनसीईएल कृषि निर्यात में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करता है:

- **निर्यात बाजार की समस्याओं का समाधान:** सघन प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, कुप्रथाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी और मानकीकरण जैसी समस्याओं से निपटना।
- **सहकारिता की ताकत का उपयोग:** कृषि पर निर्भर भारत की 60% आबादी के लिए व्यापक सहकारी नेटवर्क का लाभ उठाना।



Photo: NCEL



- **समग्र सरकारी दृष्टिकोण:** निर्यात से जुड़ी विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं और नीतियों के लाभ सहकारी समितियों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना।
- **समावेशी विकास मॉडल:** सरकार के "सहकार से समृद्धि" के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में काम करना।

## भविष्य की संभावनाएं और सुझाव

**निर्यात वृद्धि के लिए एनसीईएल का उपयोग:** एनसीईएल भारत के कृषि निर्यात के दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। सहकारी समितियों की सामूहिक शक्ति का उपयोग करके एनसीईएल 100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

**सहकारी भागीदारी का विस्तार:** 10,000 से अधिक सहकारी समितियों को सदस्य के रूप में जोड़ने और इसके व्यापक विस्तार की संभावना के साथ, एनसीईएल देश भर के लाखों छोटे किसानों के उत्पादन को एग्रीगेट कर सकता है।

**गुणवत्ता और मानकीकरण:** तकनीकी मार्गदर्शन और गुणवत्ता सुधार में सहायता प्रदान करके, एनसीईएल सुनिश्चित कर सकता है कि सहकारी उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों को निरंतर पूरा करें।

**ब्रांड निर्माण:** सामूहिक ब्रांडिंग और मार्केटिंग प्रयासों के माध्यम से एनसीईएल भारतीय कृषि उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों में मजबूत ब्रांड की पहचान बना सकता है।

**जोखिम कम करना:** इसका अंग्रेला स्ट्रक्चर छोटी सहकारी समितियों को कम जोखिम के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद करता है।

## प्रौद्योगिकी और नवाचार

कृषि निर्यात को बड़ा बूस्ट नई तकनीक और बिजनेस मॉडल में नए विचारों और इनोवेशन से आएगा। इस संदर्भ में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन और उनकी समृद्धि के लिए नीतियां अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। प्रौद्योगिकी और इनोवेशन भारतीय कृषि को पूरी तरह बदल रहे हैं, और दक्षता व सस्टेनेबिलिटी के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और एग्रीटेक समाधान किसानों को वास्तविक समय के डेटा, प्रिंसीजन खेती की तकनीक और स्वचालित सिंचाई प्रणालियों से सशक्त बनाते हैं। एआई-संचालित उपकरण फसल प्रबंधन, रोगों का शीघ्र पता लगाने और उर्वरक प्रयोग के ऑप्टिमाइजेशन में मदद करते हैं, जिससे अपव्यय कम होता है और उपज बढ़ती है।

मोबाइल एप्लिकेशन, सेंसर नेटवर्क और ड्रोन निगरानी जैसे इनोवेशन सूचना की खामियों को दूर कर किसानों को बाजारों और वित्तीय सेवाओं से जोड़ते हैं। यह तकनीकी क्रांति उत्पादकता बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। एनसीईएल उन्नत कृषि तकनीक, प्रिंसीजन खेती और सक्षम सिंचाई को बढ़ावा देने के साथ कृषि स्टार्टअप और इनोवेटिव समाधानों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि उत्पादकता और निर्यात दक्षता को बढ़ाया जा सके।

## मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण

कृषि उपज का मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण भारत की निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्नत प्रसंस्करण तकनीक उत्पाद की शेल्फ लाइफ और पोषकता बढ़ाती हैं। इससे वैश्विक उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सकता है। जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुओं को प्रसंस्कृत उत्पादों में परिवर्तित करने से कटाई के बाद होने वाले नुकसान कम होते हैं और खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त मूल्य संवर्धन से उत्पाद की ब्रांडिंग होती है और प्रीमियम बाजारों तक पहुंच संभव होती है। आधुनिक प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश और नई तकनीक अपनाकर भारत कृषि निर्यात काफी बढ़ा सकता है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।

## बाजार विविधीकरण

निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने विकसित देशों में उच्च निर्यात संभावना वाले 20 कृषि उत्पादों की पहचान की है। इनमें केले, आम, काजू, भैंस का मांस और शराब भी शामिल हैं। 2022 में ऐसे उत्पादों के 400 अरब डॉलर के वैश्विक बाजार में भारत का हिस्सा केवल 2.23 प्रतिशत था, जो 9 अरब डॉलर के बराबर है। लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में 4 से 5 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है।


## नीतिगत सुझाव

**सुसंगत व्यापार नीतियां:** अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि अस्थायी शुल्क जैसे नियम-आधारित और पूर्वानुमान योग्य नीतियां अपनाई जाएं ताकि निर्यात में अचानक बाधा न आए।

**इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास:** सरकार को आवश्यक कमोडिटी का बफर स्टॉक रखना चाहिए ताकि मूल्यों में अस्थिरता को कम किया जा सके और बाजार में स्थिरता सुनिश्चित हो।

**गुणवत्ता में वृद्धि:** अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का तंत्र विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े।

**एनसीईएल का संचालन:** एनसीईएल की पहुंच को अधिक सहकारी समितियों तक बढ़ाना, इसकी तकनीकी क्षमताओं को विस्तार देना ताकि संचालन का स्तर ऊंचा हो सके।

भारत का कृषि निर्यात एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी, छोटी जोत और नीतियों में अस्थिरता जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। लेकिन इस क्षेत्र की संभावनाएं विशाल हैं। प्रौद्योगिकी अपनाने, मूल्य संवर्धन, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास और नीतिगत स्थिरता पर केंद्रित कदमों के साथ भारत कृषि निर्यात में 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को साकार कर सकता है। इस प्रयास की सफलता से न केवल विदेशी मुद्रा और किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि भारत को वैश्विक कृषि बाजार में एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगी। आगे का सफर सरकार, निजी क्षेत्र और कृषि समुदायों के समन्वित प्रयासों की मांग करता है। 



छोटी और सीमांत जोत के साथ कर्ज मिलने में कठिनाई कमर्शियल उत्पादन में लगातार चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। भारत में दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे और सीमांत किसान 86.2% हैं। छोटी जोत और कम मैकेनाइजेशन इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल करने में बाधक हैं।

# भारतीय कृषि निर्यात को चाहिए नया दृष्टिकोण

निर्यात दोगुना होने से किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में तो मदद मिलेगी ही, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी विकसित होगा



**सिराज ए. चौधरी**

पार्टनर, अगवाया एलएलपी



**एम. रामाकृष्णन**

मेनेजिंग डायरेक्टर,  
प्राइमस पार्टनर्स

**ह**मारे देश की 40% से अधिक आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसका हिस्सा 18% से अधिक है। पिछले तीन वर्षों में हमारा कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर रहा है। वैश्विक कृषि निर्यात में हमारी हिस्सेदारी 3% से भी कम है। चीन, जिसके पास भारत के मुकाबले कम उपजाऊ भूमि है, लगभग 100 अरब डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। यह अंतर उस कुशलता और मूल्यवर्धन की कमी को दर्शाता है जिसे भरने की आवश्यकता है।

हम जिन शीर्ष 5 देशों को कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं, उनमें अमेरिका, चीन, यूएई, वियतनाम और बांग्लादेश शामिल हैं। इनके बाद सऊदी अरब, मलेशिया, इराक आदि आते हैं। हमारे प्रमुख निर्यात में समुद्री उत्पाद, चावल (बासमती और अन्य), मसाले, भैंस का मांस, चीनी आदि शामिल हैं। हाल के वर्षों में समुद्री उत्पादों का निर्यात 7 से 8 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। कपास का निर्यात लगभग 6.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। चावल (बासमती और अन्य) अब भी एक प्रमुख निर्यात कमोडिटी है। इसका हालिया निर्यात आंकड़ा 10 अरब डॉलर के आसपास है। भैंस के मांस का निर्यात अपेक्षाकृत स्थिर रहा है, जो 3.17 से 3.74 अरब डॉलर के बीच है। ताजे फल मुश्किल से शीर्ष 10 में जगह बना पाते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि कृषि उत्पादों के निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 2014-15 में 13.7% से बढ़कर 2023-24 में 23.4% हो गई है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 2018-19 के लगभग 6 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 10.9 अरब डॉलर हो गया है।

हालांकि, जलवायु परिवर्तन के दबाव, घटते भूजल स्तर और वैश्विक बाजार में बदलावों को देखते हुए भारत के लिए अपनी कृषि निर्यात रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करना आवश्यक है। वर्तमान निर्यात धान जैसी जल-प्रधान फसलों पर आधारित है। इसे धीरे-धीरे पोषण से भरपूर, आर्थिक रूप से लाभकारी और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ विकल्पों की ओर मोड़ना होगा।

## कृषि निर्यात में सतत विकास के लिए वस्तुओं का मिश्रण कैसे बदलना चाहिए?

### धान का मामला

चावल दशकों से भारत का मुख्य कृषि निर्यात उत्पाद रहा है। हालांकि धान की खेती की पारिस्थितिक लागत की स्कूटनी अब बढ़ रही है। एक किलो धान के लिए 4,000-5,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इस तरह यह पानी की कमी वाले राज्यों के लिए सस्टेनेबल नहीं रह जाता है। लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी और उत्पादकता में गिरावट आती है। इसके अलावा, धान के खेत मीथेन गैस का एक प्रमुख स्रोत हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि संबंधी स्ट्रेस बढ़ने के चलते धान निर्यात पर निर्भर रहना अब दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है। अब नीति और बाजार स्तर पर कम निवेश और अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की ओर जाने पर आम सहमति बन रही है।

### मिलेट: सुपरफूड क्रांति

मोटे अनाज (मिलेट्स) सस्टेनेबल खेती के प्रतीक बनकर उभरे हैं। 2023-24 में भारत ने 1.46 लाख टन मोटे अनाज का निर्यात किया, जिसकी कीमत 7.1 करोड़ डॉलर थी। इनमें ज्वार, रागी, बाजरा और प्रोसेस्ड मिलेट स्नेक्स प्रमुख थे (स्रोत: एपीडा)। मिलेट्स के लिए धान की तुलना में 70% कम पानी की जरूरत पड़ती है। ये कीट-प्रतिरोधी होते हैं और शुष्क मिट्टी में भी पनपते हैं। साथ ही ये ग्लूटेन-मुक्त, फाइबर, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं- जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक वैश्विक उपभोक्ताओं के लिए आदर्श हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने से यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी एशिया जैसे नए बाजार खुले हैं। इस गति को अब ब्रांडिंग, जीआई टैगिंग और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के माध्यम से संस्थागत रूप देना जरूरी है।

### मक्का: विविध मांग वाला उत्पाद

मक्का अब खाद्य, चारा, स्टार्च और बायोफ्यूल जैसे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 14.4 लाख टन मक्का निर्यात किया, जिसकी कीमत 44 करोड़ डॉलर थी। बांग्लादेश, वियतनाम और नेपाल से इसकी बहुत मांग देखी गई। इस फसल के



लिए भी कम पानी की आवश्यकता होती है और यह विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में आसानी से अनुकूलित हो जाती है। कटाई के बाद सुखाने की व्यवस्था, बेहतर कृषि तकनीक और अनुबंध खेती को बढ़ावा देकर भारत की स्थिति को और सुदृढ़ किया जा सकता है।

#### कपास: मूल्य संवर्धन आगे बढ़ने का रास्ता

पिछले 7-8 वर्षों में भारत से कपास का निर्यात 5 से 10 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच रहा है। हमारे किसान वैश्विक मूल्य अस्थिरता के साथ ब्राजील व अमेरिका से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करते हैं। प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत को कच्चे कपास के निर्यात से हटकर ऑर्गेनिक कपास, यार्न और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे मूल्य-संवर्धित क्षेत्रों की ओर बढ़ना होगा। 'सस्टेनेबल इंडियन कॉटन' ब्रांडिंग पहल से बेहतर मूल्य पाने में मदद मिल सकती है।

#### भैंस का मांस और पशु उत्पाद

भारत भैंस मांस का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है। वित्त वर्ष 2023-24 में इसका 3.74 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। इसके प्रमुख बाजारों में वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। भारत का मांस ओआईई (OIE) और कोडेक्स (Codex) मानकों का पालन करता है, जो इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। एशिया में विशेष रूप से बढ़ती प्रोटीन मांग को देखते हुए, बेहतर ट्रेसबिलिटी और लॉजिस्टिक्स के साथ भारत मांस निर्यात बढ़ा सकता है। साथ ही पशु झिल्लियों, खाल और डेयरी उत्पादों (जैसे पनीर, घी) जैसी श्रेणियां भी उभर रही हैं, जिनमें प्रीमियम उत्पादों की संभावना है।

#### प्रसंस्कृत खाद्य की ओर बढ़ता रुझान

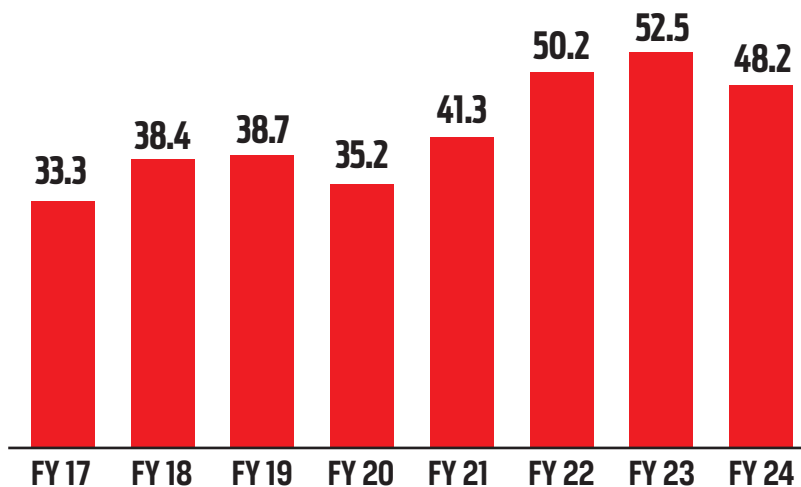
वित्त वर्ष 2023-24 में प्रोसेस्ड फूड्स का भारत के कुल कृषि-निर्यात में 23% से अधिक हिस्सा था। इनका करीब 10 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। वैश्विक बाजारों में पैकेज्ड और ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ता रुझान अब नहीं बदलने वाला है। भारत की विविध खाद्य परंपरा, कम लागत वाली मैनुफैक्चरिंग क्षमता और बढ़ता ऑर्गेनिक सेगमेंट एक विशिष्ट बढ़त प्रदान करता है। अमेरिका जैसे बाजारों में लगभग 50% खाद्य निर्यात प्रोसेस्ड ही होते हैं। भारत में प्रोसेस्ड निर्यात की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की संभावनाएं हैं। प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट उत्पादों के रूप में केवल झींगा (श्रिम्प) निर्यात लगभग 10 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है।

#### हमें किन बातों पर ध्यान देना होगा

##### ग्राहक सहभागिता

हमें दुनिया के शीर्ष खाद्य आयातक देशों का विश्लेषण करना होगा, उनकी स्थानीय खरीद आवश्यकताओं तथा भारतीय उत्पादों की ताकत को ध्यान में रखते हुए

### भारत के कृषि निर्यात का ट्रेंड (अरब डॉलर में)



स्रोत: आईबीईएफ.

दोनों के बीच कमी की पहचान करनी होगी। हमें अपने वर्तमान ग्राहक आधार से आगे जाकर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े और लाभकारी बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

कुछ प्रमुख देशों को लक्षित करने के बाद हमें वहां के ग्राहकों के साथ गहराई से जुड़ने में निवेश करना चाहिए। इसके लिए एपीडा जैसी सरकारी संस्था की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। भारत सरकार और उद्योग (निर्यात संगठनों, कृषि व्यापारियों, नाबार्ड जैसी संस्थाओं आदि) को मिलकर उन आयातक देशों के साथ काम करना होगा, उनकी आवश्यकताओं को समझना होगा और फिर किसानों के इकोसिस्टम को उसी के मुताबिक ढालना होगा। उदाहरण के लिए, हमें यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे देशों में निर्यात के लिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानकों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

#### उत्पाद विकास

एक बार हम आयातक की आवश्यकताओं को समझ लें, तो हमें किसान के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ उसी के अनुरूप काम करना होगा। ये नए उत्पाद (जैसे एवोकाडो), नए क्लस्टर (जैसे उत्तर-पूर्व भारत) या मौजूदा क्लस्टर में नया प्रोत्साहन (जैसे अंगूर/नासिक) हो सकते हैं। यदि हम भारत के कृषि-जलवायु क्षेत्रों की विविधता देखें, तो हम कई ऐसे उत्पाद उगाते हैं जो भारत में बहुत लोकप्रिय नहीं हैं – जैसे कि रामबूटन, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो आदि। यदि हमें इन उत्पादों के लिए सही बाजार से जुड़ाव मिल जाए, तो हम बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उत्पाद मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि ट्रेंड का प्रति इकाई मूल्य वर्तमान स्तर से बढ़ सके।



**जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि संबंधी स्ट्रेस बढ़ने के चलते चावल निर्यात पर निर्भर रहना अब दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है। अब नीति और बाजार स्तर पर कम निवेश और अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की ओर जाने पर आम सहमति बन रही है।**

### सप्लाई चेन की क्षमता

उत्पादन प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने बाद अगला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरी सप्लाई चेन में इन्फ्रास्ट्रक्चर में कहीं कमी न हो। इसमें खेत स्तर पर सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज यूनिट से लेकर, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, पैक-हाउस, रेफ्रिजरेटेड ट्रक, उन्नत पैकेजिंग और प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण आवश्यक है।

प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं की ग्राहक आवश्यकताओं को देखते हुए हमें बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग फैक्टरियों में निवेश करना होगा। भारत की जो कृषि उत्पादन क्षमता है, उसे देखते हुए निर्यातानुमुख प्रसंस्करण के लिए आसानी से दस मेगा फूड पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। इनमें गोदाम से लेकर गुणवत्ता परीक्षण और निर्यात डॉक्यूमेंटेशन तक की एकीकृत सुविधाएं शामिल होनी चाहिए। हमें पर्याप्त परीक्षण सुविधाओं (जैसे वैश्विक मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्रों – GAP, HACCP, ऑर्गेनिक आदि के लिए) की भी आवश्यकता है। ट्रीटमेंट फैसिलिटी (जैसे भाप उपचार) भी स्थापित की जानी चाहिए ताकि उत्पाद वैश्विक फाइटोसैनेटरी मानकों को पूरा कर सकें।

कृषि निर्यातकों की एक आम समस्या है हवाई अड्डों या समुद्री बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी की कमी। सभी बंदरगाह कृषि निर्यात को संभालने में सक्षम नहीं हैं। सप्लाई चेन को देखते हुए खेत से लेकर ग्राहक के पास उत्पाद पहुंचने तक की हर कड़ी का गंभीर विश्लेषण जरूरी है। नए बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता हो सकती है। परिवहन लागत पर प्रोत्साहन और सब्सिडी देकर इसे सुदृढ़ करना होगा। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) में निवेश प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसान उत्पादक संगठनों को अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए सॉफ्ट लोन और अनुदान देना एक और तरीका है। निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी) की योजना का विस्तार किया जाना चाहिए, जिसमें कृषि निर्यात पर विशेष ध्यान हो। सरकार को वायबिलिटी गैप फंडिंग का उपयोग करके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश को और आकर्षक बनाना चाहिए।

विमान की जगह समुद्री मार्ग से माल ढुलाई से लागत कम होती है और प्रदूषण भी कम होता है। समुद्री मार्ग बड़ी मात्रा में सामान को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए किफायती विकल्प है। इससे प्रति इकाई शिपिंग लागत में कमी आती है। इसके अतिरिक्त इसमें कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और सस्टेनेबल सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है। इसके लिए खेत से लेकर पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स तक उचित प्रक्रियाएं विकसित करनी होंगी।

देश के प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्रों में 50 एकीकृत

निर्यात लॉजिस्टिक्स हब का विकास निर्यात को एक बड़ा प्रोत्साहन दे सकता है। इन केंद्रों में संग्रह करने, छंटाई, पैकेजिंग, प्री-कूलिंग और कस्टम क्लियरेंस जैसी एंड-टू-एंड सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

यदि इन कार्यों के लिए सरकार की ओर से किसी तकनीकी निवेश की आवश्यकता हो तो उसमें तेजी लाई जानी चाहिए। इसमें उपग्रह डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सेंसर का उपयोग कर समय पर और सटीक कृषि परामर्श सुनिश्चित करना भी शामिल है। साथ ही एक केंद्रीय वॉर रूम की जरूरत होगी जो वैश्विक घटनाक्रम, मौसम के पैटर्न में बदलाव और खेतों में नए प्रोडक्शन ट्रेंड की रियल-टाइम जानकारी प्रदान कर सके।

### जनशक्ति का विकास

हम जो भी दिशा अपनाएं, हमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सचेत रूप से निवेश करना होगा। नौकरशाहों को वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठ तरीकों, खाद्य/एफएमसीजी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संचालन के तरीकों और अन्य सरकारों (जैसे चीन) द्वारा अपनाए गए तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। एक्सटेंशन कर्मियों और कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों को वैश्विक मानकों, नए तरीकों और नई विधियों को अपनाते समय मौसम की अनिश्चितता से कैसे निपटना है, इस पर प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

स्वाभाविक रूप से, यदि ग्राहकों की तरफ से कोई नई मांग आती है, या प्रक्रियाओं या गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक होता है, तो सबसे अधिक प्रशिक्षण किसान को देना होगा। इन सभी विभिन्न हितधारकों को नई तकनीकी संभावनाओं के बारे में भी प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ेगी।

### निष्कर्ष: मात्रा से मूल्य की ओर

भारत की कृषि निर्यात नीति को मात्रा-आधारित से मूल्य-आधारित दृष्टिकोण की ओर लेकर जाने की जरूरत है। चावल या चीनी जैसे पारंपरिक निर्यात में धीरे-धीरे बढ़ोतरी की बजाय, हमें टिकाऊ, जलवायु-सहिष्णु और अधिक ग्रोथ वाली कमोडिटी-जैसे मोटे अनाज, मक्का, भैंस का मांस, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कपास वैल्यू चेन और बागवानी-में निवेश करना चाहिए। निर्यात को दोगुना करना किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य में सीधे योगदान देगा। इसके अतिरिक्त देश का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी विकसित होगा।

100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात लक्ष्य तक पहुंचना कोई दूर का सपना नहीं है। समन्वित सुधार, रणनीतिक निवेश और केवल इरादों के बजाय क्रियान्वयन पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके हम इस सपने को वास्तविकता में बदल सकते हैं। **Rw**



**अमेरिका जैसे बाजारों में लगभग 50% खाद्य निर्यात प्रोसेस्ड ही होते हैं। भारत में प्रोसेस्ड निर्यात की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की संभावनाएं हैं। प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट उत्पादों के रूप में केवल इर्गिंगा (श्रिम्प) निर्यात लगभग 10 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है।**





श्री पुष्कर सिंह धामी  
मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखंड



International Year  
of Cooperatives

Cooperatives Build  
a Better World



उत्तराखण्ड राज्य



डॉ. धन सिंह रावत  
मा. सहकारिता मंत्री, उत्तराखंड

## MPACS engaged as sales point for silage under **Mukhyamantri Ghasyaari Kalyaan Yojana**

### Outreach of MGKY

- ▶ Currently, MGK scheme is operational in 11 districts
- ▶ 185 MPACS are currently carrying out distribution of silage.
  - ◆ 90 in Garhwal division
  - ◆ 95 in Kumaon division
- ▶ Additional income of MPACS due to silage distribution through the Commissions (Rs 0.30/kg) on sales of silage
- ▶ More than 52273 beneficiaries associated
- ▶ Siage Federation has distributed 53934 ton of silage through 185 cooperative societies in the last 4 years



आनंद ए.डी. शुक्ल  
प्रबंध निदेशक यूसीआरएफ

सोनिका (आईएसएस)  
निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तराखंड, देहरादून

# विश्व बाजार में कैसे जगह बनाएंगे भारतीय कृषि उत्पाद

100 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी कृषि निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना होगा



**प्रो. राकेश  
मोहन जोशी**

कुलपति, भारतीय विदेश  
व्यापार संस्थान, नई दिल्ली

rakeshmohanjoshi@iift.edu

**कृ**षि निर्यात भारत की आजीविका और रोजगार की चुनौतियों के समाधान की कुंजी हैं। यहां कृषि लोगों की आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश की 45% से अधिक आबादी को रोजगार प्रदान करती है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 18% का योगदान करती है। भारत 142 करोड़ आबादी के साथ विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता अत्यावश्यक है। भारत के अधिकांश कृषि उत्पादन की देश के भीतर ही खपत हो जाती है, जबकि विकसित देशों में कृषि उत्पादन का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। भारतीय कृषि की विशेषताएं बिखरी हुई जोत, जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, कम उत्पादकता और विपणन अक्षमताएं हैं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, भारत कई कृषि कमोडिटी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनकर उभरा है। दूध, दालें, जूट, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास जैसे अनेक कृषि उपज के मामले में यह विश्व में अग्रणी है।

भारत ने कृषि क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। एक समय खाद्यान्न का आयातक रहा भारत आज विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन चुका है। यह वैश्विक चावल व्यापार में लगभग 40% हिस्सेदारी रखता है। भारत का कृषि निर्यात 2000-01 में 7.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 53.1 अरब डॉलर हो गया, जो 8% सालाना वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद हुई कि समय-समय पर चावल, चीनी, गेहूं आदि जैसे उत्पादों पर निर्यात की मात्रा या न्यूनतम निर्यात मूल्य के अंकुश लगाए गए।

हालांकि सालों से भारत खाद्य तेलों और दालों के आयात पर निर्भर रहा है, और इनके मूल्य में वृद्धि भारत के कृषि व्यापार संतुलन पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालती है। वर्ष 2024 में भारत के कृषि निर्यात में 6.5% वृद्धि हुई, जबकि आयात में 18.7% बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे भारत का कृषि व्यापार घाटा बढ़ गया। वर्ष 2024 में भारत के प्रमुख कृषि निर्यात जैसे समुद्री उत्पाद, गैर-बासमती चावल, चीनी, बासमती चावल और मसाले कुल

कृषि निर्यात का 50% से अधिक थे।

## कृषि निर्यात की प्रमुख चुनौतियां

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के कृषि जिंस की कीमतों के सूचकांक और वर्ल्ड बैंक के कमोडिटी प्राइस इंडेक्स से संकेत मिलता है कि कृषि जिंसों की कीमतों में गिरावट का रुझान है। वर्ल्ड बैंक ने 2025 में वैश्विक खाद्य कीमतों में लगभग 7% गिरावट और 2026 में अतिरिक्त 1% गिरावट का अनुमान लगाया है। इस परिदृश्य में यह आवश्यक हो गया है कि हमारी कृषि उत्पादन प्रणाली को मूल्य श्रृंखला के हर चरण में प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, ताकि भारतीय कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मुकाबला कर सकें।

कृषि और खाद्य उत्पादों की नष्ट होने की प्रकृति के कारण आपूर्ति श्रृंखला में अनेक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, विशेषकर कोल्डचेन, भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण से संबंधित। भारतीय कृषि प्रणाली में संरचनात्मक समस्याएं हैं जिन्हें समग्र दृष्टिकोण से हल करने की आवश्यकता है। भंडारण और परिवहन की अक्षमता के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है,





जिससे कटाई के बाद 15-20% फसल का नुकसान होता है। विकसित देश अब कृषि व्यापार में अधिक से अधिक संरक्षणवादी रुख अपना रहे हैं, जहां गुणवत्ता मानकों, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों के बहाने गैर-शुल्क बाधाएं खड़ी की जा रही हैं।

### व्यापक रणनीति और सटीक कार्यान्वयन की आवश्यकता

भारत को अपने कृषि निर्यात की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए खेतों और आपूर्ति शृंखला में व्याप्त अक्षमताओं को दूर करना होगा। इसके साथ ही केवल प्राथमिक वस्तुओं के बजाय वैल्यू एडिशन और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए नए बाजारों की पहचान करना और वैकल्पिक बाजारों तक पहुंचना भारत की कृषि निर्यात रणनीति का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए।

भारत को उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हुए कृषि रसायनों के उपयोग में चरणबद्ध रूप से कमी लाने, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने और जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करते हुए उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। इसके लिए चौथी पीढ़ी की कृषि तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का एकीकृत और कुशल उपयोग आवश्यक है, विशेषकर उत्पादन और जल संचय की दिशा में।

भारत को खाद्यान्न और प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन व निर्यात से हटकर बागवानी और अधिक

शेल्फ लाइफ वाले मूल्य वर्धित उत्पादों की ओर जाने की जरूरत है, जहां मुनाफे की संभावनाएं कहीं अधिक होती हैं। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) रणनीति को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि इसमें निहित संभावनाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके।

राज्य और केंद्र सरकार, दोनों को खेतों के स्तर पर और संपूर्ण आपूर्ति शृंखला में विभिन्न एजेंसियों को जोड़ते हुए ऐसी योजनाएं विकसित करनी चाहिए जो उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हों। केंद्र और राज्यों के विभागों को समन्वित और समग्र निर्यात प्रोत्साहन रणनीति के तहत एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, न कि अलग-अलग जिनमें आपसी समन्वय की कमी हो।

भारत को नए व्यापार समझौतों में प्रवेश करते समय सावधानी बरतनी चाहिए ताकि देश को शुल्क-मुक्त या रियायती शुल्क के रूप में बाजार पहुंच का लाभ मिल सके। साथ ही गैर-शुल्क बाधाओं की स्पष्टता भी हो। गुणवत्ता में सुधार के लिए काफी प्रयासों की आवश्यकता है ताकि गुणवत्ता संबंधी उभरती व्यापार बाधाओं का समाधान किया जा सके और निर्यात गंतव्य पर कनसाइनमेंट अस्वीकार किए जाने को न्यूनतम किया जा सके।

हमें अत्यधिक सतर्क रहने की भी आवश्यकता है क्योंकि अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कई विकसित देश भारत के 142 करोड़ के विशाल उपभोक्ता बाजार पर नजर गड़ाए हुए हैं।

हाल ही अमेरिका ने अप्रत्याशित टैरिफ नीति के तहत भारत पर 26% शुल्क और अन्य कई देशों पर भिन्न-भिन्न रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में व्यापार का विश्लेषण कहीं अधिक जटिल हो गया। इस नीति के तहत वियतनाम और थाईलैंड पर अधिक शुल्क लगाए गए, जिससे भारतीय चावल थोड़ा अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया था, लेकिन बाद में सभी देशों पर लगाए गए टैरिफ को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति तेजी से जटिल और अस्पष्ट होती जा रही है, विशेष रूप से चीन पर लगाए गए उच्च शुल्कों के कारण (हाल में समझौते के बाद अमेरिका और चीन ने एक-दूसरे के खिलाफ शुल्क में कमी की है)। संभावना है कि चीन, अमेरिका से कृषि आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। तब अमेरिका के किसान वैकल्पिक बाजारों की तलाश करेंगे। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी देशों और प्रमुख बाजारों पर लागू आयात शुल्क की निरंतर निगरानी की जाए। सरकारों, निर्यात संवर्धन एजेंसियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखनी चाहिए और लचीली एवं समयानुकूल व्यापार रणनीति अपनानी चाहिए। Ru



**बागवानी और अधिक शेल्फ लाइफ वाले मूल्य वर्धित उत्पादों की ओर जाने की जरूरत है, जहां मुनाफे की संभावना अधिक होती हैं। एक जिला एक उत्पाद रणनीति को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि इसमें निहित संभावनाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके।**





# किसान केंद्रित शोध को देंगे प्राथमिकता: डॉ. मांगी लाल जाट

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपने शोध के तरीके में बदलाव कर किसानों की जरूरत को अपने शोध का आधार बनाने जा रही है। इसके साथ ही कृषि शोध के लिए काम करने वाले सभी संस्थान और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की कामकाज की प्रणाली में भी बदलाव होने जा रहा है वहीं कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका को भी नये सिरे से परिभाषित किया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में उनकी भूमिका अधिक प्रभावी बन सके। एक तरह से वन आईसीएआर की धारणा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही शोध और कार्यप्रणाली के केंद्र में समग्र एग्री फूड सिस्टम एप्रोच पर जोर दिया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के नए महानिदेशक और सचिव डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन (डेयर) के सचिव **डॉ. मांगी लाल जाट** ने देश के कृषि क्षेत्र, शोध और नीतिगत मसलों पर **रूरल वर्ल्ड** के एडिटर-इन-चीफ **हरवीर सिंह** के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह बातें कहीं। पेश है डॉ. जाट के साथ इस इंटरव्यू के मुख्य अंश:

**प्र. कृषि देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ग्रामीण परिवेश से आने के साथ ही आप कृषि शोध क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय संस्थानों में लंबा अनुभव रखते हैं। अब आपको दुनिया के सबसे बड़े कृषि रिसर्च सिस्टम में शुमार होने वाली संस्था आईसीएआर और भारत सरकार के सचिव डेयर की जिम्मेदारी मिली है। आईसीएआर और कृषि शोध को लेकर आपका क्या विजन क्या है?**

कृषि हमारे देश की रीढ़ है। 2047 तक विकसित भारत का सपना बिना विकसित कृषि के साकार नहीं हो सकता। कृषि में अनेक विविधताएं हैं- जमीन की, पानी की, जलवायु की, किसान की। हमें कृषि में शोध और

इनोवेशन उसी हिसाब से करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि एक शोध या इनोवेशन हर जगह काम कर जाए। इसलिए कहा जाता है कि कृषि में सही या गलत कुछ नहीं होता। इसका मंत्र है- मांग के मुताबिक और प्रासंगिक शोध।

एक समय हमारे पास खाना नहीं था। इसलिए हरित क्रांति में हमारा फोकस था उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना। उस समय जो रिसर्च डिजाइन हुई, उनमें उत्पादन पर फोकस था। लेकिन आज की स्थिति अलग है। आज प्रोडक्शन समस्या नहीं, बल्कि ओवर-प्रोडक्शन समस्या है। सरकार के सामने भी समस्या रहती है कि कैसे उसको डिस्पोज करें। किसान को भी औने-पौने दाम पर फसलें बेचनी पड़ती है। हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। पिछले दिनों एक मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि धान ज्यादा पैदा करके उसे बेचने की समस्या है, दूसरी तरफ दलहन और तिलहन हमें आयात करना पड़ रहा है। हम उस दिशा में क्यों जाएं?

हमें रिसर्च या टेक्नोलॉजी टार्गेटिंग की जरूरत है। टार्गेटिंग का मतलब है कि कौन सी चीज कहां जाए जिससे किसान के लिए इकोनॉमिक सेंस बने। वह आर्थिक रूप से कम खर्चीला हो और पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल भी। ऐसा न हो कि धान पैदा करने के लिए 10 साल पानी निकाला और फिर पानी खत्म। हमें शोध की परिस्थिति के हिसाब से डिजाइनिंग करनी पड़ेगी।

परिस्थितियां काफी बदली हैं। इसे हम मेगा ट्रेंड्स बोलते हैं- जलवायु परिवर्तन, भूमि का क्षरण, जैव-विविधता का नुकसान। इन चुनौतियों के समाधान के लिए हमें रिसर्च डिजाइनिंग थोड़ी बदलनी पड़ेगी। लेकिन हम रह गए उत्पादन में, जबकि कृषि उत्पादन अपने आप में समग्र नहीं है। कृषि उत्पादन से पहले और उसके बाद को भी जोड़ना होगा। इसके लिए आजकल समग्र एग्री फूड सिस्टम एप्रोच की बात



फोटो: रूरल वर्ल्ड

की जाने लगी है। जब तक एग्री फूड सिस्टम नहीं लाएंगे, तब तक किसान का मार्केट लिंकेज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी टार्गेटिंग नहीं होगी, उसके बिजनेस मॉडल नहीं होंगे।

**प्र. रिसर्च सिस्टम में किस तरह के बदलाव की जरूरत है?**

जब उत्पादन पर फोकस था, तब हमारे वैज्ञानिक उसी स्किल के थे। अब हमें समग्र एग्री फूड सिस्टम डिजाइन करना है, तो इनके लिए थोड़ी अलग स्किल की जरूरत है। अर्थात् हमें सिस्टम में नई स्किल लाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए एफपीओ की बात करते हैं। केवीके में एफपीओ की ट्रेनिंग दे सकते हैं,



**डॉ. मांगी लाल जाट**  
सचिव डेयर, महानिदेशक,  
आईसीएआर

लेकिन उसका बिजनेस प्लान बनने वाला तो एक्सपर्ट ही चाहिए। ये सब नई चीजें लाने की बात है।

**प्र आपके कहने का मतलब है कि एग्रो इकोनॉमी, रिसर्च, हमारे प्राकृतिक संसाधन और जलवायु परिवर्तन यह सब एक कंप्लीट पैकेज के रूप में आना चाहिए।**

बिल्कुल। यह कमोडिटी केंद्रित न हो क्योंकि इसमें समस्या है। मान लीजिए धान की कोई वैरायटी 150 दिन की है, उसे आपने 155 दिन रहने दिया। उससे धान का उत्पादन तो आपने आधा टन बढ़ा लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उससे अगली फसल में जो देरी हुई, उसमें एक

**आज प्रोडक्शन समस्या नहीं, बल्कि ओवर-प्रोडक्शन समस्या है। सरकार के सामने भी समस्या रहती है कि कैसे उसको डिस्पोज करें। किसान को भी औने-पौने दाम पर फसलें बेचनी पड़ती है। हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा।**

टन का नुकसान तो नहीं कर रहे? हमें देखना होगा कि कौन सी चीज कहां फिट होती है। मान लीजिए किसान के पास 70 दिन की अपॉर्च्युनिटी है। तो 70 दिन के विंडो में क्या फिट कर सकते हैं? 70 दिन वाले विंडो में आप 100 दिन वाली फसल ले आएंगे तो वह फिट नहीं होगा। इसलिए हमें रिडिजाइनिंग पर जाना पड़ेगा।

**प्र कृषि शोध, शिक्षा और एक्सटेंशन में आईसीएआर कैसे काम कर रहा है?**

ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत का एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन सिस्टम बहुत विकसित है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन जैसे-जैसे हम थोड़े आत्मनिर्भर



होते जाते हैं तो साइलो में काम करने लगते हैं। हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें हर इंस्टीट्यूट में, हर जगह, हर तरह की विशेषज्ञता न तो चाहिए, न हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई खास विशेषज्ञता वाला व्यक्ति है और पड़ोस के संस्थान में दूसरी विशेषज्ञता वाला व्यक्ति। दोनों एक-दूसरे के यहां काम कर दें तो उनका पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। पूरे सिस्टम की विशेषज्ञता को हमें एक जगह लाना पड़ेगा।

कृषि स्टेट सब्जेक्ट है। वहां के कृषि विश्वविद्यालयों में कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं। फसलों की किस्में राज्यों में विकसित होती हैं। रिकमेंडेशन राज्यों को जाती हैं। राज्य उन पर अमल करते हैं। हमें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को करीब लाने की जरूरत है। केवीके अलग-अलग बॉडी के अधीन काम कर रहे हैं। कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधीन, कोई एनजीओ के अधीन तो कोई आईसीएआर के अधीन। राज्यों के एक्सटेंशन विभाग भी आइसोलेशन में काम कर रहे हैं।

हम चाहते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक का सिस्टम कड़ी-बद्ध जुड़ा हो। सूचना एकतरफा न जाए, वह दो-तरफा हो ताकि जमीनी स्तर की डिमांड रिसर्च में इंटीग्रेट हो और रिसर्च भी एक्सटेंशन के जरिए किसान तक पहुंचे। इसके लिए हमें एक मजबूत नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम तैयार करना पड़ेगा।

**रिसर्च में दो चीजें आती हैं- साइंस और उसका इकोनॉमिक्स। रिसर्च आम तौर पर संस्थानों के आदर्श फार्म में होती हैं। लेकिन जब वह रिसर्च व्यावहारिक रूप से किसानों के खेत तक जाती है, तो वहां इकोनॉमिक्स अलग होता है। उसको कैसे पारदर्शी बनाया जाए?**

इसका एक सिस्टम है। पहले टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, फिर मल्टी लोकेशन टेस्टिंग होती है, उसके बाद वह एडाप्टिव ट्रायल्स में जाता है। एडाप्टिव ट्रायल किसानों के यहां भी होती है। वैसे, आप देखें तो एक खेत से दूसरे खेत में थोड़ा बहुत अंतर आता ही है। मिट्टी अलग होती है, मैनेजमेंट में अंतर होता है। मान लीजिए दो भाइयों की जमीन अलग-बगल है। दोनों को एक ही वैरायटी दे दी जाए, तो भी उनकी पैदावार में फर्क आएगा। यह मैनेजमेंट में अंतर के कारण होता है।

इसीलिए हमें आज जितनी जरूरत बायोफिजिकल रिसर्च की है - वैरायटी, वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट - उतनी ही जरूरत सामाजिक-आर्थिक रिसर्च की है। हम कहते हैं

कि किसान रिसर्च को अपना रहा है या नहीं अपना रहा है। लेकिन वह क्यों अपना रहा है और क्यों नहीं अपना रहा है? उसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। इसके लिए व्यवहार और विज्ञान को गहराई से समझना पड़ेगा। यह व्यवहार की समस्या है। कृषि में बहुत सारी चीजें सीधी-सपाट नहीं होती हैं।

**इसके लिए क्या आईसीएआर सिस्टम में सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज या लिबरल साइंस जैसे विषयों पर फोकस बढ़ाया जाएगा?**

बिल्कुल बढ़ाएंगे। लेकिन यह रातों-रात नहीं होगा। सोशल साइंस को मजबूत करने पर हमारा फोकस है। बायोफिजिकल साइंटिस्ट जो करते हैं, उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। उसमें बाकी चीजें भी आती हैं। अभी हम टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात कर रहे थे। हमने देखा कि औसत उत्पादकता और किसान के खेत में उत्पादकता में बहुत अंतर है। इसका मतलब है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसको अपनाने में दिक्कतें हैं। वे दिक्कतें क्या हैं। हमें उत्पादकता गैप के कारणों का पता लगाना पड़ेगा। उन कारणों में 50% से ज्यादा तो नॉलेज गैप है। इसका मतलब है कि नॉलेज पहुंचाना है। कृषि विज्ञान केंद्र नॉलेज गैप को दूर करने का माध्यम हैं।

**नई टेक्नोलॉजी में एक जीएम टेक्नोलॉजी भी है। जीएम की हमारे पास काफी रिसर्च है। आईसीएआर सिस्टम में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। इसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा?**

हमारा फोकस विज्ञान आधारित कृषि बदलाव पर है। साइंस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। आगे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए विज्ञान की जरूरत है। कुछ खास टेक्नोलॉजी हैं, उनकी एक प्रक्रिया है, सरकार का रेगुलेटरी मेकैनिज्म है। खास तौर से आप जिस जीएम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वह मामला अभी कोर्ट में है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि विज्ञान को आगे रखा जाना चाहिए। विज्ञान की अगुवाई में ही बदलाव पर फोकस होना चाहिए।

**इन दिनों इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर फोकस बढ़ रहा है। कृषि में भी। कहा जा रहा है कि इससे क्रांति आएगी, बड़ा बदलाव होगा। आईसीएआर में भी इस पर कई प्रोजेक्ट हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं?**

देखिए, हमें टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ

चलना होगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ फैंसी वर्ड नहीं होना चाहिए। उस टेक्नोलॉजी का धरातल पर भी इस्तेमाल हो। अभी हम एआई या आईओटी की जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे डाटा है। जब तक क्वालिटी डाटा, ऑर्गेनाइज्ड डाटा और इंटर ऑपरेबल डाटा दुरुस्त नहीं होगा तब तक खास सफलता नहीं मिलेगी। एआई उसी डाटा पर आधारित होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेचुरल इंटेलिजेंस का समावेश ठीक नहीं होगा। सिर्फ एआई से भी काम नहीं चलेगा। एक बेहतर सम्मिश्रण की जरूरत है। उसके लिए हमें एक मजबूत डाटा इकोसिस्टम डेवलप करना है।

हमारे पास पचासों साल का डाटा है। अभी मिनिस्ट्री डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रही है। हर खेत को जोड़ना, उसकी मैपिंग करना। कृषि ऐसा सेक्टर है जिसमें डाटा 7-8 मंत्रालयों पर निर्भर करता है। अगर हमें फर्टिलाइजर या पानी का डाटा नहीं मिलेगा तो इसे कैसे कर





सकते हैं? जब वह सारा डाटा इकोसिस्टम डेवलप होगा तभी दुरुस्त एआई बनेगा। छोटे काम भले ही हो जाएं, लेकिन आप जिस बड़ी तस्वीर की बात करते हैं उसके लिए क्वालिटी डाटा चाहिए।

**प्र** एक्सटेंशन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन माना जाता है कि हमारा एक्सटेंशन बेहतर स्थिति में नहीं है। आपने यील्ड गैप या व्यवहार की बात कही, उसमें भी एक्सटेंशन का इस्तेमाल हो सकता है। इसको आप किस तरह देखते हैं?

एक्सटेंशन बहुत जरूरी है। पुराने एक्सटेंशन सिस्टम को देखें से तुलना करें अब का एक्सटेंशन का काम बहुत कठिन हो गया है। अब डिजिटल एक्सटेंशन की बात होती है, उसके लिए स्किल चाहिए। स्किल नहीं होगी तो व्यक्ति डिलीवर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम साइंस ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं।

हमें हर इंस्टीट्यूट में, हर जगह, हर तरह की विशेषज्ञता न तो चाहिए, न हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई खास विशेषज्ञता वाला व्यक्ति है और पड़ोस के संस्थान में दूसरी विशेषज्ञता वाला व्यक्ति। दोनों एक-दूसरे के यहां काम कर दें तो उनका पूरा इस्तेमाल हो जाएगा।

फोटो: रुरल वर्ल्ड



हमें साइंस ऑफ डिस्कवरी को साइंस ऑफ डिलीवरी से जोड़ना पड़ेगा। दोनों अलग काम करेंगे तो समस्या होगी।

एक्सटेंशन सिर्फ एक्सटेंशन नहीं है। यह एक विज्ञान है। यह साइंस ऑफ डिलीवरी है और इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस मॉडल, वह कैसे काम करेगा। अगर टेक्नोलॉजी से बिजनेस बढ़ता है तो डिलीवरी होगी, अगर बिजनेस नहीं बढ़ता तो डिलीवरी नहीं होगी। हम 70 साल से एक लीनियर एक्सटेंशन सिस्टम पर चल रहे हैं। हमें लीनियर और नॉन लीनियर एक्सटेंशन सिस्टम का मिश्रण चाहिए। इसलिए एक्सटेंशन में एक नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर का भी एक एक्सटेंशन नेटवर्क है। हम यह सोच रहे हैं कि वह सरकारी और निजी दोनों एक्सटेंशन सिस्टम में कन्वर्जेंस लाना पड़ेगा। अगर दोनों अलग दिशा में चलेंगे तो किसानों को नुकसान होगा। इस कन्वर्जेंस के लिए हम लोग जुटे हुए हैं।

**प्र** कृषि निर्यात में हम 50 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। निर्यातनुमुखी उत्पाद, उनकी क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड को लेकर आईसीएआर का क्या फोकस रहेगा?

हमारा निर्यात क्वालिटी के कारण ही हो रहा है। चाहे बासमती लें या दूसरी फसलें। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि देश क्या निर्यात करना अफोर्ड कर सकता है और क्या नहीं। जैसे, हम कम पानी वाले इलाके में धान पैदा करके निर्यात करें और बाद में दलहन और तिलहन आयात करें, तो वह ठीक नहीं होगा। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमें सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। भारत और भारत का किसान, जो चीजें इनकी मदद करेंगी हम उसी दिशा में काम करेंगे।

**प्र** युवाओं को कृषि में वापस लाना है। इसमें फार्म मैकेनाइजेशन की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि फार्म मैकेनाइजेशन डिग्रेडिटी से भी जुड़ा है।

हम हमेशा एफिशिएंसी की बात करते हैं, पानी की एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी, अन्य चीजों की एफिशिएंसी। लेकिन हम टाइम एफिशिएंसी को भूल जाते हैं। खेती में यह सबसे महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसे समय में जब हम जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। बिना मैकेनाइजेशन के हम टाइम एफिशिएंसी को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। **Rw**

## इफको की आंवला व फूलपुर इकाइयों में नैनो डीएपी का उत्पादन शुरू

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) ने उत्तर प्रदेश की आंवला (बरेली) और फूलपुर (प्रयागराज) इकाइयों में नैनो डीएपी लिक्विड का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस उपलब्धि पर इफको के प्रबंध निदेशक और सीईओ डॉ. यू.एस. अवस्थी ने कहा, “किसानों से नैनो डीएपी लिक्विड को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद इफको की आंवला और फूलपुर इकाइयों में इसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। दोनों इकाइयों की उत्पादन क्षमता 2-2 लाख बोतल प्रतिदिन है, जो देश में नैनो डीएपी की आपूर्ति को

बढ़ावा देगा।” इन दो संयंत्रों के जुड़ने के साथ ही, इफको अब देश भर में पांच नैनो खाद संयंत्रों का संचालन कर रहा है। इसके साथ ही नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की कुल दैनिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 9.5 लाख बोतल प्रतिदिन हो गई है। यह पहल देश भर के किसानों को नैनो खाद उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नैनो डीएपी लिक्विड को पारंपरिक डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का एक

अच्छा विकल्प माना जा रहा है। 100 नैनोमीटर से छोटे कणों से निर्मित यह खाद पौधों को पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण सुनिश्चित करता है, मिट्टी की सेहत सुधारता है, और फसलों की वृद्धि व उपज को बढ़ावा देता है। गौरतलब है कि इफको पहले ही नैनो यूरिया के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा चुका है। अब नैनो डीएपी के उत्पादन का विस्तार भारत को सतत और आत्मनिर्भर कृषि की ओर ले जाने में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।



## 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून

इस बार मानसून 8 दिन पहले ही केरल पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार, यह 2009 के बाद भारत में मानसून का सबसे जल्दी आगमन है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। लेकिन इस बार मानसून ने जल्द दस्तक दे दी।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के जल्दी या देर से केरल पहुंचने का पूरे मानसून सीजन के दौरान कुल वर्षा पर कोई सीधा प्रभाव नहीं होता है। मानसून की प्रगति कई वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय कारकों पर निर्भर करती है। केरल में मानसून के जल्दी पहुंचने का मतलब यह नहीं कि बाकी हिस्सों में भी ऐसा ही होगा।

मौसम विभाग ने अप्रैल में जारी अपने पूर्वानुमान में बताया था कि इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।

## गेहूं की सरकारी खरीद 300 लाख टन

चालू रबी विपणन सीजन (2025-26) के दौरान देश में गेहूं की सरकारी खरीद 300 लाख टन रह सकती है। यह पिछले वर्ष की 266 लाख टन की खरीद से लगभग 13% अधिक है। हालांकि, सरकार ने इस वर्ष के लिए 332 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इस साल सबसे अधिक 119 लाख टन गेहूं पंजाब से खरीदा गया है। मध्य प्रदेश 78 लाख टन और हरियाणा 75 लाख टन खरीद के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। राजस्थान में 18.55 लाख टन की खरीद हुई है।

देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में अब तक 10.20 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जबकि राज्य के लिए 30 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था।







## सीबीजी का खरीद मूल्य बढ़ा

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) का खरीद मूल्य 1380 रुपये प्रति एमएमबीटीयू से बढ़ाकर 1478 रुपये प्रति एमएमबीटीयू कर दिया है। नई दर 1 जून से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगी। इस संशोधन से वजन आधारित सीबीजी का खरीद मूल्य 72.8 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 77.4 रुपये प्रति किलो हो गया है। इसके अलावा, 50-75 किमी की दूरी के लिए 1.5 रुपये/किलो और 75 किमी से अधिक की दूरी के लिए 2.5 रुपये/किलो की अतिरिक्त परिवहन सहायता भी दी जाएगी।

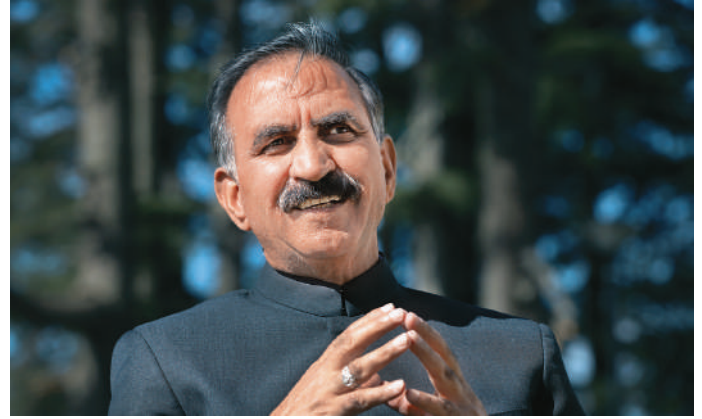
इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी के सीबीजी प्रोड्यूसर फोरम ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परियोजनाओं की व्यावसायिक संभावनाएं, कैश फ्लो और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

## डेयरी क्षेत्र के लिए बनेंगी 3 सहकारी समितियां

केंद्र सरकार सहकारी डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए तीन नई बहु-राज्य सहकारी समितियां स्थापित करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में "सस्टेनेबिलिटी और सकार्युलैरिटी" विषय पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया।

प्रस्तावित समितियों में पहली समिति पशु आहार उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान और रोग नियंत्रण पर कार्य करेगी। दूसरी समिति गोबर प्रबंधन के लिए प्रभावी मॉडल विकसित करेगी, जबकि तीसरी समिति मृत मवेशियों के अवशेषों के सर्कुलर उपयोग को बढ़ावा देगी।

अमित शाह ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत सहकारी नेटवर्क का निर्माण आवश्यक है। जो कार्य वर्तमान में निजी क्षेत्र कर रहा है, उन्हें अब किसान अपनी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करेंगे।



## हिमाचल में प्राकृतिक खेती के गेहूं की 60 रुपये प्रति किलो पर खरीद

हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों - जैसे गेहूं, मक्का और हल्दी - की किसानों से बेहतर मूल्य पर खरीद की जा रही है। इसके लिए इच्छुक किसान 15 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं।

प्राकृतिक खेती से उपजे गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। मक्का का एमएसपी 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो और कच्ची हल्दी का एमएसपी 90 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। चंबा के पांगी ब्लॉक में पैदा होने वाली जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलो का एमएसपी निर्धारित किया गया है।



## उत्तर प्रदेश में बनेंगे 5 सीड पार्क

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पांच सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये पार्क पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होंगे और प्रदेश के पांच कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार बीज उद्योगों को सीड पार्कों में निवेश के लिए 30 वर्षों की लीज पर भूमि उपलब्ध कराएगी, जिससे सीड पार्कों में बीज उत्पादन, भंडारण, प्रयोगशाला तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। यह लीज 90 वर्षों तक बढ़ाई जा सकेगी।

पहला सीड पार्क लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की 130.63 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 266.70 करोड़ रुपये होगी।



## ट्रेकिंग रूट

**तुंगनाथ ट्रेक:** सारी से तुंगनाथ ट्रेक की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। यह ट्रेक आपको तुंगनाथ मंदिर तक ले जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है।

**चोपता ट्रेक:** सारी गांव से चोपता ट्रेक की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। यह ट्रेक आपको चोपता घाटी तक ले जाता है, जो इन दिनों लाल बुरांश से सजा हुआ है।

**देवरिया ताल ट्रेक:** सारी गांव से ही देवरिया ताल ट्रेक भी शुरू होता है, जिसकी दूरी करीब पांच किमी है।

## ऐसा है सारी गांव

191	1200	50	250
परिवार हैं	आबादी है	होम स्टे	लोगों को मिला
सारी गांव में	गांव की	संचालित हो रहे	है रोजगार

# रुरल होम स्टे से बदल रहा पर्यटन लैंडस्केप

अनेक गांवों में महिलाएं कर रही होम स्टे का संचालन

## संजीव कंडवाल, देहरादून

उत्तराखंड में पर्यटन अब तक मुख्य तौर पर नैनीताल, मसूरी जैसे शहरों तक ही सीमित रहा है। लेकिन अब शहरों की चकाचौंध से दूर, गांवों में अच्छे होम स्टे उपलब्ध होने से पर्यटक दूर-दराज के गांवों में भी पहुंच रहे हैं। इससे उत्तराखंड के टूरिज्म लैंडस्केप में अहम बदलाव आ रहा है।

## उत्तरकाशी का मथोली गांव बना महिला सशक्तीकरण की मिसाल

उत्तरकाशी जनपद में पर्यटकों का रुख आमतौर पर हर्षिल वैली या मोरी-सांकरी की तरफ होता है। लेकिन चिन्वालीसौढ़ ब्लॉक के मथोली गांव की महिलाओं ने गांव को पर्यटकों का नया ठिकाना बना दिया है। यहां होम स्टे संचालन से लेकर विलेज टूर तक महिलाएं ही संचालित करती हैं।

मथोली को पर्यटन गांव के रूप में बदलने का

श्रेय जाता है स्थानीय युवक प्रदीप पंवार को। प्रदीप को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गांव लौटना पड़ा। सौभाग्य से उनके पास पर्यटन क्षेत्र में काम करने का अनुभव था। उन्होंने गांव के पास मौजूद अपनी छानी (गौशाला) को होम स्टे में बदल कर, उसे पर्यटकों के लिए खोल दिया। गांव की महिलाओं को होम स्टे संचालन का प्रशिक्षण दिया। गांव की ब्रांडिंग 'ब्बारी विलेज' के तौर पर की।

स्थानीय महिला अनीता पंवार बताती हैं कि गांव में अब अन्य महिलाएं भी अपनी छानियों को होम स्टे में परिवर्तित करने के लिए आगे आई हैं। प्रदीप बताते हैं कि उन्होंने अपने होम स्टे को पर्यटन विभाग में पंजीकृत करवा दिया है, जिससे वे ऑनलाइन बुकिंग भी ले सकते हैं। उन्होंने 8 मार्च 2022 को अपने होम स्टे की शुरुआत की थी। तब से करीब एक हजार पर्यटक आ चुके हैं।


## रुद्रप्रयाग के सारी गांव में 50 होम स्टे

रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ, चोपता ट्रेक पर

मौजूद सारी गांव उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन और स्वरोजगार की मिसाल कायम कर रहा है। गांव में इस वक्त करीब 50 होम स्टे संचालित हो रहे हैं, जिसमें ढाई सौ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।

सारी गांव में होम स्टे की शुरुआत 1999 में माउंटेन गाइड मुरली सिंह नेगी ने की। यहां वर्ष भर पर्यटकों की आवाजाही रहती है, इसलिए अन्य लोगों ने भी अपने परम्परागत घरों के दरवाजे पर्यटकों के लिए खोल दिए। वर्तमान में यहां होम स्टे की संख्या 50 तक पहुंच गई है, जिसमें से 41 पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत हैं। कई लोगों ने प्रदेश सरकार की दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन होम स्टे योजना के तहत भी होम स्टे शुरू किए हैं। स्थानीय ग्रामीण जीएस भट्ट बताते हैं कि गत वर्ष गांव में करीब सात हजार पर्यटक आए।

**मुख्यमंत्री धामी ने भी किया विश्राम:** दिसंबर में रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सारी गांव पहुंच कर होम स्टे में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांव में पर्यटन और स्वरोजगार के मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। रुद्रप्रयाग से सारी गांव की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है।

पर्यटन विभाग के पास इस समय 5331 होम स्टे पंजीकृत हैं, जिनमें से ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ही संचालित करती हैं। सरकार पंडित दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत होम स्टे की लागत पर मैदानी क्षेत्र में 25% और पहाड़ी क्षेत्र में 33% सब्सिडी देती है। 





# National Federation of Farmers' Procurement, Processing & Retailing Cooperatives of India Ltd.

Registered under the Multi State Cooperatives Societies Act, 2002 Department  
of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture. Government of India



The commercial operations of the NACOF are undertaken on all India levels through its Head Office in New Delhi and Branches / Sub-Branche s functioning in the State Capitals and other important cities / procuring centers. In the financial year, 2025-25 NACOF achieved a turnover of more than Rs.5000 Crores.

scan to join us



National Fed. of Farmers PP&R COOP OF INDIA LTD  
112-A, Devika Tower , Nehru Place, Nehru Place, New Delhi



# Empowering Rural India:

Join NCEL and be a part of  
transformative action through  
cooperative export opportunities

Reached global markets in **28 countries**  
Whopping **turnover of ₹5,396 Cr** in just 2 years  
**10,000+** cooperative societies onboarded as members



## Sahkar se Samriddhi

## Niryat se Unnati

Scan to join us:

